चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

मिस से सबक़ ले सरकार

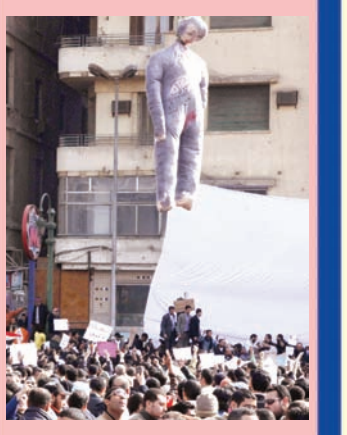

पेज-3

ममता जी, आपका एक्शन प्लान क्या है

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

विश्व कप 2011

पेज-15

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 21 फरवरी-27 फरवरी 2011 | मूल्य 5 रुपये

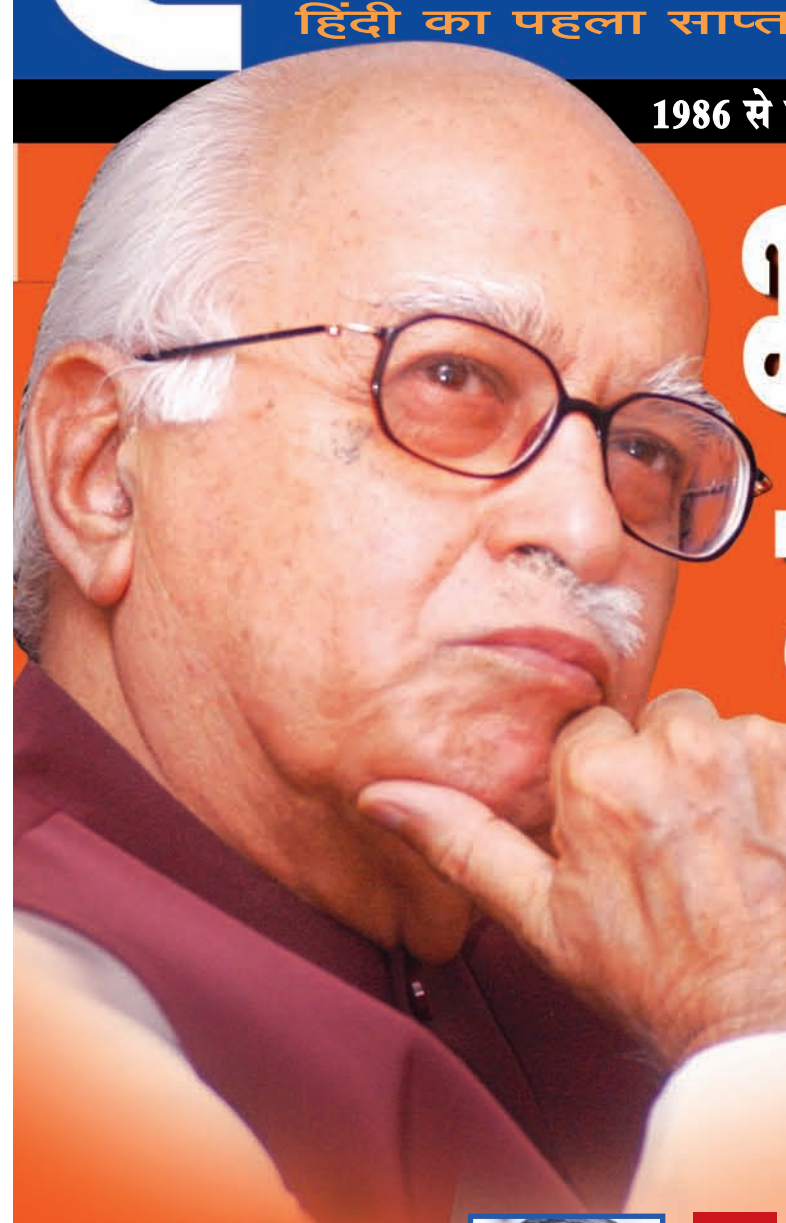

भाजपा में गृहयुद्ध

देश के मुख्य विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने के हालात चिंताजनक हैं. वरिष्ठ नेताओं के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा ने पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है. नतीजतन, पार्टी आम आदमी और उसकी समस्याओं से लगातार दूर होती जा रही है. अगर यह स्थिति बरक़रार रही तो वह दिन दूर नहीं, जबकि सरकार के साथ-साथ उसे भी जनता की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है.

मनीष कुमार

महाभारत की लड़ाई में कौरवों के साथ ज़्यादा बड़े-बड़े योद्धा थे, फिर भी वे युद्ध हार गए. वजह यह थी कि कौरवों की सेना में सेनापति से लेकर कई बड़े-बड़े महारथी तो थे, लेकिन उनमें एकता नहीं थी. युद्ध के दौरान बड़े-बड़े योद्धा एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे. भीष्म, कर्ण एवं द्रोणाचार्य जैसे महारथी युद्ध नहीं जीतना चाहते थे. वे तो सिर्फ़ राजधर्म का पालन कर रहे थे. दूसरी ओर पांडवों की सेना थी. उनके पास योद्धाओं और सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन वे जीतना चाहते थे. इसलिए पांडव युद्ध जीत गए. भारतीय जनता पार्टी की हालत कौरवों जैसी हो गई है.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की फौज में अघोषित गृहयुद्ध चल रहा है. हर नेता दूसरे नेता को पीछे छोड़कर अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहता है. दिल्ली में रहकर मीडिया में बयान देने वाले नेताओं के बीच शीतयुद्ध चल रहा है. पार्टी में हाशिए पर गए जनाधार वाले नेता लड़ रहे हैं. जो लोग पार्टी से बाहर गए हैं, वे गुटबंदी में शामिल हो रहे हैं. कुछ नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर अपने हिसाब से इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं. भारतीय जनता पार्टी में चल रहे गृहयुद्ध का सबसे बड़ा नुक़सान देश की जनता का हो रहा है. देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोज़गारी है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खानापूर्ति के लिए संसद में हंगामा कर रही है. जनता की परेशानी के लिए सरकार के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी भी ज़िम्मेदार है. जनता परेशान और नाराज़ है, लेकिन विपक्ष कोई असरदार आंदोलन करने में असफल रहा है. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी अपनी ही उलझन में उलझ गई है. अफसोस की बात यह है कि सब कुछ आडवाणी जी के रहते हो रहा है.

संसद में एक अजीबोग़रीब घटना घटी. बात मानसून सत्र की है. एजूकेशनल ट्रिब्यूनल बिल को कपिल सिब्बल ने पेश किया. यह बिल लोकसभा में पास कर दिया गया. लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज हैं. भारतीय जनता पार्टी का किसी भी मुद्दे पर क्या रुख़ होगा, इस बारे में फ़ैसला वही करती हैं. लेकिन जब यही बिल राज्यसभा में आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध कर दिया. राज्यसभा में अरुण जेटली विपक्ष के नेता हैं. एक बिल, एक पार्टी और दो अलग-अलग सदनों में अलग-अलग रुख़. इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बिल के ऊपर कोई बहस नहीं हुई. पार्टी का इस बिल पर क्या रुख़ हो, इस पर कोई एकमत नहीं हुआ. इसके अलावा इस घटना से एक बात जगज़ाहिर होती है कि पार्टी के नेताओं में एकमत नहीं है. इस घटना से अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के बीच चल रहा शीत युद्ध सार्वजनिक हो गया. अब सवाल यह है कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज क्यों लड़ रहे हैं.

किसी भी राजनीतिक दल में नेताओं के बीच प्रतियोगिता होना अच्छी बात होती है. यह प्रतियोगिता सकारात्मक हो तो पार्टी के लिए बेहतर है. इससे दल मज़बूत होता है. लेकिन अगर यह प्रतियोगिता नकारात्मक हो जाए, आगे बढ़ने के बजाय एक नेता दूसरे नेता की टांग खींचने लगे, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ साजिश करने लगे तो पार्टी के लिए सबसे ख़तरनाक स्थिति पैदा हो जाती है. चुनाव जीतना तो दूर, पार्टी के अस्तित्व पर ख़तरा मंडराने लगता है. अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए पार्टी में अभी से युद्ध शुरू हो गया है. इस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, जो आडवाणी की जगह लेना चाहते हैं. वे अगले चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते हैं. इन नेताओं में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी और नितिन गडकरी हैं. आडवाणी के उत्तराधिकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं में घमासान हो रहा है. ऐसा मालूम पड़ता है कि इन नेताओं के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है, उसके सूत्रधार ख़ुद लालकृष्ण आडवाणी हैं.

अटल जी स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं. आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं. आडवाणी जी देश के सबसे अनुभवी नेता हैं. राजनीति में ख़ुद को कैसे प्रासंगिक बनाए रखना है, यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है. ऐसा लगता है कि कोई उनकी लीडरशिप को चैलेंज न कर सके, इसलिए उन्होंने पार्टी में शेफ्टी वॉल्व तैयार कर रखा है. इस शेफ्टी वॉल्व में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार एवं रविशंकर प्रसाद जैसे कई नेता हैं. आडवाणी जी ने पार्टी में इन नेताओं की साख बढ़ाई, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए इनके बीच का कोई नेता आगे नहीं बढ़ सका. इनके लड़ने से लालकृष्ण आडवाणी का प्रभुत्व बरक़रार रहा. उन्होंने ही सुषमा स्वराज को लोकसभा और अरुण जेटली को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया. बाक़ी लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियां दीं. आडवाणी के नज़दीक जितने नेता हैं, उनकी ख़ासियत है कि वे मीडिया के ज़रिए राजनीति करने में माहिर हैं. यह सबको मालूम है कि जिन लोगों के कंधों पर आडवाणी जी ने पार्टी की ज़िम्मेदारियां दी हैं, उन्हें अगर अकेले चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो वे एक भी चुनाव नहीं जीत सकते. ये नेता पार्टी के कर्ताधर्ता तो बन गए, लेकिन इनके पास जनाधार नहीं है. भारतीय जनता पार्टी की दिशाहीनता की वजह यही है कि पार्टी में जो डिसिज़न मेकर हैं, उनकी साख जनता में नहीं है. उन नेताओं ने सबसे पहले ग्रासरूट लेवल और जनाधार वाले नेताओं को दरकिनार किया. इसमें वे सफल भी हो गए.

सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. ऐसा लगता है कि आडवाणी जी की यह रणनीति है कि जो भी जनाधार वाले नेता हैं, उन्हें राज्यों में भेज दिया जाए, उन्हें पार्टी में कोई भी निर्णायक भूमिका न दी जाए. राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास मज़बूत नेता हैं. नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, सुशील मोदी, येदुरप्पा और वसुंधरा राजे सिंधिया का अपने-अपने राज्यों में जनाधार है. वे काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन पार्टी में उनकी हैसियत नहीं है. आडवाणी जी के आशीर्वाद से दिल्ली मुख्यालय में उन नेताओं का क़ब्ज़ा है, जिनके पास जनाधार नहीं है. ऐसे में जनाधार वाले नेता पार्टी से विमुख होते जा रहे हैं. इस तरह पार्टी में गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई. एक तरफ़ बिना जनाधार वाले नेता आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ़ जनाधार वाले नेता दिल्ली के मुख्यालय में बैठे नेताओं से नाराज़ हैं. इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का काफी नुक़सान हो रहा है, लेकिन आडवाणी जी को यह लगता है कि अगर मध्यावधि चुनाव हो जाएं तो वह फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बन सकते हैं.

भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आडवाणी जी के इस खेल को भलीभांति समझते हैं. अब तो जनाधार वाले नेताओं ने आडवाणी जी की बातों को टालना भी शुरू कर दिया है. चंदन मित्रा एक पत्रकार हैं और राज्यसभा सांसद हैं. आडवाणी जी के बेहद क़रीबी हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में वह आडवाणी जी के निकटतम रणनीतिकारों में से थे. अब उनका टर्म पूरा होने वाला है. ऐसी ख़बर आई कि आडवाणी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह संदेश दिया कि चंदन मित्रा को राज्यसभा में आने में मदद कर दीजिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मना कर दिया. उन्होंने यह कहा कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बीस से चालीस साल तक पार्टी में काम किया है, उन्हें राज्यसभा में जगह देना ज़रूरी है. इससे यह समझा जा सकता है कि पार्टी के अंदर तनाव का माहौल है और वह इस कगार पर आ गया है कि आडवाणी जी की बात को भी राज्यस्तरीय नेताओं ने मना करना शुरू कर दिया है.

उत्तराधिकार की इस लड़ाई में एक अहम किरदार हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दिल्ली मुख्यालय में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं. गुजरात में अपनी लोकप्रियता और चुनाव जीतने की क्षमता की वजह से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं. अरुण जेटली मोदी के दोस्त हैं, उनके केस लड़ते हैं और जब भी गुजरात दंगों के बारे में बात उठती है तो जेटली साहब ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मीडिया में उनका बचाव करते हैं. लेकिन जेटली के अलावा उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें पसंद नहीं करते हैं. एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियों के बीच भी मोदी को लेकर विवाद है. गृहयुद्ध का ही नतीजा है कि बिहार चुनाव के दौरान एक बार सुषमा स्वराज ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात में ही चलता है. इस बात को लेकर मोदी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी से भी शिक़ायत की थी. सुषमा स्वराज के इस बयान का जवाब मोदी ने अख़बार में छपे एक विज्ञापन से दिया.

कर्नाटक के एक समर्थक ने अख़बार में एक बड़ा सा विज्ञापन छापा. उसमें लिखा था, मोदी भाजपा के सबसे ज़्यादा भीड़ जमा करने वाले नेता हैं. मतलब यह कि वह सबसे ज़्यादा जनाधार वाले नेता हैं. विज्ञापन में कहा गया कि गुजरात

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आडवाणी जी के इस खेल को भलीभांति समझते हैं. अब तो जनाधार वाले नेताओं ने आडवाणी जी की बातों को टालना भी शुरू कर दिया है. चंदन मित्रा एक पत्रकार हैं और राज्यसभा सांसद हैं. आडवाणी जी के बेहद क़रीबी हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में वह आडवाणी जी के निकटतम रणनीतिकारों में से थे. अब उनका टर्म पूरा होने वाला है. ऐसी ख़बर आई कि आडवाणी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह संदेश दिया कि चंदन मित्रा को राज्यसभा में आने में मदद कर दीजिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मना कर दिया. उन्होंने यह कहा कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बीस से चालीस साल तक पार्टी में काम किया है, उन्हें राज्यसभा में जगह देना ज़रूरी है.

पीएमओ ने कहा कि बैंक प्रमुख का चुनाव करते वक्त उम्मीदवार की प्रतिभा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि किन्हीं अन्य बातों पर.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

पीएमओ ने मांगी सफ़ाई

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब और सिंध बैंक के नए मुखिया की नियुक्ति पर वित्त मंत्रालय की पसंद पर सवाल उठाए हैं. इस बैंक का मुखिया पारंपरिक रूप से एक सिख को बनाया जाता रहा है. जब जी एस बेदी का नाम इस बैंक के चेयरमैन पद के लिए चुना गया, तब पीएमओ ने कहा कि बैंक प्रमुख का चुनाव करते वक़्त उम्मीदवार की प्रतिभा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि किन्हीं अन्य बातों पर. इस वजह से पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे डी एस बैंस को पीएमओ का समर्थन नहीं मिला. बैंस अभी पंजाब के वित्त आयुक्त हैं. वित्त मंत्रालय ने उनका नाम इस पद के लिए सुझाया था, लेकिन पीएमओ से इस नाम पर मुहर न लगने की हालत में नियुक्ति का मामला लटक गया है. साथ ही पीएमओ ने वित्त मंत्रालय से इस मुद्दे पर सफ़ाई भी मांगी है.

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ युद्ध

भ्रष्ट नौकरशाही के ख़िलाफ़ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभियान ज़ोर पकड़ रहा है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि उनका यह अभियान सफल होगा. इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि यह अभियान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं, जिन पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है. मसलन, राज्य विजिलेंस ब्यूरो, स्पेशल विजिलेंस यूनिट और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विजिलेंस विभाग में ऐसे मुख्य पद, जो भ्रष्टाचार की जांच के लिए उत्तरदायी हैं, रिक्त पड़े हुए हैं. रिक्त पदों में सबसे महत्वपूर्ण है बिहार विजिलेंस ब्यूरो में अतिरिक्त महानिदेशक का पद. अनिल सिन्हा की केंद्र में तैनाती के बाद से ही यह पद रिक्त है. फिलहाल एडीजी रैंक के अधिकारी अभयानंद और सुनीत कुमार संयुक्त रूप से इस पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इस बीच स्पेशल विजिलेंस यूनिट, जिसने पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा और आईएएस अधिकारी एस एस वर्मा के यहां छापे मारकर सुर्खियां बटोरी थीं, भी स्टाफ की कमी से परेशान है.

बाबुओं की सावधान मुद्रा

2 जी मामले में ए राजा के साथ पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा की गिरफ्तारी से दूरसंचार के बाबू सजग हो गए हैं, साथ ही उनकी चिंता भी बढ़ रही है. बेहुरा ने उन फाइलों पर दस्तख़त किए थे, जिनसे 122 लाइसेंस आवंटित हुए थे. दूरसंचार के बाबुओं को यह डर सता रहा है कि कहीं बेहुरा ने सीबीआई के सामने कुछ खुलासे किए तो संभव है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. हो सकता है कि उसमें दूरसंचार के भी कुछ बाबू शामिल हों. अब वे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बेहुरा अपने बचाव में क्या करेंगे. इस सब का असर यह दिख रहा है कि बेहुरा और आर के चंदोलिया की गिरफ्तारी के बाद से अब दूरसंचार के बाबू किसी भी संवेदनशील फाइल को निपटाने में अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं.

dilipcherian@gmail.com

डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी

नवाज़िश मेहदी

चौथी दुनिया ने अपनी परंपरा के अनुरूप साल में एक बार उस शख्सियत को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिसने लोकतंत्र की साख बचाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पहला सम्मान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी को देकर चौथी दुनिया ने पत्रकारिता के इतिहास में एक नई परंपरा शुरू की है. एस वाई कुरैशी ने जिस तरह बिहार के चुनाव संपन्न कराए, वे इस बात का प्रमाण हैं कि यदि शीर्ष पर बैठा आदमी ईमानदार और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हो तो संस्था काम करती है. बिहार के विधानसभा चुनावों में जहां जनता ने निर्भीक होकर वोट डाले, वहीं उसने उन नेताओं को नकार दिया, जिन्होंने पिछले पांच सालों में ईमानदार विपक्ष का रोल नहीं निभाया था. उन्हें जनता ने पुन: अगले पांच साल के लिए विपक्ष का जनादेश दिया. इस फ़ैसले के पीछे एक बड़ा कारण एस वाई कुरैशी का मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहना है. एस वाई कुरैशी ईमानदार भी हैं. आज राजनीति और प्रशासन में ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं, जिनके दामन पर कोई दाग़ न हो. कुरैशी साहब का नाम देश के पहले दस नामों में लिया जाता है. यह अलग बात है कि बाक़ी नौ नामों पर विवाद भले हों, पर पहले नाम पर कोई विवाद नहीं है.

आगरा में बीती पांच फरवरी को चौथी दुनिया के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर श्री कुरैशी को चौथी दुनिया की ओर से प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी के ख़िताब से सम्मानित किया. जब यह सम्मान श्री कुरैशी को दिया जा रहा था तो आगरा के प्रबुद्ध लोगों ने करतल ध्वनि से इसका स्वागत और समर्थन किया.

मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को सम्मानित करते हुए संतोष भारतीय.

भूपेंद्र-मिताली को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री कुरैशी एवं संतोष भारतीय.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश संस्करण का लोकार्पण करते हुए संतोष भारतीय एवं श्री कुरैशी

श्री एस वाई कुरैशी ने इस अवसर पर कहा कि चौथी दुनिया ने उनके सिर पर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि वह जिस लगन और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, शायद अब उन्हें उससे ज़्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा. उन्होंने संकोच के साथ सम्मान ग्रहण करते हुए कहा कि उनके लिए एक वोट का भी महत्व है. इसीलिए चुनाव आयोग एक वोट वाले बूथ को भी उतनी ही तवज्जो देता है, जितनी तीन हज़ार वोट वाले बूथ को. उन्होंने बताया कि राजस्थान में सी पी जोशी सिर्फ़ एक वोट से हारे थे. उन्होंने सी पी जोशी के कहने से कई बार गिनती कराई, लेकिन फ़ैसला आख़िर में वही रहा. उन्होंने बताया कि देश में कई ऐसे बूथ हैं, जहां मात्र तीस-पैंतीस वोटर हैं और जहां छह-सात दिनों की पैदल यात्रा करके ही पहुंचा जा सकता है.

उन्होंने चौथी दुनिया को धर्मनिरपेक्ष और मानवीय पत्रकारिता का सिंबल बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग और मीडिया लोकतंत्र के दो अहम संरक्षक हैं. अगर ये दोनों जाग्रत न हों या धर्मनिरपेक्षता और ईमानदारी से काम न करें तो लोकतंत्र को दफन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता. जिन देशों में सजग व ईमानदार मीडिया और पारदर्शी चुनाव आयोग नहीं है, वहां या तो लोकतंत्र है ही नहीं या बहुत कमज़ोर है. उन्होंने कहा कि देश में शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराना हमारा पहला दायित्व है और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे. उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर छींटाकशी करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि उनसे जैसा काम लिया जाता है, वे वैसा ही करते हैं. अगर बाबुओं से सकारात्मक काम लिया जाता है तो वे तब भी मेहनत करते हैं और नकारात्मक काम लिया जाता है, तब भी मेहनत करते हैं. उन्होंने मीडिया और चुनाव आयोग को लोकतंत्र की सुरक्षा के दो मज़बूत हाथ क़रार दिया और कहा कि जब तक ये हाथ सलामत हैं, तब तक भारत से लोकतंत्र को कोई ख़त्म नहीं कर सकता. उन्होंने चौथी दुनिया को वर्तमान काल में सकारात्मक परिवर्तन का योद्धा क़रार दिया और संतोष भारतीय को इसके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी.

प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने कहा कि कुरैशी साहब ने कार्यक्रम में शिरकत करके हमारी जो इज्जत बढ़ाई है, उसके लिए हम उनके बेहद आभारी हैं. हम मुख्य अतिथि के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहते थे, जो बेहद साफ़-सुथरी छवि का मालिक हो. इसके लिए हमारा पहला और आख़िरी चुनाव कुरैशी साहब थे. उन्होंने कुरैशी साहब को लोकतंत्र का महान सिपाही क़रार दिया और कहा कि जब तक कुरैशी साहब जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तब तक इस देश के लोकतंत्र को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता. गांधी जी के बाद अगर देश में कुछ साफ़ और पारदर्शी छवि वाली ईमानदार हस्तियां पैदा हुई हैं तो उनमें कुरैशी साहब का नाम बेहद बुलंद है. चौथी दुनिया उर्दू की संपादक वसीम राशिद ने कुरैशी साहब को देश और लोकतंत्र की अमूल्य विरासत क़रार दिया.

इस अवसर पर शाम-ए-ग़ज़ल का भी आयोजन किया गया. आगरा का सूर सदन हाल उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जब भूपेंद्र और मिताली की मदहोश कर देने वाली ग़ज़लों ने माहौल को बेहद रोमांचक बना दिया. इससे पहले चौथी दुनिया के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संस्करण के मैनेजिंग एडिटर सुनील कौशिक ने श्री कुरैशी, श्री संतोष भारतीय और श्री अखिलेश सिंह (सीनियर स्प्रिचुअल स्कॉलर, लखनऊ) का बैज लगाकर स्वागत किया. वहीं शिवानी गुप्ता ने श्रीमती संतोष भारतीय एवं श्रीमती वसीम राशिद को बैज लगाकर उनका स्वागत किया.

nawazish@chauthiduniya.com

भाजपा में गृहयुद्ध

पृष्ठ एक का शेष

के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राज्य में लगातार विजय पताका फहराने पर कर्नाटक की जनता की ओर से कोटि-कोटि बधाई, लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी गुजरात पर राष्ट्रवाद की विजय पताका फहराने और राज्य को विकास के नए सोपान पर ले जाने वाले मोदी का हार्दिक अभिनंदन...आइए, भयंकर झंझावातों से जूझ रहे देश को निर्णायक दिशा दीजिए. दरअसल, सुषमा के बयान पर मोदी नाराज़ थे. इस विवाद पर न तो आडवाणी कुछ बोले और न ही नितिन गडकरी. अख़बार में छपे विज्ञापन से मोदी ने दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं को यह संदेश दे दिया कि वह सिर्फ़ गुजरात के नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वह भी अगले आम चुनाव में प्रधानमंत्री और आडवाणी जी के उत्तराधिकारी बनने के इच्छुक हैं. पार्टी में सुषमा स्वराज के बयान को लेकर काफी बवाल मचा और बाद में सुषमा ने अपना बयान वापस ले लिया.

बिना जनाधार वाले नेता अगर किसी पार्टी के कर्ताधर्ता बन जाते हैं तो उस पार्टी में किसी भी नए नेता को उभरने का मौक़ा नहीं मिलता. उभरता हुआ नेता साजिश का शिकार हो जाता है. हाल में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए एक आंदोलन छेड़ा. इसके लिए वह लालकृष्ण आडवाणी से मिले और उनकी अनुमति से कोलकाता से श्रीनगर तक की यात्रा शुरू की. शुरू में लोगों को लगा कि इस यात्रा को ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद यह यात्रा विवादों में आ गई और पूरे देश का ध्यान इस पर चला गया. मौक़ा देखते ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता इसमें कूद पड़े. अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने यात्रा को हाईजैक कर लिया और अनुराग ठाकुर की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया. जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की किसी भी भूमिका की योजना नहीं थी. जब दिल्ली में आडवाणी जी ने इस यात्रा को झंडी दिखाई थी, तब उस कार्यक्रम में न तो जेटली थे और न ही सुषमा स्वराज. एकता यात्रा कोलकाता से शुरू हुई और इसे काफी जनसमर्थन मिलने लगा था. मीडिया में भी इस पर जमकर बहस शुरू हो गई.

उधर कर्नाटक में गवर्नर और मुख्यमंत्री येदुरप्पा के बीच लड़ाई शुरू हो गई. गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आडवाणी जी अपने चहेते नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिले. जनता का ध्यान कर्नाटक से हटाने के लिए सुषमा स्वराज और अरुण जेटली एक विशेष हवाई जहाज से जम्मू पहुंच गए. उनके पहुंचते ही इस यात्रा के हीरो अनुराग ठाकुर की भूमिका एक साइड हीरो की हो गई. इसके बाद से यात्रा के बारे में मीडिया में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज नज़र आने लगे. यात्रा के बाद हुई प्रेस कांफ्रेंस में अनुराग ठाकुर उपस्थित तो रहे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोले. असलियत यही है कि इस यात्रा से उठे विवाद से बिना जनाधार वाले नेताओं ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की. अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के जम्मू पहुंचने से दूसरे नेताओं का रास्ता बंद हो गया तो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह दिल्ली के राजघाट में भूख हड़ताल पर बैठ गए.

भारतीय जनता पार्टी के सामने सुनहरा मौक़ा है. देश की जनता सरकार की नीतियों से त्रस्त है. महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और घोटालों के पर्दाफाश से सरकार बैकफुट पर आ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मौक़े का फ़ायदा नहीं उठा पा रही है. समस्या यह है कि पार्टी देशव्यापी आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं है. इसकी वजह यह है कि दिल्ली के मुख्यालय में जिन्हें यह फ़ैसला लेना है, वे इसे सफल नहीं

बना सकते हैं. और, जो लोग इसे सफल बना सकते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फ़ायदा दूसरे लोग उठा ले जाएंगे. इसी असमंजस में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है कि अगर आंदोलन होगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा. पार्टी का अध्यक्ष ऐसा बना है, जो संघ के इशारे पर काम करता है. एक साल बीत जाने के बाद भी गडकरी के कामकाज करने का तरीक़ा ऐसा है, जिससे लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का अनुभव नहीं है. वह भाजपा के ऐसे अध्यक्ष हैं, जो कार्यक्रम वग़ैरह में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन एक नेता की भांति देश की जनता का नेतृत्व नहीं कर सकते. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ देश की जनता का भी भारी नुक़सान हो रहा है. जिस विश्वास से जनता ने उसे विपक्ष की भूमिका दी, उसे वह सही ढंग से नहीं निभा पा रही है. ऐसे हालात में सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी भी देश की जनता के गुस्से का शिकार हो सकती है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 50
दिल्ली, 21 फरवरी-27 फरवरी 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4 सेक्टर 11, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफसपा) घाटी में सेना की बर्बरता का एक जीता-जागता उदहारण है, जिसके तहत वह किसी भी तरह की मनमानी कर सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं.

मिस से सबक़ लें सरकार

ए बी वर्धन

आम आदमी का आक्रोश धीरे-धीरे बढ़ रहा है. महंगाई, घोटाले और भ्रष्टाचार इस आक्रोश को हवा दे रहे हैं. इन समस्याओं की असल वजह और इस मसले पर राजनीतिक दलों से लेकर आम आदमी और मीडिया की भूमिका को देखना-समझना होगा. मिस्र में जो हुआ, ट्यूनीशिया में जो हुआ, अरब और ग़ैर अरब के कुछ देशों में इस वक़्त जो हो रहा है, उससे भारत के सभी राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए. महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकार की अकर्मण्यता पर यहां भी जनता में आक्रोश है. सरकार कह रही है कि महंगाई दूसरे देशों में भी है तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे देशों में लाखों लोग तानाशाही के ख़िलाफ़ सड़क पर उतर आए हैं. इससे सरकार को सबक लेना चाहिए. हमारे यहां लोकतंत्र है, इसका यह मतलब नहीं है कि लोग सड़क पर नहीं उतर सकते. जनता अपना रोष सिर्फ़ मतदान के ज़रिए ही नहीं प्रकट करती. जैसे महाभारत में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, वैसे जनता भी अपना विराट रूप दिखा सकती है. सरकार भ्रष्टाचार पर क्या सोचती है, यह उसके मंत्री कपिल सिब्बल के बयान से पता चलता है. 2-जी मामले पर सिब्बल ने कैग की रिपोर्ट को झूठा साबित करने की कोशिश की. राजा की गिरफ़्तारी से भी कुछ ख़ास नतीजा देखने को नहीं मिलेगा. करुणानिधि से हरी झंडी लेकर उनकी गिरफ़्तारी हुई है. इस पूरे मामले पर लीपापोती की कोशिश होगी.

अगर हर्षद मेहता तक जाएं, तो तब तक के घोटाले चंद करोड़ रुपये के ही हुआ करते थे. बोफोर्स का मामला, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा, महज़ 64 करोड़ रुपये का था, लेकिन अब लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले हो रहे हैं. राष्ट्रमंडल खेल, 2-जी स्पेक्ट्रम, स्विस अकाउंट की कहानी सामने है. इन सबकी जड़ में लोग नहीं जा रहे हैं कि आख़िर यह लूट मची क्यों है. असल में पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ में ही भ्रष्टाचार है. हालांकि मैं यह नहीं कहता कि समाजवादी व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में कार्रवाई होती है. चीन में तो घोटालेबाज़ों को फांसी तक दी गई है. संपत्ति के लालच की कोई सीमा नहीं होती.

हमारे यहां की पूंजीवादी व्यवस्था में, खासकर पिछले 15-20 सालों में घोटालों की संख्या अचानक बढ़ी है और अगर हम इसकी जड़ में जाएं तो पाते हैं कि पिछले 20 सालों के दौरान मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी रहे और अब पिछले सात सालों से प्रधानमंत्री हैं. अमेरिका के आदेश पर इन्होंने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर नव उदारवादी अर्थव्यवस्था लागू की. इस अर्थव्यवस्था का दर्शन ही अधिकतम लाभ कमाना है. आम जनता तो जीवनयापन के चक्कर में ही इतनी व्यस्त है कि वह अधिकतम लाभ कमाने के बारे में सोच भी नहीं पाती. अब रह गए चंद मुट्ठी भर लोग यानी कुछ ख़ास औद्योगिक घराने. इनमें रिलायंस भी है, टाटा भी है, मित्तल भी है या कहें कि सब शामिल हैं. इन सबका व्यापार पिछले दस सालों में 100 गुना बढ़ गया. आख़िर यह कैसे संभव हुआ? क्या बिना भ्रष्टाचार किए, रिश्वत लिए या सरकार को बिना हाथ में लिए ऐसा होना संभव था? वर्तमान आर्थिक नीतियों की जड़ में ही भ्रष्टाचार है. क्या 2-जी मामले में अधिकारियों और मंत्रियों को रिश्वत नहीं खिलाई गई होगी? पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है लाभ कमाना, जबकि नव उदारवादी व्यवस्था में लाभ कमाने की कोई सीमा नहीं होती और न कोई मर्यादा. आप माइनिंग माफ़िया, गैस माफ़िया और तेल माफ़िया को इसका उदाहरण मान सकते हैं. 8 से 9 प्रतिशत की विकास दर की यही सच्चाई है और आधार भी. इसी देश में एक ओर अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश की 70 फ़ीसदी आबादी की रोज की कमाई 20 रुपये से भी कम है. हम पहले कहते थे कि दिन दूना-रात चौगुना विकास करो और आज की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि कुछ लोग दिन में लाख गुना और रात में करोड़ गुना कमा रहे हैं.

एक सवाल यह उठता है कि क्या इसके पीछे गठबंधन की राजनीति भी एक कारण है. मैं ऐसा नहीं मानता. अब सिंगल पार्टी का सत्ता में आ पाना संभव नहीं है. यह ज़रूर है कि गठबंधन का जमाना है और सब मिल-बांटकर खा रहे हैं. वाजपेयी सरकार से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक यही सब हुआ. लेकिन तय मानिए, अगले चुनाव में घोटालेबाज़ कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है. अभी पता चला कि नासिक की मंडी में किसानों से 5 रुपये किलो प्याज ख़रीदा गया, फिर उसे बड़े ख़रीददार ने 20 रुपये किलो की दर से ख़रीदा और आख़िरकार वही प्याज आम आदमी तक 48 रुपये किलो की दर से पहुंचा. मैं पूछता हूं कि 48 रुपये किलो बिकने वाले प्याज से किसानों को कितना मुनाफ़ा हुआ. ज़ाहिर है, सारा मुनाफ़ा बिचौलिए कमा रहे हैं. सरकार इस मुगालते में न रहे कि जनता सड़क पर नहीं उतरेगी. जनता ज़रूर सड़क पर उतरेगी और जब उतर जाएगी तो सरकार को समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करना है.

लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन बड़े-बड़े घोटाले इन्हीं के कार्यकल में हो रहे हैं. मैं ऐसा मानता हूं कि जो ऊपर की कुर्सी पर बैठा है, वह ईमानदार है, यह अच्छी बात है. लेकिन जो उनके नीचे है और घोटाले कर रहा है और वह उसे संरक्षण दे रहे हैं. तो फिर ऐसी ईमानदारी किस काम की? नेहरू ईमानदार थे, ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा. गांधी ईमानदार थे, यह कहते हुए मैंने किसी को नहीं सुना, क्योंकि उनकी ईमानदारी उनके व्यक्तित्व में इस तरह घुली-मिली थी कि यह सब कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई. अगर मनमोहन सिंह ईमानदार हैं तो फिर स्विस बैंक अकाउंट्स के नामों का खुलासा क्यों नहीं करते? स्विस बैंक अकाउंट्स में जमा पैसा तो क्राइम का है, ग़ैर क़ानूनी ढंग से कमाया और जमा किया गया है. स्विस अधिकारियों ने कभी नहीं कहा कि आप नाम नहीं बता सकते. अगर कोई ट्रिटी है, जिसके तहत आप नामों का खुलासा नहीं कर सकते तो यह ट्रिटी किसने की? क्यों की? आख़िर इस सब का जवाब कौन देगा?

नेहरू ईमानदार थे, ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा. गांधी ईमानदार थे, यह कहते हुए मैंने किसी को नहीं सुना, क्योंकि उनकी ईमानदारी उनके व्यक्तित्व में इस तरह घुली-मिली थी कि यह सब कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई. अगर मनमोहन सिंह ईमानदार हैं तो फिर स्विस बैंक अकाउंट्स के नामों का खुलासा क्यों नहीं करते? स्विस बैंक अकाउंट्स में जमा पैसा तो क्राइम का है.

बावजूद इसके भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक मज़बूत राजनीतिक आंदोलन नहीं दिख रहा है. असल में जब जनता मुख्य विपक्षी दल भाजपा से इस सब की उम्मीद करती है, तभी पता चलता है कि मैंने भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए मुख्य तौर पर जिन नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को ज़िम्मेदार बताया था, भाजपा भी उन्हीं नीतियों की समर्थक रही है और अपने शासनकाल में उसने इन्हीं नीतियों पर चलने का फ़ैसला किया था. भ्रष्टाचार से तो फिर भाजपा भी नहीं बची है. ये लोग कर्नाटक में अपने एक विवादास्पद मुख्यमंत्री को नहीं हटा सके. ऐसे में मुख्य विपक्षी दल से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. जहां तक वामपंथी पार्टियों से ऐसी उम्मीद की जा रही है तो यहां भी कुछ समस्याएं हैं. हालांकि इससे पहले मैं मीडिया की भूमिका के बारे में भी बताना चाहता हूं. बोफोर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मामले को मीडिया ही जनता के सामने लाया, 2-जी को भी मीडिया ही सामने लाया, लेकिन मीडिया यह नहीं बता पा रहा है कि कौन इन मामलों के लिए लड़ा, किसने आवाज़ उठाई? कभी किसी ने सुना कि कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा स्विस बैंक में है? इन बातों को मीडिया सामने नहीं लाता. मिस्र में जो आज इतना बड़ा आंदोलन हम सब देख रहे हैं, उसमें अल जजीरा की भी भूमिका है. मीडिया हमारे बारे में (वामपंथी पार्टियों) न्याय नहीं कर रहा है. वह हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंचाता. अंतिम फ़ैसला जनता को ही करना है, इसलिए यह ज़रूरी है कि मीडिया जनता को उसके लिए तैयार करें.

हम जब यूपीए-1 की सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, तब भी उससे नीतियों के आधार पर टक्कर ले रहे थे. हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर समर्थन दे रहे थे. हमने फाइनेंसियल सेक्टर का निजीकरण नहीं करने दिया. ज़्यादा देर हम ख़ुद को वहां नहीं रोक पाए. हमने समर्थन वापस ले लिया. न्यूक्लियर डील से डेढ़ साल पहले से ही हमने यूपीए की बैठकों में जाना छोड़ दिया था. वैसे मैं आत्मालोचना करते हुए कहता हूं कि लेफ्ट की ताक़त अब उतनी नहीं रही. लेफ्ट की ताक़त अब लाखों लोगों को सड़क पर उतारने की नहीं रही. इस काम के लिए भी हमें मीडिया का सहयोग चाहिए. एक अंतिम बात कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं. कश्मीर का हल बंदूक़ और सेना के ज़रिए नहीं निकाला जा सकता. पत्थर के जवाब में गोली चलाने से समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला. पूरे कश्मीर को नर्क बना दिया गया है.

आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफसपा) घाटी में सेना की बर्बरता का एक जीता-जागता उदहारण है, जिसके तहत वह किसी भी तरह की मनमानी कर सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं. मानो रक्षक ही भक्षक बन गया हो. केंद्र को चाहिए कि वह जल्द से जल्द अफसपा को हटाए. जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों की मांग करना गुनाह है? आख़िर उनका अपराध क्या है, जो उन मासूम कश्मीरियों की दुर्गति हो रही है? क्या उन्हें रोकने का यही तरीक़ा बचा है सरकार के पास? जिन लड़कों को गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए. जिन्होंने गंभीर अपराध, जैसे हत्या आदि की है, उन पर मुक़दमा चले, लेकिन बिना किसी जुर्म के जेल में बंद लड़कों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए. इस वजह से एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई है. सेना को अगर पूरी तरह से नहीं हटा सकते तो भी उन्हें बैरक में रहने को कहा जाए. सेना की परेड राजपथ पर ही देखने में अच्छी लगती है, अगर उसे आपके घर के सामने बैठा दिया जाए तो ज़ाहिर है, आपको अच्छा नहीं लगेगा. कश्मीर एक राजनीतिक मसला है, इसका हल भी राजनीतिक ही होना चाहिए. पीपुल्स टू पीपुल्स डायलॉग शुरू किया जाना चाहिए.

(लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं)

feedback@chauthiduniya.com

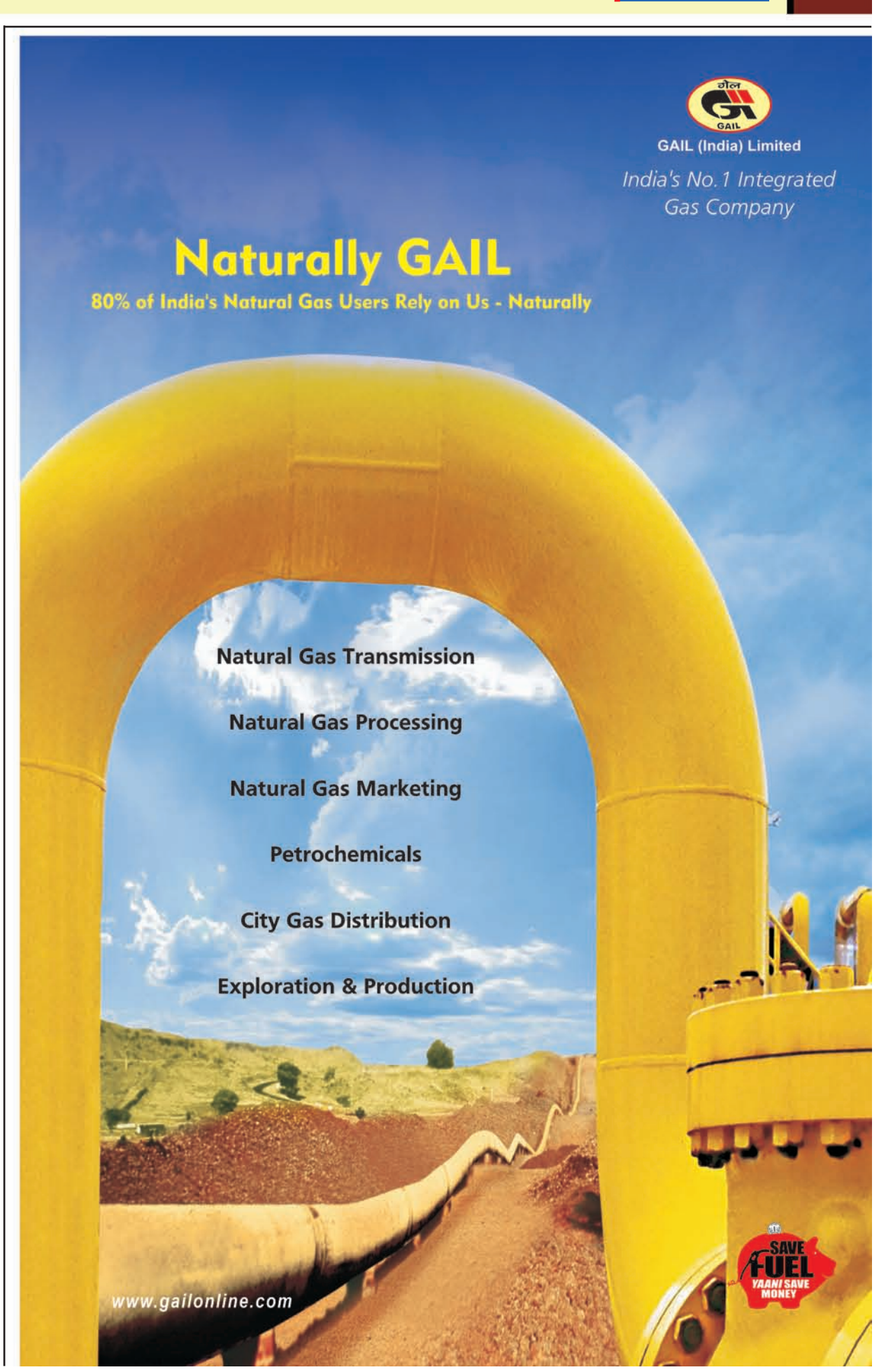

विजिलेंस ने कोर्ट को बताया कि आवास बोर्ड के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस पर कोर्ट का कहना था कि आरोपी से विजिलेंस सहयोग की अपेक्षा करती है!

नीतीश सरकार को अदालत की फटकार

सरोज सिंह

बिहार में नीतीश सरकार विकास एवं बेहतर कार्य संस्कृति के भले ही लाख दावे कर रही है, पर पटना हाईकोर्ट को लगता है कि सरकार में राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी है. अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि पटना जंगल है और यहां अफसरों की मिलीभगत से हर काम कराना संभव है. राजधानी पटना सहित कई ज़िलों में सड़क जाम और यातायात नियमों की घोर अनदेखी पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अव्यवस्था का मुख्य कारण राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी है, लेकिन यह अब बर्दाश्त से बाहर है. यदि जाम से निज़ात दिलाने के लिए नीतिगत फ़ैसला न लिया गया तो उच्चाधिकारियों की परेड कराई जाएगी.

न्यायमूर्तिद्वय शिवकीर्ति सिंह एवं डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया था कि चुनाव के बाद अतिक्रमण एवं सड़क जाम से छुटकारा दिलाने के लिए लघु एवं दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी, लेकिन सरकार अब भी पुराना राग ही अलाप रही है. कोर्ट ने जानना चाहा कि सड़क के किनारे आख़िर कौन बंदोबस्त करता है, लोग किस तरह सड़क के किनारे दुकानें बना लेते हैं. इसी तरह पटना में बन रहे बेतरतीब अपार्टमेंटों पर भी कोर्ट ने नाराज़गी जताई है. सबसे ज़्यादा फटकार विजिलेंस ब्यूरो के क्रियाकलापों को लेकर लगाई गई. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने कहा कि यदि राज्य सरकार सचमुच भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहती है तो सबसे पहले उसे निगरानी अन्वेषण विभाग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ विजिलेंस ही है. कोर्ट ने विजिलेंस को 2008 में आवास बोर्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा देने को कहा था. विजिलेंस को कर्मचारियों के कार्यकलापों की जांच भी करनी थी.

विजिलेंस ने कोर्ट को बताया कि आवास बोर्ड के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस पर कोर्ट का कहना था कि आरोपी से विजिलेंस सहयोग की अपेक्षा करती है. ऐसा कभी हुआ है कि अभियुक्त स्वयं बताए कि उसने क्या किया है. ऐसा प्रतीत होता है कि विजिलेंस आवास बोर्ड के साथ मिला हुआ है. निगरानी विभाग पर कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकार की भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग पर प्रश्नचिन्ह लग गया है. आख़िर जिस हथियार से लड़ाई लड़ी जानी है, उसकी गुणवत्ता कोर्ट की टिप्पणी से साफ हो जाती है. सभी जानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना कोई सरल काम नहीं है. ख़ुद नीतीश कुमार भी महसूस करते हैं कि यह बड़ी जंग है. उन्होंने कई मौक़ों पर कहा कि भ्रष्टाचारियों में ताक़त है तो वे मुझे उखाड़ फेकें नहीं तो मैं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दूंगा. सरकारी कार्यालयों से लेकर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर धब्बे हैं. यही वजह है कि सरकार इस काम की गंभीरता को समझ रही है.

निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अशोक कुमार चौहान कहते हैं कि सरकार प्रीवेंटिव विजिलेंस सिस्टम विकसित करेगी, जिसका मक़सद भ्रष्टाचार ख़त्म करना है. सभी विभागों से बातचीत करके सीवीओ के पद सृजित कराने का प्रयास किया जा रहा है. चौहान का कहना है कि भ्रष्टाचार समाप्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखकर ज़िला स्तर पर भी फ्लाइंग स्क्वॉयड का गठन किया गया है, जो डीएम के अंतर्गत काम करता है और इसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं. चौहान के दावों के उलट एक सच्चाई यह भी है कि निगरानी विभाग ख़ुद अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है. जिस तरह भ्रष्टाचार उन्मूलन के दावे किए जा रहे हैं, उसे अमलीजामा पहनाने के लिए एक ऐसे निगरानी विभाग की ज़रूरत है, जो सभी संसाधनों से लैस हो, पर विभाग के मौजूदा ढांचे को देखने से तो लगता है कि लड़ाई कहीं आधी-अधूरी न रह जाए.

बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े अभी लगभग दो हज़ार मामले लंबित हैं. दरअसल कोर्ट का गुस्सा इसी आधी-अधूरी तैयारी को लेकर था. सरकार कोर्ट से वादा कर आती है, पर अगली सुनवाई में वह एक- दो क़दम से आगे नहीं दिखती. कोर्ट का डंडा चलता है तो सारा अमला हरकत में आता है, पर कुछ दिनों बाद सब कुछ पुराना पड़ जाता है और गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी दिखाई पड़ती है. लोगों को याद है, जब लालू -राबड़ी शासन के दौरान कोर्ट के डंडे से ही कुछ चीजें पटरी पर रहती थीं. क़ानून व्यवस्था से नाराज़ कोर्ट ने कई दफ़ा तो बिहार में जंगलराज तक कह दिया था. लोगों को उम्मीद है कि फिर पुरानी कहानी नहीं दोहराई जाएगी और कोर्ट ने जिन मामलों में चिंता जताई है, उन पर सरकार गंभीरता से ध्यान देगी.

feedback@chauthiduniya.com

आदिवासियों की उपेक्षा कब तक?

आज देश का आदिवासी समुदाय राजनीति के केंद्र में आ गया है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने देश की सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष का बिगुल बजा दिया है. आदिवासी एक ऐसे सामजिक समूह के सदस्य हैं, जो आज अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है. वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं. आदिवासियों के प्रति सरकार और समूचे भारतीय समाज का नकारात्मक रवैया देश के संविधान में उन्हें दिए गए अधिकारों के विरुद्ध जाता दिख रहा है. इन सारे कारणों की वजह से जब आज उन्हें क़ानून अपने हाथ में लेना पड़ता है तो देश की सुरक्षा एजेंसियां उन पर अत्याचार करती हैं, उन्हें लाठियों-बंदूक़ों का बेवजह सामना करना पड़ता है.

अगर हम वास्तव में आदिवासियों की समस्याओं को समझना चाहते हैं तो यह याद रखना और समझना होगा कि आदिवासी समुदाय और उसकी मान्यताएं किस तरह भारत के अन्य समुदायों से भिन्न हैं. आदिवासी समुदाय कुछ ऐसी मान्यताओं-आदर्शों पर आधारित है, जो बाक़ी देश से अलग हैं. यह समुदाय ऐसे सामाजिक संबंधों से परिभाषित होता है, जो प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करके चलता है. इसके सिद्धांत लेनदेन से अधिक समान योगदान, सच्चाई और आपसी पारदर्शिता पर आधारित हैं. यह समुदाय अपने लड़ाई-झगड़ों को निपटाने के लिए आधुनिक न्याय प्रणाली पर नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही सामुदायिक संस्थाओं का सहारा लेता है. एकता और बाहरी जीवन से कटाव इस समुदाय के प्रमुख लक्षण हैं. इसकी परंपरागत अर्थव्यवस्था ज़मीन और जंगल की धुरी पर केंद्रित है.

ऐसी व्यवस्था, जो पैसे और बाज़ार से अधिक आपसी सौहार्द्र पर आधारित है और आत्मनिर्भरता जिसका सबसे बड़ा लक्षण है. यह व्यवस्था पैसे के लेनदेन से अधिक वस्तु विनिमय पर आधारित है. इसीलिए इसे समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था कहा जा सकता है. आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध यहां पूंजी और बाज़ार का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था के कुछ अवगुण भी हैं. यह एक बंद व्यवस्था है और समान वितरण पर आधारित है, इसलिए जब भी सूखा या बाढ़ जैसी त्रासदी होती है तो यह व्यवस्था दबाव में आ जाती है, क्योंकि और कोई साधन उपलब्ध नहीं होते. इस समुदाय का राजनीतिक संगठन भी पारंपरिक हैं, जहां निपटारा बड़े-बूढ़ों द्वारा ही किया जाता है और उनकी बात सर्वमान्य होती है. यह स्वराज का ही एक स्थानीय मॉडल कहा जा सकता है, लेकिन देश की मुख्यधारा से यह सब बहुत ही अलग है.

आज़ादी के बाद से इस आदिवासी समुदाय में भी कई दूरगामी बदलाव आए, कभी सरकारी विकास योजनाओं के थोपे जाने और कभी सरकार के प्रतिबंधों-निषिद्ध आज्ञाओं के चलते, लेकिन आज भी इस समुदाय का वही हाल है, जो बताया जा रहा हैं. आदिवासियों से भारतीय समाज की मुख्यधारा की दूरी ही सरकारी रवैये के लिए भी ज़िम्मेदार है. जैसा कि हम जानते हैं कि आदिवासी राज्य व्यवस्था के बाहर ही रहे हैं और इसी वजह से वे आज तक अपनी पुरानी परंपरागत जीवनशैली को संभाल पाए हैं, बिना किसी बड़ी उथल-पुथल के. यह स्वावलंबी व्यवस्था देश की स्वाधीनता के समय बिगड़नी शुरू हो गई. इसका मुख्य कारण था देश और इन क्षेत्रों में ऐसी नीतियों का प्रतिपादन, जो पहले न कभी सुनी और न देखी गईं. सबसे बड़ा असर पड़ा ब्रिटिश हुकूमत की उस नीति का, जिसके तहत प्राकृतिक संपदा को राज्य के नियंत्रण के अधीन लाया गया.

ब्रिटिश हुकूमत की स्थायी बंदोबस्त नीति ने खेतिहर किसानों को तो भिखारी बना ही दिया, आदिवासियों को भी बाहरी लोगों और सूदखोर महाजनों का शिकार बना दिया. ज़मीन अब ख़रीद-फरोख्त की वस्तु बन गई और ज़मीन का बाज़ारीकरण हो गया. इस कारण ज़मीन साझा नहीं रह गई और पारंपरिक अधिकार ख़त्म हो गए. इस सभी कारणों से आदिवासी अपनी ज़मीन खोते गए. ज़मीन अधिग्रहण कानून ने इस नीति को और भी कंटीले दांत दे दिए. जंगल और वन संपदा अब सरकारी तंत्र के हाथ में आ गए. खनन और वन संपदा के सरकारी प्रयोग के चलते आदिवासी अपनी ज़मीन और घर खो बैठे. इस नई व्यवस्था में आदिवासी कम वेतन पर काम करने वाले ग़रीब मज़दूर बन गए. सरकारी तंत्र का मतलब पुलिस और क़ानून व्यवस्था भी होती है. इस सरकारी व्यवस्था के दिन-प्रतिदिन बढ़ते जाने से आदिवासियों की अपनी परंपरागत संस्थाएं भी मर गईं. जब उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो क़ानून बना दिया गया कि ऐसे आदिवासी जन्मजात रूप से अपराधी प्रवृत्ति के हैं.

आज़ादी मिलने के बाद जिन आदिवासियों को सरकार को संजोकर रखना चाहिए था, उनकी कोई सुध नहीं ली गई. पुराने तरीक़ों पर आदिवासियों का शोषण और उनके हितों का हनन चलता रहा. यहां तक कि नए-नवेले तरीक़े भी खोज लिए गए शोषण की इस परंपरा को और सशक्त करने के लिए. आदिवासियों को पहले से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर बाज़ार से जोड़ दिया गया. ऊपर से जंगल-प्राकृतिक संपदा का दोहन और भी बढ़ गया. आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों की पैठ भी पहले से अधिक हो गई. जब भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए खोल दिया गया और नव उदारवाद का शिकंजा कसने लगा तो आदिवासी क्षेत्रों का दोहन दूर देशों की पूंजी ने भी करना आरंभ कर दिया. इसके साथ ही ज़मीन का अधिग्रहण भी बड़े पैमाने पर हुआ. यह अधिग्रहण राज्य और निजी कंपनियों, दोनों ने ही किया. क़ानून भी ऐसे बना दिए गए, जिससे आदिवासियों का संरक्षित क्षेत्र बाहरी ख़रीद-फरोख्त के लिए बिल्कुल ही खुल गया. सरकारी तंत्र को सुडौल बनाने के लिए लाए गए सुधारों के नाम पर सरकारी पद कम किए गए. सरकार अपने कर्तव्यों की अनदेखी करती रही, नतीजतन आदिवासियों के जीवन स्तर में गिरावट आने लगी और नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के कारण छोटे क़र्ज़ की संभावनाएं भी कम होती चली गईं. आदिवासियों की मौजूदा स्थिति को सामाजिक-आर्थिक पैमाने पर समझा जा सकता है. आर्थिक पैमाने को देखा जाए तो आदिवासी देश के मज़दूरों से अधिक संख्या में हैं, लेकिन इसके विपरीत वे उनसे बदतर हालत में हैं, क्योंकि वे अधिकतर कृषि पर निर्भर हैं और उनकी दिहाड़ी या वेतन का स्तर बहुत ही निम्न है. कृषि से बाहर उनकी भागीदारी सबसे कम है या कहें कि नगण्य है. आदिवासियों के पास खेती लायक़ ज़मीन न के बराबर है और वे बहुत छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं. बस एक चौथाई ऐसे हैं, जिनके पास कहने को ही सही, लेकिन सिंचाई का साधन है.

सीमित साधनों के चलते वे साल में केवल एक ही फ़सल उगा पाते हैं. उन्हें न तो कोई सरकारी अनुदान मिलता है और न क़र्ज़, जो कम ब्याज वाला हो. इसलिए अधिकतर आदिवासी साहूकारों की गिरफ़्त में हैं और धीरे-धीरे अपनी ज़मीनों से हाथ धोते जा रहे हैं. ग़रीबी के कारण वे कुपोषण के शिकार हैं और भुखमरी एक आम बात है. आज़ादी के बाद भारत में ग़रीबी कम हुई, लेकिन आदिवासियों में ग़रीबी आज भी सबसे अधिक है. उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है और आज भी प्रति व्यक्ति आय-व्यय के मामले में वे देश के अन्य तबकों से काफी पीछे हैं. सामाजिक पैमाने पर भी उनकी हालत काफी ख़राब है. सबसे अधिक पिछड़ापन आदिवासियों में ही पाया जाता है, चाहे वह साक्षरता हो, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हो या फिर जच्चा-बच्चा की मृत्यु दर.

के बी सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com
(लेखक पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं)

पहाड़ी वोटरों को लुभाने के लिए पिछले साल उन्होंने वहां का दौरा किया था, पर गोरखालैंड स्वायत्त परिषद के गठन को लेकर उन्होंने किसी तरह का बयान नहीं दिया.

पश्चिम बंगाल

ममता जी, आपका एक्शन प्लान क्या है

बिमल राय

बंगाल के बाहर के लोग नहीं जानते हैं कि ममता बनर्जी ने हावड़ा से सिंगुर तक आंदोलन नामक एक लोकल ट्रेन भी चला रखी है. यह ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को याद दिलाते रहने के एक प्रतीक की तरह है कि उनके भूमि आंदोलन ने जो जंग जीती है, उसे आगे भी जारी रखना होगा और नैनो के बाद अब वाममोर्चे को लालकिले से बेदख़ल करना होगा. पर विडंबना यह है कि आंदोलन का यह प्रतीक 33 सालों से राज कर रहे वाममोर्चे को ममता को उनके ही हथियार से हराने का मौक़ा भी दे रहा है. राज्य में औद्योगीकरण के ताबूत में नैनो की विदाई की कील ठोंकने वाली ममता सांसत में हैं. इधर वाममोर्चा ममता की रेलवे परियोजनाओं की बुनियाद उसी आंदोलन एक्सप्रेस से ढहा रहा है. ममता ने पिछले दो बजटों में राज्य के लिए कई रेलवे परियोजनाओं का ऐलान करके बंगाल में बेरोज़गारी का हल निकालने या कम से कम उम्मीद जगाने की कोशिश की है, जिसे माकपा नेता एक झांसे से ज़्यादा कुछ नहीं मानते. इस तरह सिंगुर और नंदीग्राम का भूमि रक्षा आंदोलन अब ममता के इरादों को भी अपनी लपटों से झुलसा रहा है.

उद्योगों के लिए किसानों से ज़मीन लेने के मामले पर जिस तरह उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, वही अब उनके गले की फांस बन गया है. इसी वजह से ममता को रेलवे के लिए नई ज़मीन अधिग्रहण नीति बनानी पड़ी है. इसमें यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की ज़मीन जबरन नहीं ली जाएगी. खासकर खेती की ज़मीन का कम से कम उपयोग होगा और इसकी भरपाई के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी. यही नहीं, ममता की नई नीति के मुताबिक़, रेलवे को ज़मीन देने वाले हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत ज़मीन की क़ीमत बाज़ार दर से 30 प्रतिशत ज़्यादा दी जाती है, पर रेलवे 60 प्रतिशत ज़्यादा मुआवज़ा देगी. मालूम हो कि नोएडा में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ईडीएफसी) के लिए 140 हेक्टेयर ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर बवाल हुआ था और पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी. हालांकि पहले ममता ने यह कहते हुए बचाव किया था कि इस परियोजना के लिए ज़मीन की पहचान पिछले रेलमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में की गई थी.

सिंगुर में ममता अभी भी 997.11 एकड़ ज़मीन में से 400 एकड़ ज़मीन अनिच्छुक लोगों को वापस करने की मांग कर रही हैं और राज्य सरकार वहां कोई दूसरी ऑटो मोबाइल कंपनी लगाने का जनता से वादा कर चुकी है. हाल में सिंगुर में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया. अब राज्य सरकार उसी मुद्दे से तृणमूल को मात देने की तैयारी में है और बंगाल की भावी मुख्यमंत्री ममता के लिए सिंगुर मामला गर्म आलू हो गया है, जिसे न वह चबा सकती हैं और न निगल ही सकती हैं. वाममोर्चा मतदाताओं को बताना चाहता है कि ममता किस तरह यहां उद्योग लगाने का दूसरा प्रयास भी विफल करना चाहती हैं. ममता भी जानती हैं कि एक निश्चित समय बाद अधिग्रहीत की जा चुकी ज़मीन वापस नहीं लौटाई जा सकती, पर वोटबैंक पर नज़र रखते हुए वह अपना रुख़ नहीं बदल रही हैं. हालांकि चोट उन्हें भी खानी पड़ रही है.

हावड़ा ज़िले के सांकराइल में ममता ने 630 एकड़ में डीजल मल्टीपल यूनिट की योजना का बजट बनवाया और आनन–फानन में काम भी शुरू हो गया, पर वामपंथी कॉडरों के उकसावे में लोगों ने यहां ममता का ही हथियार चला दिया. कई पखवाड़े तक आंदोलन चला. लोगों ने ज़्यादा मुआवज़ा और परिवार के एक सदस्य को रेलवे की नौकरी देने की मांग की. ममता ने लोगों की मांग नहीं मानी और फैक्ट्री को वहां से हटाना ही बेहतर समझा. ग़ौरतलब है कि ममता रेलवे की नई भूमि अधिग्रहण नीति के ऐलान के बावजूद हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के वादे पर ना–नुकुर कर रही हैं. जोश में तो उन्होंने घोषणा कर दी, पर जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि इस एक्ट को पूरे देश की रेल परियोजनाओं पर लागू किया जाना है और बताने की ज़रूरत नहीं कि इससे कितनी बड़ी आफत आ सकती है. ज़ाहिर है, ममता की नीतियों में ढुलमुलपन साफ हो गया है. कुछ ऐसा ही मामला नंदीग्राम का है. नंदीग्राम में सिंगुर की सिर्फ़ कुछ चिंगारियां पहुंची थीं और वहां केमिकल हब बनाने के लिए केवल ज़मीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी. सिंगुर के दूध से जली वाममोर्चा सरकार ने तुरंत केमिकल हब को दूसरी जगह ले जाने की घोषणा की, पर तब तक वहां पुलिस फायरिंग में दर्जन भर लोग मारे जा चुके थे.

नंदीग्राम पूरे देश में भूमि रक्षा आंदोलन का प्रतीक बन गया और वहां महीनों तक मानवाधिकार समर्थकों का मेला लगा रहा. उसी नंदीग्राम को ममता ने रेल से जोड़ना चाहा और लाइनें बिछाने के लिए जब ज़मीन लेने की बारी आई तो लोग भड़क उठे. जैसे ही रेलवे के लोग ज़मीन मापने के लिए आए, गांववालों ने कहा कि मुआवज़े के बारे में पूरी जानकारी दिए बिना वे कुछ नहीं करने देंगे. इसके बाद नंदीग्राम के ए नंबर ब्लॉक के हरिपुर, देवीपुर, ताजपुर, वनश्री गौरी एवं रतनपुर जैसे गांवों में आपत्ति जता रहे लोगों को हड़काने के लिए तृणमूल की मोटरसाइकिल वाहिनी को उतरना पड़ा. बताया जाता है कि तृणमूल के लोगों ने घूम–घूमकर धमकाया कि लोग बेवजह बाधा पैदा करके विपत्ति मोल न लें. इसी तरह डानकुनी से फुरफुरा शरीफ तक रेल लाइन बिछाने के दौरान रेलमंत्री को चंडीतला में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा.

इन नीतिगत खामियों के अलावा ममता के पास रेलमंत्री के रूप में कामयाबी का कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय किराया–भाड़ा न बढ़ाने के. रेलमंत्री ने बंगाल में अपनी पार्टी का भविष्य सुधारने के लिए रेलवे का इतना आर्थिक दोहन किया कि भंडार शून्य हो गया. कोलकाता में तो शायद ही कोई दिन होगा, जब अख़बारों में किसी न किसी नई परियोजना के उद्घाटन का विज्ञापन न छपता हो. सनद रहे कि लगभग 80 फ़ीसदी विज्ञापन रेलवे रिज़र्वेशन काउंटरों के उद्घाटन, वह भी बंगाल के होते हैं. बीती तीन जनवरी को एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ने रेलवे के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह रेल का व्यय आय से बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक़, रेलवे का घाटा 2500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 1142 करोड़ रुपये की आमदनी के मुक़ाबले 1330 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है. वर्तमान वित्तीय वर्ष का 1000 करोड़ रुपये का घाटा तो दो बार डीजल की क़ीमतों के बढ़ने, 2 फ़ीसदी महंगाई भत्ते के भुगतान और दिल खोलकर कर्मचारियों को बोनस देने के कारण हुआ है. रेलवे की आर्थिक सेहत की माप ऑपरेटिंग अनुपात (यानी 100 रुपये कमाने के लिए कितना ख़र्च करना पड़ा) के प्रतिशत से होती है. 2001–02 में यह अब तक के सर्वोच्च 96 प्रतिशत तक पहुंचा था. यूपीए की पहली सरकार में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में यह 75.9 प्रतिशत तक आया, जिसे लेकर इतनी चर्चा हुई कि इसे तत्कालीन रेलमंत्री का करिश्मा कहा गया. वर्ष 2008–09 में यह आंकड़ा 90.5 और 2009–10 में ऑपरेटिंग अनुपात का प्रतिशत 98.9 हो गया. रेल भवन के सूत्रों के मुताबिक़, वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस अनुपात के 98 प्रतिशत से काफी आगे निकलने की आशंका है. बंगाल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ममता ने पिछले रेल बजट में किसी तरह के किराए एवं मालभाड़े में वृद्धि नहीं की थी और इस साल भी वैसी ही उम्मीद है. ज़ाहिर है, रेलवे की हालत और खस्ता होने वाली है.

राज्य के कई अन्य दूसरे मुद्दों एवं समस्याओं पर भी ममता का रुख़ साफ नहीं है. राज्य में माओवादियों की गतिविधियों को ही लें. अब पूरी तरह साफ हो गया है कि तीन ज़िलों यानी जंगल महल की लगभग दो दर्जन विधानसभा सीटों के लोभ में माओवादियों के प्रति ममता का रुख़ नरम रहा है. इस मामले पर वह जब–तब केंद्र को भी धमका देती हैं. तृणमूल के एक सांसद कबीर सुमन खुलेआम माओवादियों के लिए क्रांति गीत गाते हैं और बाक़ायदा पार्टी में बने हुए हैं. हाल में मिदनापुर में तृणमूल के राहत शिविर से सिलदा कांड से जुड़े दो माओवादियों को पकड़ा गया और उनकी निशानदेही पर सुरक्षाबलों से लूटे गए कई हथियार भी बरामद किए गए, पर ममता ने उसे राजनीतिक रंग दे दिया और कहा कि यह तृणमूल को बदनाम करने की सरकार की चाल है. मालूम हो कि सिलदा कांड में 22 सुरक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतारा गया था. उत्तर बंगाल के गोरखालैंड आंदोलन को लेकर भी ममता का रुख़ साफ नहीं है. पहाड़ी वोटरों को लुभाने के लिए पिछले साल उन्होंने वहां का दौरा किया था, पर गोरखालैंड स्वायत्त परिषद के गठन को लेकर उन्होंने किसी तरह का बयान नहीं दिया.

जाहिर है, गोरखालैंड का समर्थन करना राजनीतिक रूप से उनके लिए संभव नहीं है, पर जिस तरह राज्य के उद्योगपतियों के साथ बैठकें करने और माओवाद प्रभावित इलाक़ों से सुरक्षाबलों को हटाने की मांग सहित कई मुद्दों पर वह मुखर रही हैं, उसी तरह परिषद के गठन के माध्यम से इस समस्या का सर्वमान्य हल निकालने, चाय बागान श्रमिकों की समस्याओं के समाधान आदि के प्रति अपनी राय देकर वह एक सजग विपक्ष का रोल अदा कर सकती थीं और साथ–साथ मतदाताओं को अपनी भावी नीतियों का संकेत दे सकती थीं. इसी तरह ममता को एक मुकम्मल कृषि नीति, शिक्षा नीति और उद्योग नीति के साथ चुनावी अखाड़े में उतरना चाहिए. ये सब बातें वाममोर्चा के लोग मतदाताओं को समझा रहे हैं कि आप जिसे सत्ता सौंपना चाहते हैं, उसकी कोई अपनी नीति नहीं है, विजन नहीं है. ममता को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि लोग अब वाममोर्चा से ऊब गए हैं तो उन्हें सत्ता सौपेंगे ही. इस नकारात्मक जनादेश से उनकी प्रतिष्ठा में इज़ाफ़ा नहीं होगा, बेहतर होगा कि वह अपना एक एजेंडा सामने रखें.

feedback@chauthiduniya.com

आस्था व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है. कट्टर व्यक्ति अपने नेता का बौद्धिक गुलाम होता है. अरबी में धार्मिक आस्था के लिए ईमान शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है वह जो आदमी को सुरक्षा का भाव दे.

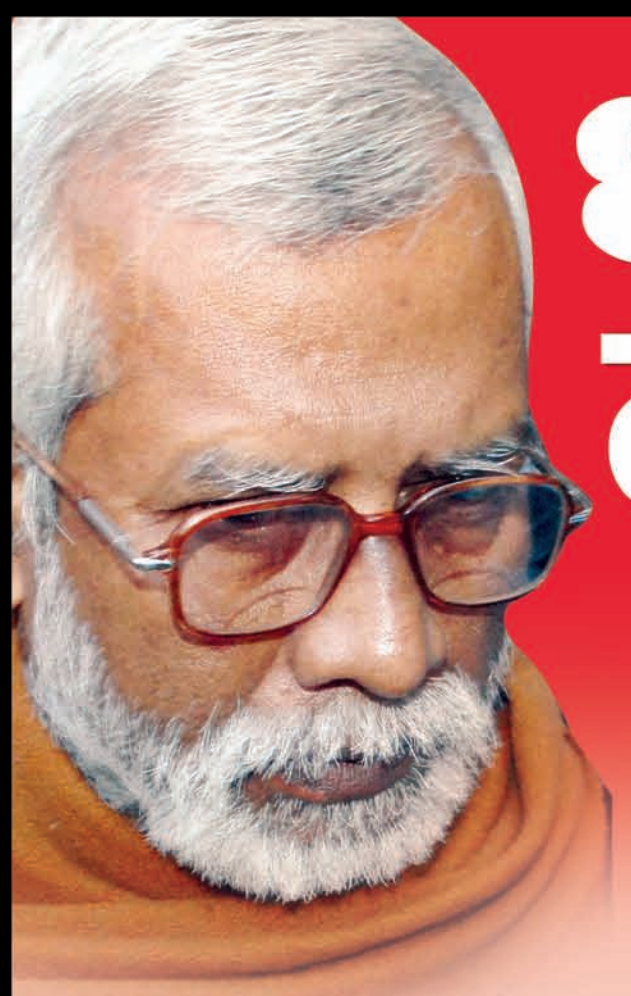

धार्मिक कट्टरता और धर्म

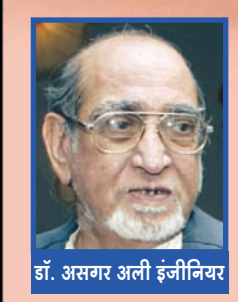

डॉ. असगर अली इंजीनियर

तार्किकता के पैरोकार, अक्सर धार्मिक कट्टरता के लिए धर्म को दोषी ठहराते हैं. क्या यह सोच सही है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हमें धार्मिक कट्टरता का अर्थ समझना होगा. सामान्य भाषा में हम यह कह सकते हैं कि कट्टर वह व्यक्ति है जिसने अपने दिमाग़ के खिड़की-दरवाजे बंद कर रखे हैं, जो किसी तर्क को सुनना या समझना ही नहीं चाहता. वह किसी नए विचार को ग्रहण करने के बजाय, पिटी-पिटाई लीक पर चलता रहता है. उसकी मान्यताओं-विश्वासों का खंडन करने वाले चाहे जितने तर्क दें, वह अपनी बात पर अड़ा रहता है. स्पष्टत:, कट्टरता का संबंध व्यक्ति की मानसिकता से है जबकि धर्म का ताल्लुक आध्यात्मिकता व नैतिकता से है.

आस्था और कट्टरता के बीच विभेद करना भी आवश्यक है. आस्था वह है जिस पर व्यक्ति पूरी दृढ़ता से विश्वास करता है. दृढ़ विश्वास के बिना आस्था का कोई अर्थ नहीं है. यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आस्था और कट्टरता में क्या अंतर है. आस्था और कट्टरता में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है. आस्था वह मान्यता है, जिस पर कोई व्यक्ति पूरी दृढ़ता से विश्वास करता है परंतु आस्था, तार्किकता पर आधारित होती है. आस्था से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसे आंतरिक शांति मिलती है. इसके विपरीत कट्टरता, अंधश्रद्धा पर आधारित होती है. कट्टरता से बौद्धिक विकास बाधित होता है.

आस्था व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है. कट्टर व्यक्ति अपने नेता का बौद्धिक गुलाम होता है. अरबी में धार्मिक आस्था के लिए ईमान शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है वह जो आदमी को सुरक्षा का भाव दे. कट्टर व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है और इसलिए वह कोई तर्क सुनना ही नहीं चाहता. जिस व्यक्ति में असुरक्षा का भाव और आत्मविश्वास की कमी जितनी अधिक होती है, वह व्यक्ति उतना ही कट्टर होता है. आस्थावान व्यक्ति, ज्ञानी व परिपक्व होता है जबकि कट्टर व्यक्ति, अज्ञानी व अपरिपक्व.

मैं आस्था और कट्टरता के बीच के अंतर पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन दिनों धार्मिक कट्टरता से प्रेरित कई हिंसक घटनाएं हो रही हैं. इनमें से सबसे ताजी घटना है तौहीन-ए-रिसालत क़ानून की ख़िलाफ़त करने वाले पंजाब (पाकिस्तान) के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या. इसमें कोई दो मत नहीं कि तासीर का हत्यारा धार्मिक व्यक्ति नहीं था. वह तो एक कट्टर शख्स था.

कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता. विशेषकर तब, जबकि उसका शिकार जिस क़ानून का विरोध कर रहा था, वह कोई दैवीय क़ानून नहीं था. वह तो पाकिस्तान की संसद द्वारा बनाया गया एक साधारण क़ानून था, जिसके निर्माण के पीछे धार्मिक नहीं बल्कि राजनैतिक उद्देश्य थे. जब पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जिया-उल-हक को लगा कि उनका सिंहासन डोल रहा है, तब उलेमा के एक तबके का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने यह क़ानून बना दिया. यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुटिल राजनेता अक्सर धार्मिक कट्टरता का इस्तेमाल अपने हितसाधन के लिए करते हैं और पाकिस्तान में तानाशाहों के अलावा वहां के कथित उदारवादी व प्रजातांत्रिक नेताओं ने भी यही किया है.

यहां यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि कट्टरपंथियों का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनके दृष्टिकोण को समझा जाए और उन्हें सच्चा ज्ञान दिया जाए. इस सिलसिले में स्वामी असीमानंद का उदाहरण हमारे सामने है. स्वामी असीमानंद एक हिन्दू कट्टरपंथी हैं. उनके साथ जेल में एक मुस्लिम युवक भी था, जो मक्का मस्जिद बम धमाके का आरोपी था. अब्दुल कलीम नामक इस मुस्लिम युवक ने स्वामी असीमानंद की भरपूर सेवा की. वह उनके लिए पानी और खाना लाता था और अन्य तरीक़ों से उनकी मदद करता था. यह इसके बावजूद कि उसे यह मालूम था कि असीमानंद की ऐसे अनेक विस्फोटों में भूमिका थी, जिनमें मुस्लिम मारे गए थे.

अब्दुल ने स्वामी को यह भी बताया कि उसे पुलिस के हाथों क्या-क्या शारीरिक यंत्रणाएं झेलनी पड़ीं. अब्दुल की निस्वार्थ सेवा से असीमानंद बहुत प्रभावित हुए. उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ. उन्हें लगा कि एक ओर वे हैं, जिनके कारण निर्दोष अब्दुल को घोर यंत्रणाएं झेलनी पड़ीं और दूसरी ओर अब्दुल है, जो सब कुछ जानते हुए भी उनकी सेवा कर रहा है. उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्होंने अपने गुनाह कुबूल नहीं किए तो अब्दुल जैसे कई मुस्लिम युवकों का जीवन बर्बाद हो जाएगा. असीमानंद ने अब्दुल से पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के बारे में कई प्रश्न पूछे. अब्दुल ने उन्हें बताया कि पैगंबर साहब कितने विनम्र थे और किस प्रकार वे अपने शत्रुओं को भी माफ कर दिया करते थे. इसका भी स्वामी पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने अपराध स्वीकार कर लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें मौत की सज़ा ही क्यों न भुगतनी पड़े.

इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि धार्मिक कट्टरपंथियों को भी बदला जा सकता है. ज़रूरत केवल इस बात की है कि उन्हें सही तथ्यों से परिचित करवाया जाए. चूंकि स्वामी असीमानंद, अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने इक़बालिया बयान पर क़ायम रहे, अत: यह मानना ग़लत होगा कि उन्होंने दबाववश इक़बालिया बयान दिया है. अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों के निवासियों ने, जो 9/11 के बाद से इस्लाम से घृणा करने लगे थे, क़ुरान का अध्ययन करने के बाद इस्लाम को अंगीकार कर लिया. कई ने मौलाना रूमी की मस्नवी का भी अध्ययन किया जो मोहब्बत पर इतना जोर देती है कि उसके अनुसार केवल मोहब्बत ही सच्चा मजहब है. 9/11 के बाद से अमेरिका में कुरान और मौलाना रूमी की मस्नवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई हैं.

इस तरह, 9/11 की भयावह घटना ने इस्लाम से घृणा करने वालों को क़ुरान पढ़ने और इस्लाम की मूल आत्मा को समझने की प्रेरणा दी और उनमें से कई ने इस्लाम को अपना भी लिया. यह एक जाना-माना मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसी चीज से हम जितनी अधिक घृणा करते हैं, हृदय परिवर्तन के बाद हम उससे उतना ही अधिक प्रेम करने लगते हैं. अगर मीडिया अपना काम ज़िम्मेदारी से करे-जैसी की उससे अपेक्षा की जाती है-तो दुनिया से धार्मिक कट्टरता लगभग ग़ायब हो जाएगी. मीडिया अक्सर लोगों को सही जानकारी देने की बजाए उन्हें भ्रमित करता है. धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले निहित स्वार्थी तत्व होते हैं और दुर्भाग्यवश, मुख्यधारा का मीडिया इन्हीं निहित स्वार्थी तत्वों के नियंत्रण में है.

अख़बारों में छपने वाली सभी ख़बरें झूठी नहीं होतीं. आख़िरकार, मीडिया को भी अपनी निष्पक्षता का भ्रम बनाए रखना होता है. आमजन मीडिया की ख़बरों पर सहज विश्वास करते हैं. वह मीडिया के शहंशाहों की निष्पक्षता पर विश्वास करते हैं. पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका, में मीडिया और सरकार की मिलीभगत रहती है. वहां का मीडिया सरकार की नीतियों के अनुरूप नए-नए शब्द गढ़ता है जिनका उपयोग शनै:-शनै: पूरे विश्व का मीडिया करने लगता है. एशिया व अफ्रीका के देशों का मीडिया काफी हद तक अमेरिकी मीडिया का पिछलग्गू है और जिन धर्मों या समुदायों को अमेरिकी मीडिया अपना निशाना बनाता है वे ही पूरी दुनिया के मीडिया के निशाने पर आ जाते हैं. सन् 1970 के दशक में, जब ईरान में क्रांति हुई थी, उस समय पश्चिमी मीडिया ने क्रांतिकारियों पर कट्टरपंथी का लेबिल चस्पा कर दिया था.

यह अमेरिकी मीडिया की एक कुटिल चाल थी जिसका उद्देश्य असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना था. ईरान की क्रांति के पीछे कई जटिल कारण थे. शाह के विरूद्ध आम जनता में बहुत रोष था. शाह एक तानाशाह था, जिसके गुप्तचर एजेटों ने सैकड़ों नवयुवकों को शारीरिक यातना देकर मौत के घाट उतार दिया था. शाह, मध्यपूर्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिट्ठू था और इस कारण ईरानी जनता अमेरिका से घृणा करती थी. इन सब तथ्यों को छुपाने के लिए ऐसा प्रचारित किया गया मानो ईरान की क्रांति के पीछे केवल धार्मिक कट्टरता थी. बहुत कम अख़बारों और पत्रिकाओं ने ईरान की क्रांति के असली कारणों की समग्र विवेचना की. इसका सबक यही है कि हमें अख़बारों और टी. वी. चैनलों पर आंख मूंदकर यक़ीन नहीं करना चाहिए.

पुरातनपंथी पुरोहित वर्ग, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान या ईसाई, कट्टरपंथी यूं ही नहीं होता. उसके सतही पागलपन के पीछे निश्चित उद्देश्य होते हैं. पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मुस्लिम पुरातनपंथी पुरोहित वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है परंतु उसका उद्देश्य धार्मिक कम है राजनैतिक ज़्यादा. पुरोहित वर्ग, शरीयत क़ानून इसलिए लागू करवाना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि इससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाएगा. अगर धर्मनिरपेक्ष क़ानून लागू किए जाते हैं तो सत्ता, धर्मनिरपेक्षता व प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले उदारवादी तबके के हाथ में रहेगी और उलेमा सत्ताविहीन रहेंगे. इसके विपरीत, यदि शरीयत क़ानून लागू किए जाते हैं तो शासन में धर्मनिरपेक्षता व प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले उदारवादी तबके की कोई भूमिका नहीं होगी और सत्ता का उपभोग उलेमा करेंगे.

इस तरह मुस्लिम दुनिया का उदारवादी-धर्मनिरपेक्ष तबका बहुत दुविधा में है. यदि वह उलेमा का साथ देता है तो भी उसकी मुसीबतें बढ़ती हैं और यदि वह इन उलेमा का विरोध करता है तब भी वह मुसीबत में फंसता है. अगर वह उलेमा का साथ देता है तो इससे पुरोहित वर्ग की ताक़त बढ़ती है, जैसा कि पाकिस्तान में जिया-उल-हक के शासनकाल में हुआ था. और अगर वह इन तत्वों का विरोध करता है तो ईरान जैसी क्रांति का ख़तरा उत्पन्न हो जाता है. एशिया और अफ्रीका के मुस्लिम देशों के शासक वर्ग के लिए एक तरफ़ कुआं है तो दूसरी तरफ़ खाई. और उनके सामने इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई आसान रास्ता नहीं है.

जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने भी यही समस्या थी. उन्होंने उलेमा के सामने झुकना बेहतर समझा और उनकी कई मांगें स्वीकार कर लीं. यहां तक कि उन्होंने अहमदिया समुदाय को ग़ैर-मुस्लिम घोषित कर दिया. इस सबसे पाकिस्तानी समाज में धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि हुई. इसी प्रकार नवाज शरीफ, मुशर्रफ़ और ज़रदारी ने भी उलेमा का इस्तेमाल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किया और अंतत: इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ी. स्पष्टत: हमें धार्मिक कट्टरता के बढ़ते प्रभाव के पीछे के कारणों का गहराई से अध्ययन करना होगा. धार्मिक कट्टरता के लिए केवल धर्म को ज़िम्मेदार ठहरा देने से काम नहीं चलेगा. ऐसा करने से तो परंपरावादी पुरोहित वर्ग और कुटिल राजनेताओं की बन आएगी. धार्मिक कट्टरता का अंत करने के लिए हमें उसकी जड़ों पर प्रहार करना होगा.

(लेखक मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म के संयोजक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

शराबखोरी गांव के लिए एक बड़ी समस्या थी. 70 के दशक के उत्तरार्द्ध में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि अब कुछ करना है.

गंगादेवी पल्ली में बही विकास की गंगा

ज़रूरी नहीं कि हमारे गांव का विकास तभी होगा, जब बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों की कृपादृष्टि हो. गांव का विकास ख़ुद गांव वालों के हाथ में है. सरकारी क़ानून ऐसे हैं, जिनके इस्तेमाल से हम अपने गांवों में विकास की गंगा बहा सकते हैं. ग्रामसभा एक ऐसी संस्था है, जिसकी नियमित बैठक से भ्रष्टाचार को करारा जवाब दिया जा सकता है और अपने गांव का संपूर्ण विकास किया जा सकता है.

- घरों से 100 प्रतिशत गृहकर इकट्ठा होता है
- 100 प्रतिशत साक्षरता है
- 100 प्रतिशत परिवार छोटी बचत अपनाते हैं
- बिजली बिल अदायगी 100 प्रतिशत है
- 100 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं
- समूचे गांव के लिए पेयजल है

शशि शेखर

आंध्र प्रदेश के वारंगल ज़िले की मचापुर ग्राम पंचायत का एक छोटा सा क्षेत्र था गंगादेवी पल्ली. ग्राम पंचायत से दूर और अलग होने के चलते विकास की हवा या कोई सरकारी योजना यहां के लोगों तक कभी नहीं पहुंची. बहुत सी चीजें बदल सकती थीं, लेकिन नहीं बदलीं, क्योंकि लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आएगा और उनकी ज़िंदगी संवारेगा, बदलाव की नई हवा लाएगा. क़रीब दो दशक पहले गंगादेवी पल्ली के लोगों ने तय किया कि वे ख़ुद एकजुट होंगे और बदलाव की हवा स्वयं लेकर आएंगे, जिसका वह अब तक सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे थे. आज गंगादेवी पल्ली एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र को आदर्श गांव बनाया जा सकता है.

आज गंगादेवी पल्ली में 100 प्रतिशत घरों से गृहकर इकट्ठा होता है, 100 प्रतिशत साक्षरता है, 100 प्रतिशत लोग परिवार नियोजन के साधन अपनाते हैं, 100 प्रतिशत परिवार छोटी बचत अपनाते हैं, बिजली बिल की अदायगी भी 100 प्रतिशत है, समूचे गांव के लिए पेयजल है और सभी बच्चे स्कूल जाते हैं. ज़ाहिर है, इस सबके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रामसभा की ही भूमिका थी. जनता की सहभागिता, नियमित बैठक और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की बदौलत यह गांव आज भारत के 6 लाख गांवों के लिए एक मिसाल बन चुका है.

शराबखोरी गंगादेवी पल्ली गांव में एक बड़ी समस्या थी. इस सामाजिक बुराई ने अन्य समस्याओं को भी और बढ़ा दिया था, जैसे घरेलू झगड़े, गुटों के झगड़े. 70 के दशक के उत्तरार्द्ध में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि अब कुछ करना है. इन लोगों ने गांव में लगातार बैठकें की कि शराब से क्या-क्या नुक़सान हो रहे हैं. 1982 तक गांव में पूर्णत: मद्य निषेध हो चुका था. 1994 में गंगादेवी पल्ली भी ग्राम पंचायत बन गया. पंचायती राज एक्ट की धारा 40 में ग्रामसभा के सहयोग से समिति बनाने की बात कही गई है. गंगादेवी पल्ली गांव की सफलता इन समितियों के गठन में पारदर्शिता और ईमानदारी में निहित है.

किसी नई योजना की घोषणा माइक द्वारा की जाती है. ग्रामसभा की बैठक होती है और समिति के सदस्य चुन लिए जाते हैं. समितियां गठित होने के बाद लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं. दरअसल, गांव के सभी मतदाता ग्रामसभा के स्वत: सदस्य होते हैं. ऊपर से इस गांव ने विभिन्न समितियां गठित करके और बेहतर काम किया. इससे फ़ायदा यह हुआ कि गांव के सभी लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुआ और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता बढ़ी. समितियां बनाने से गांव की अलग-अलग समस्याओं का कम समय में बेहतर समन्वय के साथ निराकरण संभव हो सका. मौजूदा सरपंच बताते हैं कि जनसहभागिता तभी से शुरू हो जाती है, जब लोग अपनी समस्याओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं. इसके बाद हम समस्या का हल ढूंढने और उसे लागू करने के लिए काम करते हैं. सरपंच प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं. इससे उनकी अनुपस्थिति में भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने पाती. लोग हर स्तर पर ग्राम पंचायत से जुड़े होते हैं. लिहाज़ा सभी मुद्दों और फ़ैसलों से वाक़िफ़ रहते हैं. इससे उत्तराधिकार की भावना और पारदर्शिता भी आती है. इसमें समूची प्रक्रिया स्वयं देखने को मिलती है. यह भी देखने को मिलता है कि किसी भी भ्रष्टाचार के बिना योजनाओं को लागू किया जा सकता है.

कोई भी फ़ैसला गांव के लोगों पर थोपा नहीं जाता. समस्याएं ग्रामसभा के सामने पेश की जाती हैं और उनका समाधान लोगों की तरफ़ से ही आ जाता है. इस प्रकार लोगों का अपना फ़ैसला होता है. गांव की सड़कों पर अंधेरा रहता था, लेकिन लोगों ने मिलकर पूरे गांव की सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था कर ली. गांव में पानी की बड़ी समस्या थी. इकलौता कुआं लगभग एक किलोमीटर दूर था. कुएं से पानी निकालने के लिए लोगों को सुबह तीन बजे से लाइन में खड़ा होना पड़ता था. गांव वालों ने एक संस्था की मदद से टंकी लगाने की योजना बनाई. 15 प्रतिशत ख़र्च स्वयं गांववालों ने उठाया. धन इकट्ठा करने के लिए लोगों के 18 समूह बनाए गए और महज़ 2 दिनों में 65 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गए. इसी तरह टंकी से आने वाले पानी के इस्तेमाल के लिए ग्रामसभा में विचार-विमर्श करके नियम बनाए गए, ताकि कोई पानी बर्बाद न करे और पूरा गांव नियमों को मानता है. गांव वाले जानते हैं कि अब उनके यहां पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इन नियमों का पालन इसलिए किया जाता है, ताकि कोई व्यर्थ ही पानी न बहाए. पानी के इस्तेमाल से जुड़े कुछ नियम हैं. जैसे टंकी का कनेक्शन केवल लोगों के घर के सामने लगेगा, हर घर आधा इंच का पाइप इस्तेमाल करेगा, हर नल ज़मीन से 4 फीट ऊपर होगा, नल के आसपास की जगह सूखी रखी जाएगी, किसी घर में पानी बहाया नहीं जाएगा, पौधों को भी पानी देने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल होगा, कोई पाइप लगाकर पानी नहीं देगा.

ग्रामसभा की बैठक में ही तय किया गया कि खुले में शौच जाने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि नियम-क़ानून में ऐसे जुर्माने का प्रावधान नहीं था, लेकिन यह ग्रामसभा की सामूहिक इच्छाशक्ति थी, जिसने जुर्माना लागू कराया और उसे वसूला भी. आज गांव का हर व्यक्ति अपने घर में बने शौचालय का इस्तेमाल कर रहा है.

इन नियमों को तोड़ने वाले व्यक्ति का पानी कनेक्शन सील कर दिया जाता है और 100 रुपये का जुर्माना भरने पर ही दोबारा बहाल किया जाता है. जल समिति की नियमित बैठक महीने के दूसरे शनिवार को होती है. अगर कोई विशेष बात या आपत्ति हो तो ग्रामसभा की बैठक में उस पर चर्चा होती है. लेकिन यह पानी पीने के लिए नहीं है. नल में आने वाला पानी फ्लोराइडयुक्त है, इसलिए पीने के काम में नहीं लिया जाता. पेयजल के लिए टाटा कंपनी के सहयोग से जल शुद्धि संयंत्र लगाया गया है. इससे शुद्ध होने वाला पानी एक रुपये प्रति कैन उपलब्ध कराया जाता है. इसकी पूरी व्यवस्था पंचायत की देखरेख में चलती है, लेकिन कोई भी फ़ैसला ग्रामसभा में ही लिया जाता है. इसलिए यह प्रक्रिया सही तरह से लागू की गई है और गांव का कोई भी व्यक्ति इसे हल्के में नहीं लेता.

ग्रामसभा की बैठक में ही तय किया गया कि खुले में शौच जाने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि नियम-क़ानून में ऐसे जुर्माने का प्रावधान नहीं था, लेकिन यह ग्रामसभा की सामूहिक इच्छाशक्ति थी, जिसने जुर्माना लागू कराया और उसे वसूला भी. आज गांव का हर व्यक्ति अपने घर में बने शौचालय का इस्तेमाल कर रहा है. ग्रामसभा ने गांव में हरियाली योजना लागू करने के लिए एक समिति बनाई. हर घर से कहा गया कि वह अपनी ज़मीन पर पेड़ लगाए. साथ ही सड़क के किनारे भी पेड़ लगाए गए. पेड़ों की सुरक्षा के लिए उनके सामने स्थित घरों को ज़िम्मेदार बनाया गया. अगर ये घर मंगलवार एवं शनिवार को इन वृक्षों को पानी नहीं देते तो उनके लिए पीने का पानी बंद करने का प्रावधान है. गांव के लोग अपने पशुओं को बांध कर रखते हैं, ताकि वे गांव में लगाए जा रहे पेड़-पौधे खा न जाएं. ग्रामसभा ने लोगों, विभिन्न समितियों और पंचायत की विभिन्न गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश तय कर रखे हैं. पहले लोग इनके पालन में आनाकानी करते थे, लेकिन जब उनकी समझ में आ गया कि ये उनके और पूरे गांव की भलाई के लिए हैं, तबसे दिशानिर्देशों का पालन उन्होंने अपनी आदत बना लिया.

गांव में 256 घर और दूसरे संस्थान हैं, इन सभी द्वारा ग्राम पंचायत को दिया जाने वाला कुल टैक्स 95,706 रुपये बनता है. यह रकम बिना नागा ग्राम पंचायत को अदा कर दी जाती है. जिस तरह विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लोगों ने पूरी ज़िम्मेदारी ली, उसे देखते हुए हो सकता है कि सरकारी संस्थाएं और बड़े औद्योगिक घराने भी ग्राम पंचायत को सहयोग देने के लिए आगे आएं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

लोकतंत्र की इस लड़ाई में भारत कहां है

मेघनाद देसाई

अमेरिका किसी भी हाल में नहीं जीत सकता. यदि वह किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल देता है तो उसकी निंदा होती है. लेकिन यदि, जैसा कि मिस्र में हो रहा है, अमेरिका ने जल्द ही हस्तक्षेप नहीं किया तो होस्नी मुबारक जैसे एक अलोकप्रिय तानाशाह को हटाना मुश्किल हो जाएगा. फिर इसके लिए भी अमेरिका को ही दोषी ठहराया जाएगा. लेकिन मिस्र का वर्तमान संकट एक महान क्षण है. 1922 में जबसे ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ, तबसे मध्य पूर्व कभी भी स्थिर या शांत नहीं रहा. सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान और फिलिस्तीन में भी इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभाव लीग ऑफ नेशंस ट्रस्टीज के रूप में रहा, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के राज्य एक लंबे समय तक एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभर सके. मिस्र एक शताब्दी से भी अधिक समय तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा. मिस्र के पास वह सब कुछ था, जो एक राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए जरूरी होता है.

आज 21वीं शताब्दी में, मध्य-पूर्व संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है. 9/11 की घटना ने अमेरिका को चिंतित किया और इससे उसका ध्यान इस क्षेत्र की ओर ज़्यादा बढ़ गया. अमेरिका का मुख्य हित इस बात में निहित है कि वह कैसे इजरायल की मदद कर सके और उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सके. एक लंबे समय तक सस्ते तेल के लालच में अमेरिका ने कई सारे ऐसे सुल्तानों और तानाशाहों को सहन किया, जिनका कोई सिद्धांत नहीं था, लेकिन 9/11 के बाद से स्थितियां बदलने लगीं. पहली और सबसे कड़ी प्रतिक्रिया इराक पर आक्रमण के रूप में दिखी. ईरान को घेरने में इराक ने अमेरिका का सहयोग किया. आधुनिक समय के 8 साल के खूनी संघर्ष के बाद भी गतिरोध बरकरार रहा. इसके बदले अमेरिका ने इराक को कुर्दों पर अत्याचार और शियाओं पर बमबारी के लिए माफ कर दिया, लेकिन कुवैत पर इराकी हमले के बाद सद्दाम हुसैन अमेरिका के लिए खलनायक बन गए. जब जॉर्ज बुश सत्ता में आए, उन्होंने स्थितियों को बदलने का फैसला किया. अब अमेरिका मध्य-पूर्व में लोकतंत्र की लहर फैलाना चाहता था, जैसा उसने 21वीं शताब्दी में लैटिन अमेरिका में किया था.

इस काम के लिए सबसे पहले इराक को चुना गया. इराक पर हमला हुआ, लेकिन 8 साल लगे. इराक में इस बीच दो चुनाव हुए और अब जाकर वहां दूसरी स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार का गठन संभव हुआ. असल में इराक का अंतिम चुनाव काफी गतिरोध के बीच संपन्न हुआ. छह महीने की सौदेबाज़ी के बाद नूरी अल मलिकी को प्रधानमंत्री बनाया गया. यह सारी प्रक्रिया करने के लिए बेहद धैर्य की ज़रूरत थी. आख़िरकार इराक में एक अंतरिम सरकार बनी और हालात सामन्य हुए. लेकिन मैं इस पूरे मामले को थोड़े अलग ढंग से देखता हूं. मैं सोचता हूं कि इराक ने ही ट्यूनीशिया के लोगों को अपने तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद बारी आई मिस्र की. इस बात की अधिक संभावना है कि मुबारक को जाना होगा. हम अभी जॉर्डन, सीरिया एवं सऊदी में भी ऐसे ही हालात देख सकते हैं. इनमें से किसी भी राजाओं के पास ऐसी कोई वैधता नहीं है, जो जनता से मिली हो. ये राजा या तो ब्रिटिश या फ्रेंच द्वारा स्थापित सत्ता का सुख भोग रहे हैं. लोकतंत्र का महत्व इनके लिए कुछ भी नहीं है. ईरान ने उस वक्त लोकतंत्र अपनाने का अवसर खो दिया, जब शाह का तख्ता उखाड़ फेंका गया था.

लोकतंत्र के लिए मुस्लिम जगत अनुपयुक्त है. इस तरह के कई सारे मिथक फैलाए गए हैं. तुर्की के मुस्लिम बहुल देश हैं और वहां लोकतंत्र भी है. इसका एक संविधान है, जो धर्मनिरपेक्षता पर ज़ोर देता है और तुर्की के सिद्धांतों का मार्गदर्शक है. इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी कुछ समय के लिए लोकतंत्र को देखा है.

लोकतंत्र के लिए मुस्लिम जगत अनुपयुक्त है. इस तरह के कई सारे मिथक फैलाए गए हैं. तुर्की के मुस्लिम बहुल देश हैं और वहां लोकतंत्र भी है. इसका एक संविधान है, जो धर्मनिरपेक्षता पर ज़ोर देता है और तुर्की के सिद्धांतों का मार्गदर्शक है. इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी कुछ समय के लिए लोकतंत्र को देखा है. कुछ साल पहले तक की बात रहने दें, तो बांग्लादेश में भी दशकों तक लोकतंत्र रहा है. इस हिसाब से देखें तो लोकतंत्र हर संस्कृति, हर समुदाय के लिए उपयुक्त है, कारगर है.

यह एक पेचीदा सवाल है कि जो भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर ख़ुद को गौरवांवित महसूस करता है, फिर भी वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए एक उत्साही समर्थक नहीं दिखता. मिस्र के मुद्दे पर भी भारत का मुंह अब तक बंद है. और, अब तो काफ़ी देर भी हो चुकी है.

feedback@chauthiduniya.com

आम आदमी और न्यायपालिका-2

रवि किशोर

लंबित मुकदमों की लंबी कतार और साथ ही जजों की ईमानदारी पर सवालिया निशान एक बहुत बड़ी समस्या है. ऐसा न हो कि इसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के इस अंतिम गढ़ की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए. अन्य दो संस्थाएं, विधायिका और नौकरशाही तो पहले से ही कमज़ोर हो चुकी हैं. आम आदमी का विश्वास अभी भी न्यायपालिका में है, लेकिन न्यायपालिका से जुड़े जो सवाल उठाए जा रहे हैं और जो समस्याएं दिख रही हैं, अगर उनका निपटारा जल्द से जल्द न किया गया तो मुझे आशंका है कि तब अराजकता जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. अभी हाल में सामने आया 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला लोगों के दिमाग़ में तरोताज़ा है. कुछ खास टेलीकॉम ऑपरेटरों को लाइसेंस दिए गए और उसके लिए तमाम नियम-क़ानूनों को धता बताया गया, वह भी मनमाने ढंग से और भेदभाव के साथ. कैग रिपोर्ट में जितनी बड़ी रकम का यह घोटाला बताया जा रहा है, वह चौंकाने वाली है.

सबसे ज़्यादा अफ़सोस की बात यह है कि उक्त लाइसेंस यूपीए-1 सरकार के दौरान जारी किए गए थे और इस बात के पुख्ता सबूत थे कि लाइसेंस देने में मनमानी हुई. इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी थी. बावजूद इसके, सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए उसी शख्स को दोबारा संचार मंत्री बनाया गया. यह सुप्रीमकोर्ट ही था, जिसने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया. उसके बाद सरकार जागी और उसने कुछ क़दम उठाए. हालांकि यह क़दम देर से उठाया गया था. सरकार अभी भी वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उनके पद पर बैठाए हुए है, जबकि क़ायदे से उनके ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाखिल होना चाहिए था.

इससे ज़्यादा दु:खद बात और क्या हो सकती है कि सरकार इन सब मामलों में अंतिम समय तक कोई क़दम उठाने से बचती रही. इतना ही नहीं, यह अभी भी दिख रहा है कि सरकार मानो इन सारी हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है. जब सरकार ने कोई क़दम उठाया तो वह महज दिखावा से अधिक कुछ नहीं लग रहा था. आख़िर सरकार ने कोई कठोर क़दम क्यों नहीं उठाया. आम आदमी को मनमोहन सिंह पर बहुत भरोसा था और यही वजह थी कि आम आदमी ने उनके लिए वोट किया और यूपीए को दूसरा मौका दिया, लेकिन यूपीए-2 लगभग सारे मोर्चों पर असफल साबित हुआ. ख़ासकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो वह बिल्कुल असहाय दिखा. महंगाई ने आम आदमी को कितना व्यथित किया, इसका जिक्र करने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है.

हम आम आदमी को न्यायपालिका की संपूर्ण व्यवस्था को समझाने में असफल रहे. हम उन्हें जजों की नियुक्ति से लेकर मामलों के निष्पादन तक से जुड़ी बातें नहीं समझा सके. मानो ये बातें किसी पर्दे में छुपाकर रखी गई हों. हम नहीं जानते कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है.

हम आम आदमी को न्यायपालिका की संपूर्ण व्यवस्था को समझाने में असफल रहे. हम उन्हें जजों की नियुक्ति से लेकर मामलों के निष्पादन तक से जुड़ी बातें नहीं समझा सके. मानो ये बातें किसी पर्दे में छुपाकर रखी गई हों. हम नहीं जानते कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है. ख़ासकर, उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर कोई तय मापदंड नहीं है. बहुत से मामलों में अकेले योग्यता या प्रतिभा जजों की नियुक्ति का आधार नहीं है. यही वजह है कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है. सबसे आश्चर्य की बात तो यह कि एक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ और मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीमकोर्ट नहीं भेजा गया. दूसरी ओर उनके ही एक कनिष्ठ साथी को सुप्रीमकोर्ट भेज दिया गया. इसी तरह उच्च न्यायालयों में भी नियुक्ति प्रक्रिया बेहद अपारदर्शी तरीके से की जाती है. लेकिन जब किसी जज की नियुक्ति हो जाती है, तब उसे उसके पद से हटाना असंभव नहीं, पर मुश्किल तो हो ही जाता है.

यही हाल मामलों के निष्पादन का भी है. सामान्यतय: एक आम याचिकाकर्ता को यह नहीं पता होता है कि मामलों को सूचीबद्ध कैसे किया जाता है और उनका निष्पादन कैसे होता है. ऐसे कई उदाहरण हैं कि कई पुराने मामले अभी तक लंबित हैं और कई नए मामलों का निष्पादन हो गया. लोग पूछते हैं कि सुप्रीमकोर्ट में कैसे दो उद्योगपति भाइयों का मामला तुरंत सूचीबद्ध हो जाता है और उसका निष्पादन भी हो जाता है. जबकि अन्य मामले, जिनमें पावरफुल लोग शामिल नहीं होते, लंबित रह जाते हैं. और हां, कुछ मामले तो ऐसे भी होते हैं, जिनकी सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होती है. पिछले दस सालों में न्यायपालिका की व्याख्या में भारी परिवर्तन दिखा है.

आज ज़रूरत एक ऐसी न्यायपालिका की है, जो संवेदनशील हो, जो गरीब आदमी के जीने के अधिकार को समझ सके, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की समस्याओं को समझ सके और उनके अधिकारों की रक्षा कर सके. अगर ऐसा होगा, तभी इस संस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकेगा. आज आम आदमी के दिमाग़ में एक धारणा बन चुकी है कि उच्च न्यायपालिका सिर्फ अमीरों और ताक़तवर लोगों के लिए है. ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले को समझा जाए और इसका समाधान निकाला जाए, ताकि न्यायपालिका के उच्च मानदंडों की रक्षा हो सके.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

धारदार लेखन

चौथी दुनिया के लेख और तेवर बहुत अच्छे लगे. देश में जन सरोकार की पत्रकारिता दिनोंदिन सिमट रही है. चौथी दुनिया जैसे समाचारपत्रों ने इसे बचाकर रखा है. बिहार में जो पत्रकारिता हो रही है, वह अपने आप सब बयान कर देती है.

-जेबा अख्तर, *रांची, झारखंड.*

मुसलमानों की लड़ाई

साक्षात्कार-मुसलमान अपनी लड़ाई भारतीय नागरिक बनकर लड़ें, अच्छा लगा. इस साक्षात्कार के ज़रिए जो भी बातें मदनी साहब ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की दशा के बारे में बताईं, वे पूरी तरह से ठीक हैं और जो समाधान बताया, वह भी सराहनीय है. हर समस्या से उभरने के लिए शिक्षा ही निदान है. मुसलमानों ने यदि शिक्षा हासिल करने का लक्ष्य बनाया तो उससे सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा. लेकिन सवाल उठता है कि क्या सभी मुसलमानों की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर है कि वे अपने बच्चों को तालीम दिला सकें? जिस तरह ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना चल रहा है, उस हिसाब से तो अच्छी तालीम की ही ज़रूरत है. अगर मुसलमान एक मयारी तालीम हासिल नहीं करते तो पढ़-लिखकर भी वे एक चपरासी की ही नौकरी हासिल कर पाएंगे और उसमें भी बहुत कंप्टीशन है. रही बात आला तालीम की, तो कुछ लोगों को छोड़कर बाकी मुसलमानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है.

-खादीजा सिद्दीका, *ई-मेल से.*

ज़िम्मेदार कौन?

हमारे देश के किसान पागल नहीं हैं और उन्हें आत्महत्या करने की ज़रूरत भी नहीं है. वास्तव में हमारे देश के नेता, मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं. उन्हीं की वजह से किसान आत्महत्या को मजबूर हुए और हो रहे हैं. सवाल यह है कि इन भ्रष्टाचारी नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अकेले मध्य प्रदेश के भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पास इतना पैसा है कि पूरे देश का क़र्ज़ आसानी से अदा किया जा सकता है.

-महेश चंद्र वर्मा, *इंदौर, मध्य प्रदेश.*

धंधे में सब शामिल

तस्करी की बात कोई आज की नहीं है. यह तो कई दशकों से हो रही है. चाहे कछुओं की हो या अन्य वन्यजीवों के अंगों की. सवाल यह है कि क्या इसकी ख़बर प्रशासन को नहीं होती. जब अख़बार और ग्रामीणों को इसकी जानकारी हो सकती है तो फिर प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगती. दरअसल सच्चाई यह है कि तस्करी के इस गोरखधंधे में सभी का कमीशन शामिल रहता है, इसी वजह से यह धंधा आज भी फल-फूल रहा है.

-रामकुमार, *दरभंगा, बिहार.*

बख्तावरपुर को सलाम

गांवों से जुड़े ज़्यादातर समाचार किसी न किसी समस्या या परेशानी वाले होते हैं, लेकिन बख्तावरपुर गांव के विकास की खबर पढ़कर जेहनी ख़ुशी हुई. जानकर अच्छा लगा कि देश के बदहाल गांवों के बीच कुछ गांव ऐसे भी हैं, जो अपने विकास का रास्ता ख़ुद बना रहे हैं. अगर हमें सीखना है तो इस गांव से सीखें कि हर बात पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराए बिना भी विकास हो सकता है. इस गांव के हर आदमी के जज़्बे को सलाम.

-भानु प्रताप, *कायमगंज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश.*

सरहद पार की प्रतिभाएं

पाकिस्तान के मशहूर शायर और नाटककार अमजद इस्लाम अमजद का साक्षात्कार पढ़ा. उनके बारे में कई दिलचस्प बातें जानने को मिलीं. सरहद पार की ऐसी प्रतिभाओं भारतीय मीडिया में जगह मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. लेकिन अब तक बहुत कम अख़बार मैंने देखे हैं, जो सरहद पार की हस्तियों से जनता को रूबरू कराते हैं. चौथी दुनिया का यह अंदाज़ अच्छा लगा.

-एस अकमल, *फरीदाबाद, हरियाणा.*

राजनीति का रंग

इसमें कोई शक़ नहीं है कि पूरे देश में अगर राजनीति की पाठशाला की बात की जाए तो उसमें बिहार का नाम सबसे पहले आएगा. लेख-कर्पूरी के बहाने पिछड़ा राग इस बात को पुख्ता करता है. किस तरह से नेता महापुरुषों की जयंतियों के बहाने अपने-अपने हितों को साधते हैं, यही सरोज सिंह ने बेहतर तरीक़े से बताया है. राजनीति का यही रंग है.

-महेश सिंह, *मधुबनी, बिहार.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह संसद के चेतने का समय है

संतोष भारतीय

संसद को चेतना होगा. देश की सारी संस्थाओं पर विशेषकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. इन्हें सवालों के दायरे में आने से बचाना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था पर विश्वास का संकट पैदा हो जाएगा. नए संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं. इसरो ने एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियम-क़ानून तोड़ डाले. प्रधानमंत्री पर एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इसरो प्रधानमंत्री के पास है. क्या प्रधानमंत्री के पास इतना भी समय नहीं है कि वह अपने अधीन आने वाले मंत्रालयों का कामकाज देख सकें, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के संज्ञान में यह मामला आया होता तो यह नहीं हो पाता.

आख़िर क्यों प्रधानमंत्री की दिलचस्पी अपनी नाक के नीचे होने वाले घपलों पर नहीं है. सीवीसी थॉमस का सवाल कांग्रेस की किरकिरी करा ही चुका है. कांग्रेस पहले ख़बर फैलाती है कि सीवीसी अपने आप इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन सीवीसी कहते हैं कि वह इस्तीफ़ा क्यों दें. वह सुप्रीम कोर्ट में भी आधिकारिक तौर पर अपने जवाब में कहते हैं कि जब सांसद उनसे ज़्यादा आरोपी हैं तो वह क्यों पद से हटें. क्या अब भी प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए कि ग़लती कहां हो रही है. पर एक बात जो सभी जानते थे, अब बिना हिचक बोली जा रही है.

विधायिका और कार्यपालिका आपस में लड़ रहे हैं. परिणामस्वरूप दोनों में कितनी गंदगी है, आरोपों के रूप में सामने आ रही है. पर नुक़सान तो संवैधानिक संस्थाओं का हो रहा है. उनकी स्थिति हास्यास्पद बनती जा रही है. जिस तरह प्रसार भारती के सीईओ लाली को राष्ट्रपति ने हटाया, ध्यान देने योग्य है. लाली ने भी प्रसार भारती की मर्यादा उछाली थी तथा उन्होंने सोचा था कि उन्हें हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वह कभी पूरी की ही नहीं जा सकेगी. अब वही पी जे थॉमस सोच रहे हैं और वैसा ही कर रहे हैं. संसद क्या करेगी और क्या सांसद देशहित को सर्वोपरि रखेंगे? लेकिन देशहित और पार्टी हित में अंतर्विरोध है. अक्सर पार्टी हित को देशहित मान लिया जाता है और कमोबेश सभी पार्टियां ऐसा ही कर रही हैं.

किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. वामपंथी पार्टियां नियंत्रित लोकतंत्र के दायरे में चलती हैं और ग़ैर वामपंथी पार्टियां परिवारों की संपत्तियां बन गई हैं. भाजपा में भी केंद्रीय स्तर पर इस बीमारी ने असर नहीं दिखाया है, पर पांच साल बाद यह पार्टी भी इसी बीमारी का शिकार दिखाई देगी, क्योंकि लगभग हर बड़े नेता का बेटा या बेटी राजनीति में या तो आ चुका है या आने वाला है. आना बुरा नहीं है, लेकिन बिना काम किए, बिना जनता के बीच गए, सीधे विधायक या सांसद बनना जनता के दर्द का मज़ाक उड़ाना है. कार्यकर्ता इसलिए निराश हो जाता है, क्योंकि तब ये अपने साथ अपने पुराने साथियों को भी राजनीति में घुसाने की कोशिश करते हैं. ऐसे साथी, जो पैसे वाले हैं और जिन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है. तो कार्यकर्ता करे क्या? वह राजनीति से निराश होने लगता है और तब राजनीति अपराधियों और ठेकेदारों के हाथों बंधक बन जाती है.

क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, दोनों इसके शिकार हैं. इसीलिए विधानसभाओं और लोकसभा में शोर तो होता है, लेकिन समस्याओं पर बात नहीं होती. जो बात उठा सकते हैं, वे खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनका नेतृत्व उनसे नाराज़ हो जाएगा. नेता सोचते हैं कि ज़्यादा बोलेंगे तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा और मिल भी गया तो साधन नहीं मिलेंगे. इस ऊहापोह ने भारत की संसदीय व्यवस्था को पंगु बनाने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. बजट सत्र कितने तमाशे दिखाने वाला है पता नहीं, पर तमाशे होंगे ज़रूर. ये तमाशे सत्ता और विपक्ष दोनों की मर्जी के ख़िलाफ़ होंगे. समस्याओं का दबाव और घपलों की पराकाष्ठा इतनी हो गई है कि यह भ्रष्ट व्यवस्था भी उसे सहन नहीं कर पा रही है. एक जुमला आम हो चला है कि खाओ ज़रूर, पर इतना तो मत खाओ. ए राजा, आदर्श, कॉमनवेल्थ, सेना और अब इसरो आदि. न जाने क्या-क्या.

इन घोटालों को कोई सामने नहीं लाया. कूड़ा जब ज़्यादा दिनों तक साफ नहीं होता है तो बदबू करने लगता है. भ्रष्ट व्यवस्था में भ्रष्टाचार की इतनी अधिकता हो गई है कि यह सड़ांध पैदा करने लगी है. अब लोग सोचने लगे हैं कि आख़िर हो तो क्या हो.

अब सांसद कहने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए, क्योंकि वह अब प्रधानमंत्री से भी इस्तीफ़ा मांगने लगा है. सभी का सभी पर अविश्वास है. किसी का किसी एक पर भी विश्वास नहीं है. यह स्थिति तो अपराधी समाज से भी बदतर है, क्योंकि अपराधी भी आपस में एक-दूसरे का विश्वास करते हैं. इस स्थिति में जनता कहां जाए? क्या किसान आत्महत्या करते रहें? नौजवान रोज़गार की तलाश में अपराधी बनने का रास्ता तलाशने लगें और मज़दूर नरेगा जैसे कार्यक्रम लागू होने के बाद भी भूखे मरते रहें?

जज खुलेआम भाषण में केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को मंत्री बने रहने पर अफसोस जता रहे हैं और सांसदों की स्थायी समिति सरकार से कहती है कि वह जजों को रोके, क्योंकि उनकी टिप्पणियां उन्हें असहज बना देती हैं. सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के कामकाज के तरीक़ों को लेकर टिप्पणियां करता है तथा अब सांसद कहने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए, क्योंकि वह अब प्रधानमंत्री से भी इस्तीफ़ा मांगने लगा है. सभी का सभी पर अविश्वास है. किसी का किसी एक पर भी विश्वास नहीं है. यह स्थिति तो अपराधी समाज से भी बदतर है, क्योंकि अपराधी भी आपस में एक-दूसरे का विश्वास करते हैं. इस स्थिति में जनता कहां जाए? क्या किसान आत्महत्या करते रहें? नौजवान रोज़गार की तलाश में अपराधी बनने का रास्ता तलाशने लगें और मज़दूर नरेगा जैसे कार्यक्रम लागू होने के बाद भी भूखे मरते रहें?

सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनाज सड़ाने की जगह बांटो, यह हमारा आदेश है, पर सरकार इंकार कर देती है और कहती है कि यह बाज़ार में हस्तक्षेप होगा. कोई ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से कहे कि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की धारा क्या जनता के लिए काम करने वालों पर ही इस्तेमाल होगी. सरकार खुलेआम उसकी राय की अवहेलना कर देती है तो क्यों कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ़ से नहीं करता. इतिहास का यह ऐसा मौक़ा है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बंटे नज़र नहीं आते, बल्कि वे संसद में हैं, सत्ता पक्ष में हैं और जो वहां नहीं है यानी जनता, वही इस पक्ष में है. संसद में जाने की इच्छा रखने वाले भी जनता के ख़िलाफ़ मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं. इसी में मीडिया के वे लोग भी हैं, जो संसद में पिछले दरवाजे से जाना चाहते हैं. गिरावट की पराकाष्ठा है. लगभग नंगे रूप में सामने आ चुका है कि मीडिया के तीन या चार लोग भाजपा और कांग्रेस के ज़रिए राज्यसभा में जाना चाहते हैं और इसके लिए वे अपने चैनल और अख़बार का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं. अब तो जनता के लिए मीडिया भी वैसा ही होता जा रहा है, जैसी संसद है. लेकिन इसमें भी एक आशा की किरण है.

सरकार जनता की समस्याएं न हल करे, उसके शांतिपूर्ण विरोध की आवाज़ न सुने और किसी प्रकार के विरोध को दबाने के लिए कमर कस ले, वहीं विपक्ष केवल संसद में अपनी आवाज़ उठा अपना कर्तव्य पूरा मान ले तो देश की जनता के एक साथ खड़े होने का समय नज़दीक आ रहा है, यह मानना चाहिए. हमारे यहां इजिप्ट नहीं होगा. उससे भयानक होगा. भारत की जनता को संघर्ष का दो बार का अनुभव है. एक बार गांधी के साथ अंग्रेजों से लड़ने का, दूसरी बार लोक नायक जयप्रकाश नारायण के साथ इंदिरा गांधी से लड़ने का. सरकार और विपक्ष को संभलना चाहिए. हमारी ख्वाहिश है कि देश को उतने बुरे दिन न देखने पड़ें.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

प्रजातंत्र के नाम पर चीरहरण

भारत ने पिछले दो दशकों में जिस ऊर्जा के साथ विकास किया है, सराहनीय है. लेकिन इस विकास का एक काला पक्ष भी है, जिसे न तो मीडिया देखना चाहता है और न ही देश का मध्यम वर्ग. इस विकास यात्रा के दौरान ग़रीबों की संख्या बढ़ती चली गई. भारत में विश्व के 25 फ़ीसदी ग़रीब लोग थे और आज यह प्रतिशत 39 हो गया है. विकास तो हुआ, लेकिन एक बहुत छोटे तबके का और जनता ग़रीब होती चली गई. दूसरे देशों ने भी तरक्की की, लेकिन वहां कहानी इतनी दु:खद नहीं है. चीन और ब्राज़ील में ग़रीबी घटी और विकास के साथ आम जनता को भी फ़ायदा हुआ. भारत की ग़रीबी रेखा यदि 1770 कैलोरी मान ली जाए (जो पहले शहरों के लिए 2100 और गांवों के लिए 2400 कैलोरी थी) तो भी तेंदुलकर कमीशन के अनुसार, भारत की ग़रीबी दर 37 फीसदी आंकी जा सकती है. एन सी सक्सेना की रिपोर्ट इस संख्या को और भी अधिक आंकती है. उसके अनुसार, भारत की 50 फीसदी जनता अति ग़रीब है. लगातार बढ़ती ग़रीबी ने भारत के राज्य तंत्र पर सवालिया निशान लगा दिया है.

भारत में रोज़गार बस एक फ़ीसदी की दर से बढ़ा है और उत्पादन सात से आठ फ़ीसदी की दर से. सार्वजनिक क्षेत्र में तंत्र सुधार के नाम पर बड़े पैमाने पर मजदूरों की छंटनी हुई, उसे निजी क्षेत्र में व्यवस्थित नहीं किया जा सका. संगठित क्षेत्र में नियमित रोज़गार न होने की वजह से अधिकतर कामगार असंगठित क्षेत्र में चले गए, जहां आय बहुत कम है. भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को गरीब विरोधी आईएमएफ और डब्लूटीओ के अनुरूप ढाल दिया.

जब यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रजातंत्र की लहर आई तो वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 2 हज़ार डॉलर थी (1991 की कीमत के पैमाने पर). भारत ने जब लोकतंत्र की अपनी यात्रा शुरू की तो देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय यूरोप के आंकड़े का पांचवां हिस्सा थी. भारत की यात्रा लंबी रही और बहुत अलग भी, लेकिन भारतीय राज्य तंत्र की सबसे बड़ी नाकामी रही देश से भुखमरी और ग़रीबी न हटा पाना. ऐसा नहीं कि देश के संविधान रचने वालों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है. इसीलिए उन्होंने समाजवाद को संविधान में जगह दी और कहा कि देश को इसके लिए काम करना होगा, लेकिन आज प्रजातांत्रिक तरीक़े से चुनी हुई सरकारों ने अपने राजनीतिक कर्तव्यों को छोड़कर देशवासियों को बाज़ार के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया है. एक मरीचिका फैलाई गई कि जो काम सरकार ग़रीबों के प्रति नहीं कर पाई, वह काम बाज़ारवाद करेगा और चुनिंदा पूंजीवादियों की बदौलत जो अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है, उसका फ़ायदा ग़रीबों तक भी पहुंचेगा, लेकिन ऐसा तो होना ही नहीं था.

राज्य बाज़ार के नियम कि अमीर ग़रीब से ज्यादा बलवान होता है, और प्रजातंत्र के नियम कि हर व्यक्ति एक वोट होता है, के बीच मध्यस्थ होता है. लेकिन भारतीय प्रजातंत्र ने अपनी इस ज़िम्मेदारी को छोड़ दिया है. बड़ी-बड़ी कंपनियां आज मशीनीकरण को बढ़ावा देती हैं, ताकि मजदूरों और कामगारों को उत्पादन तंत्र से कम किया या हटाया जा सके. इस वजह से बेरोज़गारी फैलती जा रही है. इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत में रोज़गार बस एक फ़ीसदी की दर से बढ़ा है और उत्पादन सात से आठ फ़ीसदी की दर से. सार्वजनिक क्षेत्र में तंत्र सुधार के नाम पर बड़े पैमाने पर मजदूरों की छंटनी हुई, उसे निजी क्षेत्र में व्यवस्थित नहीं किया जा सका. संगठित क्षेत्र में नियमित रोज़गार न होने की वजह से अधिकतर कामगार असंगठित क्षेत्र में चले गए, जहां आय बहुत कम है. भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को गरीब विरोधी आईएमएफ और डब्लूटीओ के अनुरूप ढाल दिया. हम एक ऐसे प्रजातंत्र में रहते हैं, जो यह सोचता है कि जो काम राज्य नहीं कर पाता, उसे निजी हाथों में दे दिया जाए. वह अपनी राजनीतिक अक्षमता और विफलता को छुपाना चाहता है और चाहता है कि जनता यह मान ले कि बाज़ार की आर्थिक सफलता देश की समस्याओं से निपट लेगी.

पूंजीवादी व्यवस्था ने ग़रीबों और देश के संसाधनों के दोहन का एक नया रास्ता खोला, जिसे एसईजेड और खनन का नाम दिया गया. इसका सबसे बड़ा पहलू है भूमि अधिग्रहण. आदिवासियों और किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी जा रही है. उड़ीसा में 84.5 फीसदी लोग ग़रीब हैं, जो भारतीय औसत से कहीं अधिक है. इसके विपरीत 1993-1994 से लेकर 2004-05 के बीच उत्खनन किए गए लोहे की कीमत में दस गुना, बाक्साइट और क्रोमाइट की कीमत में दो गुना और कोयले की कीमत में तीन गुना इजाफ़ा हुआ. देश की प्राकृतिक और खनिज संपदा में सबसे संपन्न तीन राज्यों में 86 फीसदी ज़िले झारखंड में, 90 फीसदी ज़िले उड़ीसा और 94 फीसदी जिले छत्तीसगढ़ में हैं, जो देश के सबसे ग़रीब ज़िलों में आते हैं. मधु कोड़ा ने दो साल से भी कम समय में 4 हज़ार करोड़ रुपये कमा लिए. कर्नाटक में रेड्डी बंधुओं ने सोचा कि बिचौलियों का काम करने से क्या फ़ायदा, इसलिए वे ख़ुद लोहे के खनन में लग गए. उद्योगपतियों को नाना प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं. उन्हें देश की प्राकृतिक धरोहर से लैस ज़मीनें दी जाती हैं और उन पर यह दायित्व नहीं डाला जाता कि वे अपने उत्पादन को भारत में बेचें. एसईजेड देश के भीतर एक ऐसे देश के रूप में उभरा है कि उसे घरेलू उद्योगों की सीमा से बाहर रख दिया गया है. उपनिवेशवाद को परंपरागत ढंग से प्राकृतिक संपदा और संसाधनों की लड़ाई माना जाता है, लेकिन यह परिभाषा भारत के भीतर बदल सी गई है. अब देश में आंतरिक उपनिवेशवाद चल रहा है.

अमित भादुड़ी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक जेएनयू के अवकाशप्राप्त प्रोफेसर हैं)

अध्ययन के दौरान कॉलेज छात्रों के 40 जोड़ों से बात की गई. इन जोड़ों ने एक-दूसरे के साथ चार-चार मिनट की स्पीड डेट की.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

बीपीएल चयन प्रक्रिया की जांच कैसे करें

जिस देश की 37 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी ग़रीब हो, वहां यह ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबी से जुड़ी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए, लेकिन व्यवहार में अब तक यही देखने को मिला है कि ग़रीबों के विकास के लिए बनाई गईं लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है. इस अंक में हम एक ऐसे ही मसले पर बात कर रहे हैं, जो सीधे-सीधे ग़रीबों के अधिकारों और उनके विकास से जुड़ा हुआ है यानी बीपीएल सूची, जिसके आधार पर ग़रीबों को बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है. ज़ाहिर है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोग किसी भी प्रकार अपना नाम बीपीएल सूची में शामिल करा लेते हैं. नतीजतन, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिन्हें वाकई सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं. इस अंक में एक ऐसा ही आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप बीपीएल सूची में पारदर्शिता बनाने का दबाव डाल सकते हैं और साथ ही सूची तैयार करते वक़्त इसमें होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ सकते हैं या उसका खुलासा कर सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए उत्साहित करेंगे.

पाठकों के पत्र

आवेदन लंबित है

मैंने एक आवेदन शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेजा था, जो अब तक लंबित पड़ा हुआ है. मेरी अपील पर भी कोई निर्णय नहीं आया है, जबकि काफी समय बीत चुका है. आख़िर मेरे मामले का निष्पादन क्यों नहीं हो रहा है?

–आर एच नकवी, *अमरोहा, उत्तर प्रदेश.*

अगर आपने तय समय सीमा के भीतर प्रथम अपील कर दी है और प्रथम अपील के निष्पादन के लिए तय समय सीमा के भीतर सुनवाई नहीं हुई है तो आपको सूचना का अधिकार क़ानून, 2005 के नियमों के तहत द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में कर देनी चाहिए.

समाजसेवी बनना चाहता हूं

सूचना अधिकार क़ानून को लेकर चौथी दुनिया की पहल जनता को बहुत जागरूक कर रही है. मैं भी एक समाज सेवक के रूप में काम करना चाहता हूं. कृपया मुझे इस संबंध में कुछ सलाह दें.

–रंजय कुमार, *नवादा, बिहार.*

यह ख़ुशी की बात है कि आप समाजसेवा करना चाहते हैं और वह भी आरटीआई का इस्तेमाल करके. आप अगर नियमित रूप से चौथी दुनिया में प्रकाशित इस स्तंभ को पढ़ते रहें तो आपको इस क़ानून से जुड़ी लगभग अधिकांश सामग्री मिल जाएगी. वैसे आप जब चाहें, हम आपको इस क़ानून से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर सलाह देने के लिए हमेशा तैयार हैं.

द्वितीय अपील के बाद क्या करूं

मेरे मामले में केंद्रीय सूचना आयोग ने जो निर्णय दिया, वह मेरे हिसाब से पक्षपातपूर्ण है. इसके अलावा पीआईओ ने आयोग के आदेश के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई. अगर द्वितीय अपील के बाद भी न्याय न मिले, तो क्या करना चाहिए?

–एस आर के मिश्रा, *धनबाद, बिहार.*

सूचना क़ानून के तहत अगर द्वितीय अपील/शिक़ायत के बाद भी सूचना नहीं मिलती है तो इसके बद सिर्फ़ न्यायालय का रास्ता ही बचता है. आप यदि उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और अगर निर्णय के बाद भी आपको सूचना नहीं मिली है, तो आप अपना यह मामला उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(बीपीएल के चयन के लिए किए गए सर्वे का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

.....ग्राम में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:

1. उपरोक्त गांव में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के कितने कार्डधारक हैं, उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
क. कार्डधारक का नाम
ख. पिता का नाम
ग. कार्ड संख्या
घ. कार्ड पर सदस्यों की संख्या (यूनिट)
2. उपरोक्त लोगों का ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस संबंध में कार्डधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उपरोक्त गांव में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों का सर्वेक्षण पिछली बार कब हुआ था? उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं, साथ ही सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम व पद बताएं?

4. ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के सर्वेक्षण केसमय चयन के लिए क्या मापदंड/मानक बनाए गए हैं? इस संबंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
5. उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरांत क्या कोई पुन: निरीक्षण (रिव्यू) किया गया? यदि हां, तो समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

6. पुन: निरीक्षण (रिव्यू) के संबंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

7. सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया? यदि हां, तो शिक़ायत पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
अपनी चिंताओं का समाधान करने के लिए आप कोई शार्टकट या तीसरा रास्ता भी अपनाने की सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे प्रयासों में आपको असफलता भी मिल सकती है. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन अपने सामान के प्रति सचेत रहें. शुभ समाचार मिलने से किसी गहरी चिंता का भी निवारण होगा. कामकाज और कारोबार में अच्छी प्रगति होने से धन लाभ के संकेत हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
ग्रहों की तेज चाल से अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है. दोस्त एवं परिवारीजनों के बीच आपकी पहुंच अच्छी होगी. जनसंपर्क के लिए भी समय ठीक है. वाणी में मधुरता बनाए रखें, अन्यथा विवाद उत्पन्न हो सकता है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. किसी अटके हुए काम को बनाने के लिए सप्ताह के मध्य का समय अनुकूल तो ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर प्रयास अभी पूरी तरह सार्थक नहीं हो पाएगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग हैं. जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें शुरुआती कठिनाई ज़रूर है, लेकिन यह भी सुनिश्चित है कि आगे चलकर आपको इच्छित लाभ हो सकता है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
संतान के संबंध में कोई सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. किसी अज्ञात व्यक्ति के ज़रिए आपको अच्छा लाभ या कार्यक्षेत्र में तरक़्क़ी करने का अवसर मिल सकता है. कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान के प्रति सचेत रहें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
समाज के कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. जिस व्यक्ति से आप समय लेकर मिलने जा रहे हैं, उसका अपनी जगह से नदारद रहना आपके लिए दु:ख का विषय होगा. आय पर नियंत्रण बनाए रखें. नेत्र संबंधी शिक़ायत हो सकती है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
जितना कठिन परिश्रम आजकल आप कर रहे हैं, उसके अनुरूप अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे हैं. घर में किसी बुज़ुर्ग से अनबन हो सकती है. अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो उसे टालने में ही भलाई है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
एक साधारण सी सफलता के चलते इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़-चढ़कर रहेगा. किसी विवाद या क़ानूनी मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
रचनात्मतक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. आपकी सूझबूझ-तरकीब इतनी सघन और अचूक है कि कहीं पर भी रुकावट आने की आशंका नहीं है. घर के कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. परिवारीजनों का सहयोग प्राप्त होगा. काफी लंबे समय से पड़ा हुआ कोई कार्य पूरा हो जाएगा. सप्ताहांत तक कहीं यात्रा या दावत में जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
समाज के कार्यों में व्यस्त होने के कारण परिवार को समय नहीं दे पाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में कुछ नया करने से पहले बुज़ुर्गों की सलाह अवश्य लें. संतान संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है. मनोरंजन के अवसर मिलेंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

यह रिश्ता क्या कहलाता है

वैसे तो रिश्तों को समझना आसान नहीं है. हर रिश्ते की अपनी अलग ही गणित होती है. फिर भी कुछ लोग हैं, जो इसकी पेचीदगियां सुलझाने के लिए शोध करते रहते हैं. अमेरिकी शोधकर्ता भी आजकल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. दो लोगों का रिश्ता कितने दिन चलेगा? किन लोगों का रिश्ता ज़्यादा लंबा चलेगा? शोधकर्ताओं ने इन सवालों के अनूठे जवाब खोजे हैं. उनके मुताबिक़, किसी दंपत्ति के संबंधों की सफलता का आधार उनके शब्द भी हो सकते हैं. कॉलेज छात्रों पर किए गए इस अध्ययन में पता चला कि जो जोड़े एक जैसी ज़ुबान बोलते हैं, उनके साथ बने रहने की संभावना दूसरे लोगों के मुक़ाबले चार गुना ज़्यादा होती है. इसकी वजह यह है कि उनके अंदर एक-दूसरे से मिलने की इच्छा औरों के मुक़ाबले ज़्यादा होती है. टेक्सस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स पेनेबेकर शोध करने वाली इस टीम के प्रमुख हैं. वह बताते हैं, हम लोगों के संबंधों का अनुमान ख़ुद उन लोगों से ज़्यादा लगा सकते हैं. साइकलॉजिकल साइंस नामक पत्रिका में छपे इस अध्ययन में शब्दों को आधार बनाया गया. शोधकर्ताओं ने ऐसे शब्दों पर ध्यान दिया, जो संज्ञा या क्रिया नहीं हैं. मसलन ए (a), बी (be), एनिथिंग (anything), दैट (that), विल (will), हिम (Him). पेनेबेकर बताते हैं कि ये बहुत सामाजिक शब्द हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए कुशलता की ज़रूरत होती है. वह कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी लेख के बारे में बात कर रहा हूं जो छपने वाला है, तो कुछ मिनटों बाद मैं उस लेख के लिए कोई शब्द प्रयोग करूंगा, जिससे हम दोनों समझ जाएंगे कि किस लेख की बात हो रही है.

अध्ययन के दौरान कॉलेज छात्रों के 40 जोड़ों से बात की गई. इन जोड़ों ने एक-दूसरे के साथ चार-चार मिनट की स्पीड डेट की. इनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया गया. पेनेबेकर के मुताबिक़ , पता चला कि ये चुनिंदा शब्द किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में बताने का बहुत सशक्त ज़रिया हैं. वह कहते हैं कि इन शब्दों के आधार पर आप बता सकते हैं कि दो लोग एक जैसी मानसिक स्थिति में हैं या नहीं.

अध्ययन के दूसरे हिस्से में पहले से ही डेटिंग कर रहे जोड़ों के बीच रोज़ाना भेजे जाने वाले संदेशों को आधार बनाया गया. संदेशों के ज़रिए हुई इस बातचीत का एक कंप्यूटर ने विश्लेषण किया और पता लगाया कि शब्दों और बातचीत का पैटर्न क्या रहा. पेनेबेकर बताते हैं कि इस विश्लेषण के आधार पर सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन से जोड़े ज़्यादा दिनों तक साथ रहेंगे. वह कहते हैं कि लिखने और बोलने के अंदाज़ से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि किसी संबंध के सफल होने की संभावना कितनी है. जितना लोगों का स्टाइल मिलता है, उनके रिश्ते की सफलता की संभावना उतनी ज़्यादा है. अध्ययन के तीन महीने बाद जब जांच की गई तो पता चला कि जिन जोड़ों का अंदाज़ एक जैसा था, उनमें से 80 फ़ीसदी अब भी डेटिंग कर रहे थे. इसके मुक़ाबले बातचीत के अलग-अलग अंदाज़ वाले जोड़ों की डेटिंग का प्रतिशत सिर्फ़ 54 था. पेनेबेकर कहते हैं कि ये शब्द और बातचीत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हैं, जिन पर लोग ध्यान ही नहीं देते. यानी आप फ़ैसला करते नहीं हैं, वह तो आपके मुंह से निकल जाता है. आप भी कभी ख़ुद पर इस शोध को लागू करके अपने रिश्तों की गणित समझने की कोशिश कीजिए.

कॉफी और महिलाएं

हमारे देश में हमेशा से यह बहस चली आ रही है कि पुरुष और महिलाओं में समानता क्यों नहीं है? वहीं कई प्रयोग भी हैं, जो इस असमानता को बढ़ावा देते हैं. अब कॉफी के प्रयोग को ही देखिए, जिसके तहत महिलाओं एवं पुरुषों पर कॉफी के असर की बात कही गई है. क्या कॉफी पीने से नींद ग़ायब हो जाती है, स्फूर्ति आ जाती है और दिमाग़ तेजी से काम करने लगता है? इसका जवाब हर व्यक्ति के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. चाय या कॉफी का असर किस पर कैसा होगा, इसका सटीक निष्कर्ष निकालना कठिन है, परंतु एक नए सर्वे से पता चला है कि कॉफी का असर महिलाओं के दिमाग़ पर जहां सकारात्मक रूप में पड़ता है, वहीं पुरुषों पर इसका नकारात्मक असर होता है. कैपेचीनो या एस्प्रेसो कॉफी पीने से महिलाओं का दिमाग़ तेजी से काम करने लगता है, वहीं पुरुषों के मामले में इसका उतना असर नहीं होता. मनोचिकित्सक लिंडसे क्लेर ने अपने अभ्यास में पाया कि तनाव के दौरान कॉफी पीने से पुरुषों के दिमाग़ पर कुछ ख़ास असर नहीं होता.

पश्चिमी देशों में कॉरपोरेट बैठकों से लेकर सैन्य योजनाएं बनाते समय तक कॉफी पीने का चलन आम है और उक्त सभी बैठकों में आम तौर पर पुरुष भाग लेते हैं. लिंडसे ने अपने अभ्यास के लिए कुछ स्वयंसेवकों को चुना और उन्हें पुरुष एवं महिला वर्ग में बांट दिया. इसके बाद दोनों को कुछ पहेलियां सुलझाने का कार्य दिया गया और साथ में कॉफी भी पीने को दी गई. माहौल को तनाव भरा बनाया गया. इस अभ्यास से पता चला कि कॉफी पीने के बाद पुरुषों को पहेलियां सुलझाने में 20 सेकेंड का अतिरिक्त समय लगा, जबकि महिलाओं ने वही पहेलियां सुलझाने में 100 सेकेंड तक कम समय लिया. ब्रिटेन में हर दिन 7 करोड़ कप कॉफी पी जाती है, भारत में भी चाय पीने का चलन अधिक है. अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय महिलाएं इतनी सुस्त क्यों होती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सात महीने तक बिना सरकार के रहने के बाद अब देश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के नेता झालानाथ खनाल के नेतृत्व में सरकार बन गई है.

नेपाल प्रधानमंत्री खनाल और चुनौतियां

राजीव रंजन तिवारी

देर आए, पर दुरुस्त नहीं. पड़ोसी देश नेपाल में सोलहवें प्रयास के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ. नए प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के लिए यह ताज कितना सुखद होगा, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुविधाओं का जंजाल दूर तक उनका पीछा करता रहेगा. उनके प्रधानमंत्री बनने के पीछे माओवादी नेता कमल दहल प्रचंड का विशेष योगदान रहा है, इसलिए उनकी यह नैतिक ज़िम्मेदारी होगी कि वह प्रचंड के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखें. राष्ट्रपति राम बरन यादव के साथ भी उन्हें तालमेल बैठाकर रखना होगा. सवाल तो यह है कि खनाल छत्तीस के रिश्ते वाले राम बरन यादव और कमल दहल प्रचंड से एक साथ अपने संबंध अनुकूल कैसे बनाए रख सकेंगे?

सात महीने तक बिना सरकार के रहने के बाद अब देश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के नेता झालानाथ खनाल के नेतृत्व में सरकार बन गई है. अब समझा जा रहा है कि नए गणतांत्रिक संविधान को लिखने का काम आगे बढ़ेगा, जिसकी दूसरी समय सीमा 28 मई को ख़त्म हो रही है. यानी इसमें क़रीब चार महीने बाक़ी हैं. बताते हैं कि 16 बार नाकाम रहने के बाद संविधान सभा प्रधानमंत्री चुनने में इसलिए कामयाब हो सकी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेता कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री का चुनाव न लड़ने का फ़ैसला किया. बहरहाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के बीच तालमेल हुआ और खनाल प्रधानमंत्री बन सके. जानकार बताते हैं कि इन दोनों दलों में इस मुद्दे पर समझौता हुआ है कि माओवादियों की जनमुक्ति सेना के तक़रीबन 20 हज़ार लड़ाकों के बारे में दोनों पक्ष कोई हितकारी रास्ता निकालें. इस पर खनाल ने भी यह घोषणा कर दी है कि 90 दिनों के भीतर इन लड़ाकों में से कुछ को नेपाली सेना में शामिल कर लिया जाएगा और बाक़ी का पुनर्वास होगा. दिलचस्प यह है कि प्रचंड वाली माओवादी पार्टी के अलावा देश की सभी पार्टियां इन लड़ाकों को सेना में लेने के विरुद्ध हैं. नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और सेना के एक धड़े को आशंका है कि इन लड़ाकों को लेने से सेना और अन्य सरकारी व्यवस्थाओं पर माओवादियों का शिकंजा कस सकता है. यहां तक कि राष्ट्रपति राम बरन यादव भी इसके पक्ष में नहीं हैं.

ग़ौरतलब है कि प्रचंड ने अपनी सरकार बनने के आठ महीने बाद बीते वर्ष मई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. दरअसल, माओवादी पार्टी की जनमुक्ति सेना के लड़ाकों को नेपाली सेना में भर्ती करने के मुद्दे पर उन्होंने सेना प्रमुख जनरल कटवाल को निकाल दिया था, लेकिन राष्ट्रपति राम बरन यादव ने प्रधानमंत्री के फ़ैसले को पलट कर जनरल कटवाल को बहाल कर दिया. इसी विवाद से ख़फ़ा होकर प्रचंड ने इस्तीफ़ा दे दिया. तबसे राष्ट्रपति राम बरन यादव और माओवादी नेता कमल दहल प्रचंड के बीच शीत युद्ध चल रहा है. यूं कहें कि दोनों एक–दूसरे के परस्पर विरोधी हैं. इतना ही नहीं, प्रचंड की पार्टी ने तो राष्ट्रपति के विरुद्ध आंदोलन तक चलाने की घोषणा कर रखी है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र से गणराज्य में तब्दील करने में कमल दहल प्रचंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने दस साल तक नेपाली सेना और पुलिस के ख़िलाफ़ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया. जनांदोलनों के ज्वार के बाद हुए चुनाव में उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर जीती और आख़िर संसद ने मई 2008 में राजा ज्ञानेंद्र को गद्दी से हटाकर 240 साल पुरानी राजशाही का अंत किया. तब नेपाल पहली बार एक गणराज्य बना.

ख़ैर, फ़िलहाल खनाल के सामने चार प्रमुख समस्याएं हैं, जिनसे निपटना उनके लिए चुनौती है. पहली यह कि उन्हें प्रधानमंत्री बनवाने में मदद करने वाले कमल दहल प्रचंड के साथ मधुर संबंध बनाए रखते हुए उनकी शर्तों को पूरा करना. दूसरी, यदि खनाल प्रचंड के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखते हुए उनकी शर्तें मानते हैं तो निश्चित रूप से वह राष्ट्रपति राम बरन यादव की आंखों की किरकिरी बन सकते हैं. यानी कहा जा सकता है कि यदि खनाल राम बरन यादव और कमल दहल प्रचंड से एक साथ दोस्ती निभाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है. खनाल को कोई एक रास्ता पकड़ना होगा. तीसरी अहम बात यह कि आगामी 28 मई से पहले देश का संविधान लिखवाना.

चौथी यह है कि खनाल भारत के साथ अपने संबंध प्रचंड के हिसाब से बनाए रखते हैं अथवा राष्ट्रपति राम बरन यादव के हिसाब से. दरअसल, प्रचंड पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह भारत की अपेक्षा चीन के ज़्यादा क़रीब हैं. हालांकि प्रचंड इन आरोपों का खंडन करते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों से उन पर भरोसा नहीं हो पाता. वहीं राष्ट्रपति राम बरन यादव भारत के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के न सिर्फ़ इच्छुक हैं, बल्कि वह भारत के साथ अपने बेहद नज़दीकी संबंधों की ओर भी इशारा करते हैं.

बहरहाल, उपरोक्त हालात से यह प्रतीत हो रहा है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री खनाल राष्ट्रपति राम बरन यादव और कमल दहल प्रचंड जैसे मज़बूत पाटों के बीच फंसे हुए हैं. यदि वह इनमें से किसी को भी नज़रअंदाज करते हैं तो उनके लिए समस्या पैदा हो जाएगी और दोनों से उनका एक साथ मधुर संबंध बनाए रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है. अब देखना यह है कि देशहित में खनाल नैतिक (प्रचंड) और संवैधानिक (राष्ट्रपति) में से किसका चुनाव करते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

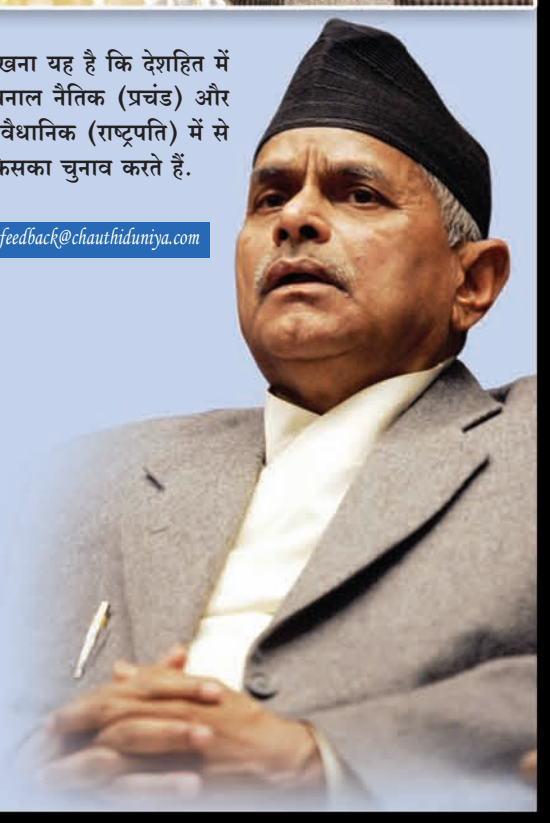

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

जब तक आदमी की सोच अपने तक सीमित रहेगी, तब तक वह दर्द, परेशानी और दुःख में रहेगा. जब दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेगा, कुछ करना शुरू करेगा, तब कोई और उसके लिए करेगा.

साई से नाता कैसे जोड़ें

ऑसिम खेत्रपाल

जीवन में हम बहुत से रिश्ते-नातों से घिरे रहते हैं. कई रिश्ते जन्म से बनते हैं और कई हम ख़ुद बनाते हैं. हमें लगता है कि ये रिश्ते हमने बनाए हैं, हमने चुने हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो हर रिश्ता चाहे जन्म से हो या बाद में बना हो, उस चैतन्य शक्ति से होता है जो ज्ञाश्वत है. मैं चैतन्य शक्ति जब अपने हर रिश्ते को चुनती हूं, बुनती हूं तो साई के साथ कैसे जोड़ूं अपना नाता? अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर रिश्ते में लेनदेन, आदान-प्रदान है. स्थूल वस्तुओं का ही नहीं, ऊर्जा का, भाव का. चाहे वह मां-बच्चे का हो, पति-पत्नी का हो, गुरु-शिष्य का हो. हम हर रिश्ते में जाने-अनजाने इसलिए आते हैं, क्योंकि यह सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है. उस रिश्ते की ऊर्जा या आदान-प्रदान के इस सिलसिले को हम कितना पवित्र, कितना शुद्ध रखते हैं, यह हम पर, हमारी सोच पर निर्भर करता है. एक समय की बात है. धर्मराज से एक आत्मा ने पूछा, आप किसी की क़िस्मत अच्छी और किसी की बुरी कैसे तय करते हो. धर्मराज ने कहा, मैं किसी की भी क़िस्मत नहीं तय करता, बल्कि हर आत्मा की सोच उसकी क़िस्मत तय करती है. वह आत्मा हैरान हो गई, तब धर्मराज उसे एक कमरे में ले गए. दरवाजा बाहर से बंद था. दरवाजा खोलने पर अंदर का नज़ारा बहुत भयावह था. बहुत से लोग उस कमरे में थे, जिनके हाथ-पैर बंधे थे. सब बहुत कमज़ोर थे और दर्द-भूख से छटपटा रहे थे. मजे कि बात यह कि सबके सामने स्वादिष्ट एवं गरमागरम खाने के, गर्म सूप के कटोरे रखे थे. हाथ से बंधे बड़े-बड़े चम्मच भी थे. सभी उस चम्मच से खाना भरते थे, लेकिन वे चम्मच इतने लंबे थे कि मुंह तक आते-आते खाना गिर पड़ता था. चम्मच पहुंच ही नहीं पाता था. यह नज़ारा देखकर वह आत्मा बहुत दुःखी हुई. उसके बाद धर्मराज उसे एक और कमरे में ले गए. दरवाजा खोलते ही वही नज़ारा था. लोगों के हाथ-पैर बंधे हुए थे. सामने खाना रखा था और उसी तरह हाथ पर बड़ा सा चम्मच बंधा था, लेकिन यहां लोग हष्ट-पुष्ट थे, हंसते-खेलते बेहद ख़ुश थे. तब उस आत्मा ने हैरानी से देखा. फ़र्क़ क्या था? माहौल में इतना फ़र्क़ कैसे? दरअसल, इस कमरे में हर आदमी एक-दूसरे को खिलाना सीख गया था. तब धर्मराज ने उस आत्मा को समझाया कि जब तक आदमी की सोच अपने तक सीमित रहेगी, तब तक वह दर्द, परेशानी और दुःख में रहेगा. जब दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेगा, कुछ करना शुरू करेगा, तब कोई और उसके लिए करेगा. समझने की बात यही है कि अगर हम इन रिश्ते-नातों में हैं तो कोई न कोई वजह है. अगर हम एक-दूसरे के लिए सोचना, करना शुरू कर पाएं, तो हमारे लिए कोई न कोई सोचना या करना ज़रूर शुरू करेगा.

एक समय की बात है. धर्मराज से एक आत्मा ने पूछा, आप किसी की क़िस्मत अच्छी और किसी की बुरी कैसे तय करते हो. धर्मराज ने कहा, मैं किसी की भी क़िस्मत नहीं तय करता, बल्कि हर आत्मा की सोच उसकी क़िस्मत तय करती है.

उसी तरह हमारा रिश्ता बाबा के साथ है. आज तक इस रिश्ते में भी हम देखते रहे कि हमें क्या मिलेगा. मांगते रहे, बाबा मेरे दुःख दूर करो, बाबा मेरा यह काम करा दो, बाबा मुझे सुख दिलवा दो, तब तक उतना ही मिलेगा, जो हम भोगते जाएंगे. लेकिन कभी आपने सोचा कि उनसे नाता जोड़ें प्रेम का, शांति का, आनंद का और उनसे रिश्ता जोड़ें अनुभव का, सर्व प्राप्तियों का, लेकिन प्राप्ति स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में....

ओम साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

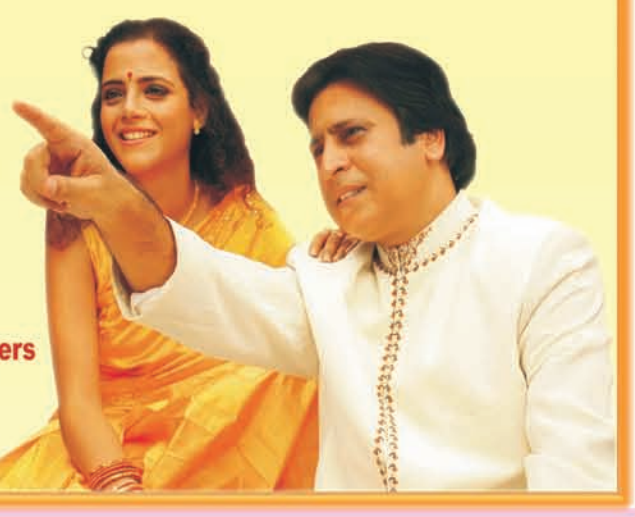

AUM Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

साई की महिमा के इस अंक में हम आपके लिए एक प्रतियोगिता लेकर आए हैं. इसमें हम आपसे बाबा के जीवन से जुड़ी पहेली पूछेंगे.

इस बार की पहेली का जवाब आपको साई सच्चरित्र से मिलेगा. बाबा के परम भक्त कीर्तनकार दासगणु कीर्तन के लिए सूट-बूट पहन कर जाते थे लेकिन बाबा कहने पर इन्होंने पूरा लिबास बदल लिया. आपको बताना है कि यह घटना साई सच्चरित्र के किस अध्याय में है.

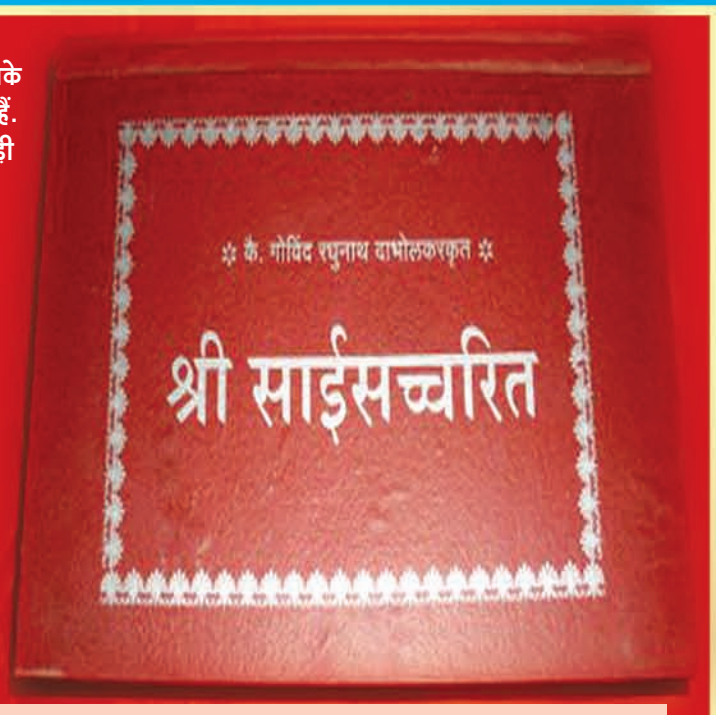

सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन,
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली- 110065
आप अपने जवाब info@ssbf.in भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. 011-46567351, 46567352

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साई बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ़ कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

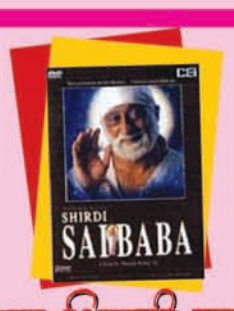

पहली बार शिरडी साई बाबा फीचर फिल्म अब कॉमिक्स के रूप में

क्रमशः

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

बिल्कुल अज़नबीपन महसूस नहीं होता. यहां आकर महसूस ही नहीं होता कि हम अपने देश से बाहर हैं.

पीछे हूं कहां आपसे रफ़्तार में देखें

पाकिस्तान की मशहूर शायरा फ़ातिमा हसन एक अखिल भारतीय मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए पिछले दिनों भारत में थीं. इस दौरान चौथी दुनिया (उर्दू) की संपादक वसीम राशिद ने उनसे एक लंबी बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:

मूल रूप से आप कहां से संबंध रखती हैं?

मेरा जन्म तो कराची में हुआ, लेकिन मेरे माता–पिता का संबंध उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले से है, जहां से वे पाकिस्तान चले गए थे. वहां आज भी मेरे मौसेरे भाई–बहन रहते हैं.

आप जब भी भारत आती हैं तो अपने रिश्तेदारों से मिलने ज़रूर जाती होंगी?

मेरे कई रिश्तेदार यहां दिल्ली में भी हैं. जितने मिलने वाले हैं, मैं तो सबको अपना रिश्तेदार समझती हूं. जगन्नाथ आज़ाद साहब जब भी पाकिस्तान जाते थे, मेरे घर ठहरते थे. मुशायरा ख़त्म होने पर लोग पूछते कि कहां जाना है तो वह कहते कि यहां मेरी बेटी फ़ातिमा रहती है. हमारा क़लम का रिश्ता भी ख़ून के रिश्तों की तरह स्थिर और पवित्र है.

आपकी शायरी की शुरुआत कहां से हुई?

मैं 1973 से निरंतर लिख रही हूं. 1973 में मेरा पहला संग्रह–बहते हुए फूल प्रकाशित हुआ. इसके बाद दूसरा संग्रह दस्तक से दर का फ़ासला आया और फिर तीसरा संग्रह यादें भी अब ख्वाब हुईं प्रकाशित हुआ. फिर इन तीनों संग्रहों को एक साथ प्रकाशित किया गया याद की बारिशें नाम से. एक संग्रह जल्द ही प्रकाशित होने वाला है. इसके अलावा कहानियों का एक संग्रह है–कहानियां गुम हो जाती हैं. फिर मैंने पीएचडी की. ज़ाहिदा ख़ातून शरवानिया अलीगढ़ में 1894 से 1922 तक थीं. वह पहली ऐसी शायरा थीं, जो पत्रिकाओं में छपती थीं. उन पर काम नहीं हुआ था, मैंने उन पर काम किया. वजह, उर्दू अदब के इतिहास में इतनी बड़ी महिला साहित्यकार का नाम नहीं आ रहा था. मैंने अलीगढ़ जाकर उनके ख़ानदान से मिलकर सामग्री एकत्र की और उन पर कराची यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, जिसे अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू पाकिस्तान ने प्रकाशित किया. मेरे परीक्षक ख़लीक अंजुम थे. उनके अलावा मैंने स्त्री आलोचना पर तीन किताबें संपादित की हैं, ख़ामोशी की आवाज़, दूसरी फ़ेमिनिज़्म और हम, तीसरी ब्लूचिस्तान का अदब और ख्वातीन. चौथी नसाई रद तश्कील है, जिसमें हमने यह देखा है कि मर्दों ने महिलाओं को किस तरह लिखा है. इसमें फ़हमीदा रियाज़ ने नून मीम राशिद, मैंने राजेंद्र सिंह बेदी, आसिफ़ फारुख़ी ने अली अब्बास हुसैनी और तनवीर अंजुम ने अज़ीज़ अहमद की तहरीरों का जायज़ा लिया. मेरी जो किताब इस वक़्त छपने को है, वह है किताब दोस्तां, जिसमें 25 लेख हैं. इनमें डॉक्टर असलम फ़ारुख़ी, ख़ालिदा हुसैन, फ़हमीदा रियाज़, किश्वर नाहीद, मुनीर नियाज़ी, अहमद फ़राज़ और कई साहित्यकारों एवं शायरों के लेखों को पढ़ा गया है.

मैं बहुत मज़बूत क़दमों से चली हूं, मैंने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया. मैं कभी रिएक्शन में नहीं पड़ी कि लोग मुझे क्या समझते हैं या क्या कहते हैं. मैंने शुरू में ही लिख दिया था कि जैसी भी हूं, अच्छी या बुरी, अपने लिए हूं. मैं ख़ुद को दूसरों की नज़र से नहीं देखती. यह समझती हूं कि जो ताक़त मैं इस तरह की बातों में लगाऊंगी, अगर उसे किसी सकारात्मक काम में लगाऊंगी तो उसका सकारात्मक परिणाम ही आएगा.

जब आपने शेर कहना शुरू किया तो क्या माहौल साज़गार था?

माहौल तो साज़गार होने लगा था. अदा जाफ़री आईं और उन्होंने एक औरत की हैसियत से अपनी निजी पहचान के साथ लिखा और सामने आईं. उनकी शायरी की सराहना हुई और उन्हें हाथोंहाथ लिया गया. इसके बाद ज़हरा निगाह, किश्वर नाहीद, फ़हमीदा रियाज़ और परवीन शाकिर आईं. लेकिन मेरे साथ 1970 के दशक में जो नस्ल आई, उसने इस बात पर विरोध किया कि उनके लेखों के वे अर्थ नहीं निकाले जा रहे हैं, जो वह लिख रही है. स्त्री आलोचना स्त्री चेतना पर ज़ोर देती है. हमने बाक़ायदा स्त्री आलोचना पर काम किया और बताया कि हमारे लेखों को किस तरह पढ़ा जाए. हमने कहा, आप जो समझ रहे हैं, हमने वह नहीं लिखा है और हम जो लिख रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं. आप सदियों से बने–बनाए सामाजिक मूल्यों के तहत हमारे किरदार को देखना चाहते हैं, उसी को मद्देनज़र रखकर हमारे लेखों को पढ़ते हैं, औरत या तो आपको फ़रिश्ता नज़र आती है या बदमाश.

अगर औरत किसी मुक़ाम पर पहुंचती है तो उसे तरह–तरह की बातों का सामना करना पड़ता है. क्या आपको भी उन्हीं हालात से लड़ना पड़ा?

मैं बहुत मज़बूत क़दमों से चली हूं, मैंने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया. मैं कभी रिएक्शन में नहीं पड़ी कि लोग मुझे क्या समझते हैं या क्या कहते हैं. मैंने शुरू में ही लिख दिया था कि जैसी भी हूं, अच्छी या बुरी, अपने लिए हूं. मैं ख़ुद को दूसरों की नज़र से नहीं देखती. यह समझती हूं कि जो ताक़त मैं इस तरह की बातों में लगाऊंगी, अगर उसे किसी सकारात्मक काम में लगाऊंगी तो उसका सकारात्मक परिणाम ही आएगा. आपको आगे बढ़ने के लिए मज़बूत क़दमों के साथ आगे की सोचकर चलना होगा. रुकावटें तो आती हैं, हर कामयाब आदमी को रुकावटें झेलनी पड़ती हैं. मैंने जो लिखा, वह छपवाती रही. इससे मेरा कोई वास्ता नहीं रहा कि कौन मुझे मुशायरे में बुला रहा है और कौन टीवी पर. काम पब्लिसिटी से ज़्यादा होना चाहिए. कुछ चीज़ें अपने ज़हन में बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए. एक तो यह कि हम शो बिज़ लिखने वाले नहीं हैं कि हम अपना स्कैंडल बनवाएं और फिर उससे मशहूर हों. तो फिर हमारा काम पीछे रह जाएगा. हम राजनीतिज्ञ भी नहीं हैं, हम बुद्धिजीवी हैं. हमें बुद्धिजीवी का किरदार अदा करना चाहिए. राजनीतिज्ञ हमसे इशारे लें, हम उनके इशारों पर न चलें.

महिला साहित्यकारों के बारे में आपका क्या कहना है?

यह महिलाओं का संकल्प है. जहां कहीं भी ग़लत व्यवहार हो रहा है, वहां अगर प्रतिरोध करें तो महिलाएं करें. पाकिस्तान के साथ भारत में भी महिलाएं गंभीर लिख रही हैं. जब वे हमसे मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब एक ही विषय पर सोच रहे हैं.

हमारे पाठकों के लिए कुछ सुनाइए?

आंखों में न ज़ुल्फ़ों में न रुख़सार में देखें,
मुझे मेरी दानिश मेरी उफ़कार में देखें.
सौरंग मज़ामीन हैं जब लिखने पर आऊं,गुलदस्ता–ए–माना मेरे अश्आर में देखें.
पूरी न अधूरी हों न कमतर हों न बरतर,
इंसान हूं इंसान के मियार में देखें.
रखे हैं क़दम मैंने भी तारों की ज़मीं पर,
पीछे हूं कहां आपसे, रफ़्तार में देखें.

जब आप भारत आती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है?

बिल्कुल अजनबीपन महसूस नहीं होता. यहां आकर महसूस ही नहीं होता कि हम अपने देश से बाहर हैं. बाहर निकलने में सबसे बड़ी परेशानी ज़ुबान की आती है या फिर खाने–पीने की, लेकिन यहां तो ज़ुबान एक है, लिबास एक है और रिवायतें भी एक हैं.

इस समय पाकिस्तान में जो शायरी हो रही है, उसका ख़ास विषय क्या है?

शायरी के लिए कोई ख़ास विषय तो होता नहीं है. शायरी तो इंसान का ऐसा इज़हार है, जिसमें हर विषय समां जाता है. इसीलिए शायरी में बड़ी गुंजाइश होती है. आंतरिक घटनाएं हों, बाहरी हालात हों, सियासत हो, मौसम, हुस्न, इश्क या प्राकृतिक दृश्य, सब कुछ इसमें आ जाता है. शायरी न नारेबाज़ी है और न ही पत्रकारिता. शायरी में सबसे बड़ी चीज़ शायरी होना चाहिए. शायर और साहित्यकार इतना संवेदनशील होता है कि वह जो कुछ लिखता है, उस पर आंतरिक घटनाओं के प्रभाव ज़रूर पड़ते हैं. इसलिए उसका लिखा हुआ आगे चलकर इतिहास का हिस्सा बन जाता है.

आप भारत–पाक के मुशायरों में क्या बुनियादी फ़र्क़ महसूस करती हैं?

मैं बहुत ज़्यादा मुशायरों में शरीक नहीं होती, उन्हीं मुशायरों में जाती हूं, जो कांफ्रेंस के साथ होते हैं. हर ज़माने में दो तरह का अदब लिखा जाता है, एक पॉपुलर अदब कहलाता है, जो सभी को अपील करता है और पसंद आता है. दूसरे अदब में एक सतह होती है, उसमें फ़िक्र होती है, उसे अदब–ए–आलिया कहते हैं. इस तरह पाकिस्तान में भी दो तरह के मुशायरे हो रहे हैं.

भारतीय मुशायरे में आपकी पसंद कौन–कौन हैं?

अभी मुझे कुछ नाम याद आते हैं, मसलन दाराबानो वफ़ा, साजिदा ज़ैदी, ज़ाहिदा ज़ैदी, शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा, मलिका नसीम, शहनाज़ नबी और शबनम ईशाई आदि.

किजाशी में 2.4 लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन लगाया गया है. साथ ही इसमें स्टाइल, सेफ्टी और कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है.

सबसे तेज कंप्यूटर

सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग निर्धारित करने वाली टेन्नेसी प्रयोगशाला के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कहा है कि चीन द्वारा बनाया गया यह कंप्यूटर शीर्ष स्थान पर रहने का हकदार है.

तेज रफ्तार कारों और बाइक्स के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर के बारे में. दुनिया के इस सबसे तेज रफ्तार कंप्यूटर का नाम है तिआन्हे-1-ए सुपर कंप्यूटर और इसे तैयार किया है चीन के वैज्ञानिकों ने. यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के टेन्नेसी की प्रयोगशाला में मौजूद सुपर कंप्यूटर से 1.4 गुना अधिक तेज गति से काम करता है. यह कंप्यूटर प्रति सेकेंड 2.67 क्वाड्रिलियंस गणनाएं कर सकता है. ख़ास बात यह है कि अमेरिका ने भी यह मान लिया है कि चीन का नया सुपर कंप्यूटर ही दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है. सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग निर्धारित करने वाली टेन्नेसी प्रयोगशाला के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कहा है कि चीन द्वारा बनाया गया यह कंप्यूटर शीर्ष स्थान पर रहने का हकदार है. आपको बता दें कि दुनिया का दूसरा सबसे फास्ट कंप्यूटर अमेरिका में बना क्रे एक्स टी-5 जगुआर है. जगुआर प्रति सेकेंड 1.75 क्वाड्रिलियंस गणनाएं कर सकता है.

कार ऑडियो सिस्टम की नई रेंज

कार ऑडियो सेगमेंट में भारत एक बढ़ता हुआ बाज़ार है. इसी को देखते हुए पायनियर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ने डीईएच और एवीएच रेंज के कार ऑडियो सिस्टम बाज़ार में उतारे हैं. कंपनी ने इनकी क़ीमत 3500-32,000 रुपये तक रखी है. नए कार ऑडियो सिस्टम में मोबाइल फोन के नंबरों को स्टोर किया जा सकता है, जिससे वाहन चालक ब्लूटूथ एक्टीवेट करके फोन को बिना कान पर लगाए बात कर सकता है. डीईएच रेंज में सीडी रिसीवर मल्टी कलर को ड्राइवर के मूड और कार के इंटीरियर के हिसाब से उपलब्ध कराएगा. यूजर बैंड ग्राफिक ईक्यू से साउंड को ट्यून कर सकता है. आगे-पीछे की सीटों पर बैठे व्यक्ति अपनी-अपनी पसंद का संगीत सुन सकेंगे. लांच के मौक़े पर पायनियर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी तोमोयुकी कोमीया ने कहा कि कार ऑडियो सेगमेंट में भारत एक प्रमुख बाार है. इस ऑडियो सिस्टम को विभिन्न कार निर्माता कंपनियां अपनी कारों में इस्तेमाल कर सकती हैं. इस ऑडियो सिस्टम के माध्यम से कंपनी अपने अंतरराष्ट्रीय अनुभव भारतीय ग्राहकों के साथ बांटना चाहती है. कोमीया ने कहा कि पायनियर का ट्रेडमार्क कनेक्टिविटी, क्वालिटी और सुलभता का प्रतीक है.

किजाशी का इंतज़ार ख़त्म

देश की जानी-मानी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने प्रीमियम कारों के सेग्मेंट में अपनी पकड़ बनाने के इरादे से अपनी प्रीमियम सेडान कार मारुति सुजुकी किज़ाशी लांच कर दी. कंपनी को उम्मीद है कि बेहतरीन ख़ूबियों से लैस यह कार भारतीय ग्राहकों को पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगी. किजाशी में 2.4 लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन लगाया गया है. साथ ही इसमें स्टाइल, सेफ्टी और कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है. अपने दमदार इंजन के बूते किजाशी महज़ 8 सेकेंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है. मारुति किज़ाशी में एयरबैग, क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम और पार्किंग सेंसर भी हैं. साथ ही रिमोट के ज़रिए सेंट्रल लॉक सिस्टम भी है. ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आरामदायक सफर के लिए इस लग्जरी सेडान में पूरा इंतज़ाम है. किजाशी में सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प मौजूद है. इसमें 18 इंच के एल्युमिनियम व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन कम होने के कारण रफ्तार में मदद मिलती है, ज़्यादा चौड़ाई के चलते सड़कों पर ग्रिप भी काफी बेहतर मिलता है. भारत में डी सेगमेंट की बात की जाए तो इसमें विभिन्न कंपनियों की 12 कारें पहले से ही मौजूद हैं. भारत में किज़ाशी का तगड़ा मुक़ाबला होंडा की सिविक, वोल्क्सवैगन जेत्ता, टोयोटा कोरोल और स्कोडा लौरा से होगा. इसी सेगमेंट में शेवरले की ऑप्ट्रा और क्रूज भी मौजूद हैं. इनमें से ख़ासतौर पर क्रूज से किजाशी को चुनौती मिल सकती है. किजाशी को दो मॉडलों में पेश किया गया है, मैनुअल ट्रांसमिशन और कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमीशन. मैनुअल ट्रांसमिशन की क़ीमत 16,50,000 रुपये रखी गई है, जबकि कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन की क़ीमत 17,50,000 रुपये. कार की डिलीवरी मार्च महीने से मिलेगी, इसे 50 हजार रुपये देकर बुक किया जा सकता है. किजाशी में की-लैस एंट्री है. कंपनी उम्मीद कर रही है कि कम क़ीमत में बेहतरीन ख़ूबियों केचलते भारतीय ग्राहकों को यह कार बेहद पसंद आएगी.

ख़ास स्मार्ट फोन

सस्ते सामान की दौड़ में चीनी सबसे आगे रहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने सारी दुनिया के बाज़ारों पर क़ब्ज़ा जमा लिया है. दुनिया भर के बड़े-बड़े स्टोर चीन निर्मित सामान से भरे रहते हैं. अगर मोबाइल फोन की बात करें तो चीनियों का कोई मुक़ाबला ही नहीं है. चीन की एक नामी टेलीकॉम कंपनी हुआवेई भारत में अपना नया स्मार्ट फोन उतारने की तैयारी में है. उसका दावा है कि यह फोन चीन में बने फोनों के बारे में लोगों की धारणा बदल देगा. कंपनी का यह फोन है आयडिओस एक्स-5 और यह एंड्रॉयड 2.2 फोन है. इस टच स्क्रीन फोन की ख़ासियत इसकी ऑडियो क्वालिटी है, क्योंकि इसमें डोल्बी मोबाइल साउंड है. इसमें 5 मेगा पिक्सल कैमरा है और यह 800 एमएचजेड प्रोसेसर है. कंपनी ने ख़ूबसूरती के लिए इसे बेहद पतला बनाया है. इसकी ख़ासियत यह है कि इसमें आप अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट नंबर रख सकते हैं. इसी तरह कॉल रिकॉर्ड रखने के लिए भी इसमें अनलिमिटेड जगह है. भारत में इसकी क़ीमत संभवत: 16 हज़ार रुपये होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

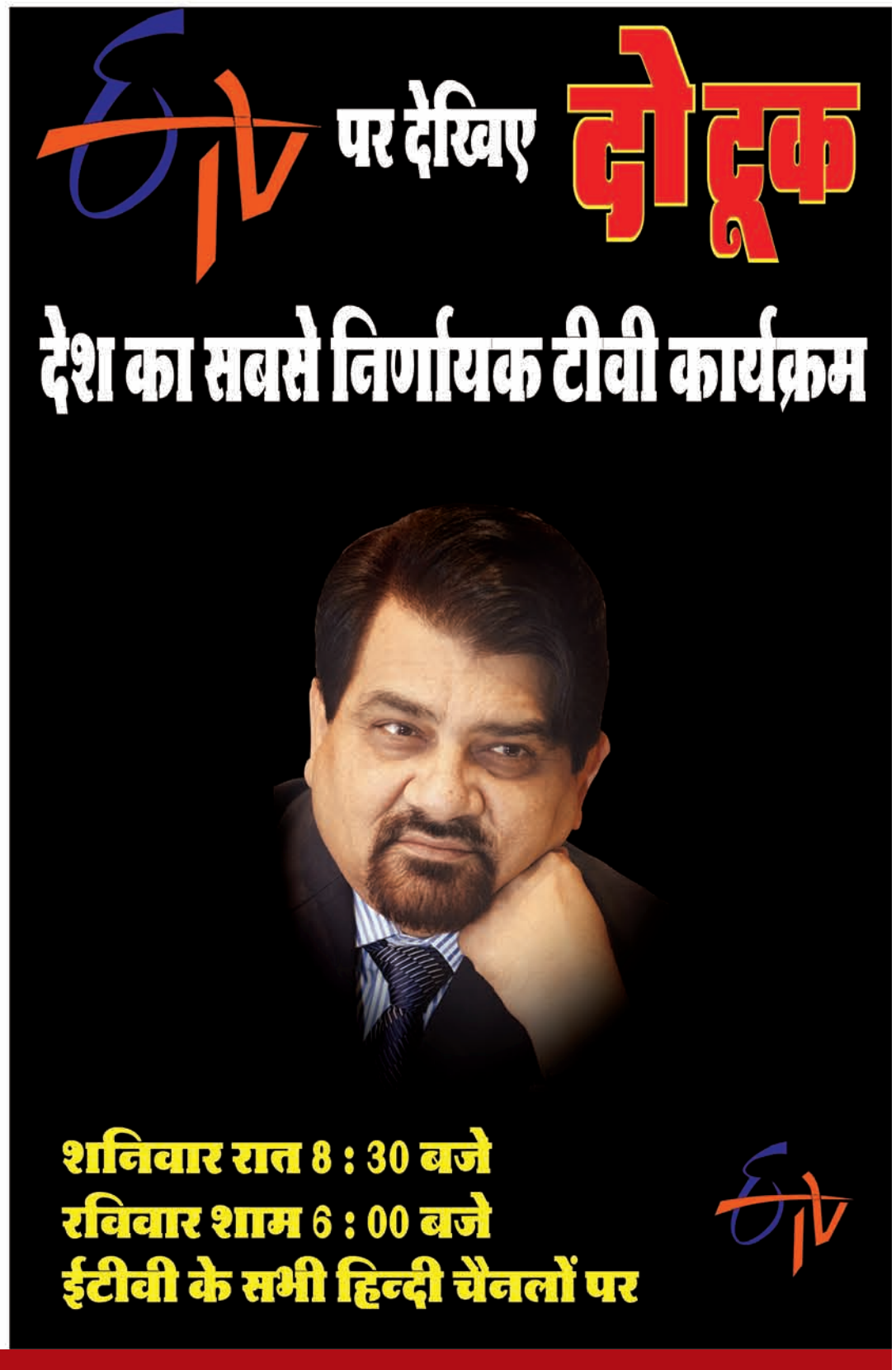

2011 का क्रिकेट विश्व कप दसवां क्रिकेट विश्व कप है. इसका आयोजन भारत सहित श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा है.

विश्व कप 2011

- 2 अप्रैल तक चलेगा क्रिकेट का महाकुंभ
- श्रीलंका और बांग्लादेश हैं मेज़बान देश
- कुल 14 देशों की टीमें ले रही हैं हिस्सा
- 13 शहरों में खेले जाएंगे 43 मैच
- मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल
- पुरस्कार राशि है 18 करोड़

विश्व कप का आग़ाज़ हो चुका है. ज़ाहिर है आपके दिलों की धड़कने बढ़ गई होंगी. ऐसे में सबसे ज़्यादा चिंता इसकी होती है कि कौन सा मैच कब और कहां होने वाला है, इसकी सूचना कहां से मिलेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए खेल दुनिया के इस कॉलम में हम आपके लिए विश्व कप का कैलेंडर प्रकाशित कर रहे हैं. 2011 का विश्व कप दसवां क्रिकेट विश्व कप है. इसका आयोजन भारत सहित श्रीलंका और बंगलादेश में आयोजित किया जा रहा है. पहली बार बंगलादेश को विश्व कप की मेजबानी करने का मौक़ा मिल रहा है. इससे पहले भारतीय उपमहाद्धीप में 1987 और 1996 में भी विश्व कप आयोजित हो चुका है. पहले कहा जा रहा था कि 2011 का क्रिकेट विश्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड द्वारा आयोजित किया जाएगा. लेकिन एशियाई देशों ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की बोली को 3 के मुक़ाबले 7 वोटों से हरा दिया. पहले पाकिस्तान भी मेजबान देश में शामिल था, लेकिन 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर लाहौर में हुए हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया. इतना ही नहीं, आईसीसी ने 2011 विश्व कप की आयोजन समिति के मुख्यालय को लाहौर से हटा मुंबई कर दिया. इस बार का वर्ल्ड कप थोड़ा अलग होगा. पिछले बार के विश्व कप की तुलना में दो टीम कम भाग लेंगी, वहीं इस बार के विश्व कप में सुपर सिक्स का प्रारूप भी हटा लिया गया है. विश्व कप में 14 टीम भाग ले रही हैं. इन्हें दो ग्रुपों में रखा गया है. पहला चरण राउंड रॉबिन होगा. जिसके तहत सभी टीमें अपने-अपने ग्रुप में एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक-एक मैच खेलेंगी. दूसरा दौर क्वार्टर फाइनल होगा, जिसमें पहले चरण के मुक़ाबलों के आधार पर प्रत्येक ग्रुप से चार-चार टीमें जाएंगी. क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल. अंत के तीनों दौर नॉकआउट प्रारूप पर खेले जाएंगे. वर्ल्ड कप 2011 का शुभंकर हाथी का बच्चा स्टंपी है जिसकी उम्र 10 साल है. स्टंपी उत्साह और युवा जज़्बे का प्रतीक है. कुल मिलाकर, इस वर्ल्ड कप में आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया गया है.

कब कौन सा मैच

टीमें	तारीख़	दिन	भारतीय समयानुसार	मैदान
भारत बनाम बांग्लादेश	19/02/2011	शनिवार	1400 बजे	शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर
केन्या बनाम न्यूज़ीलैंड	20/02/2011	रविवार	09:30 बजे	एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
श्रीलंका बनाम कनाडा	20/02/2011	रविवार	1430 बजे	महिंद राजपक्षे स्टेडियम, हमबंतोहता
आस्ट्रेलिया बनाम जिंबाब्वे	21/02/2011	सोमवार	1430 बजे	सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद
इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड	22/02/2011	मंगलवार	1430 बजे	विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम, नागपुर
केन्या बनाम पाकिस्तान	23/02/2011	बुधवार	1430 बजे	महिंद राजपक्षे स्टेडियम, हमबंतोहता
द. अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज	24/02/2011	गुरुवार	1430 बजे	फिरोजशाह कोटला, दिल्ली
बांग्लादेश बनाम आयरलैंड	25/02/2011	शुक्रवार	0900 बजे	शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर
आस्ट्रेलिया बनाम न्यूज़ीलैंड	25/02/2011	शुक्रवार	1430 बजे	विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम, नागपुर
श्रीलंका बनाम पाकिस्तान	26/02/2011	शनिवार	1430 बजे	आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
भारत बनाम इंग्लैंड	27/02/2011	रविवार	1430 बजे	ईडन गार्डंस,कोलकाता
कनाडा बनाम जिंबाब्वे	28/02/2011	सोमवार	0930 बजे	विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम, नागपुर
नीदरलैंड बनाम वेस्टइंडीज	28/02/2011	सोमवार	1430 बजे	फ़िरोज़शाह कोटला, नई दिल्ली
श्रीलंका बनाम केन्या	01/03/2011	मंगलवार	1430 बजे	आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
इंग्लैंड बनाम आयरलैंड	02/03/2011	बुधवार	1430 बजे	एम चिन्नास्वामी, बंगलूरू
नीदरलैंड बनाम द. अफ्रीका	03/03/2011	गुरुवार	0930 बजे	पीसीए स्टेडियम, मोहाली
कनाडा बनाम पाकिस्तान	03/03/2011	गुरुवार	1430 बजे	आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
न्यूज़ीलैंड बनाम जिंबाब्वे	04/03/2011	शुक्रवार	0930 बजे	सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद
बांग्लोदश बनाम वेस्टइंडीज	04/03/2011	शुक्रवार	1400 बजे	शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर
श्रीलंका बनाम आस्ट्रेलिया	05/03/2011	शनिवार	1430 बजे	आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
इंग्लैंड बनाम द. अफ्रीका	06/03/2011	रविवार	0930 बजे	एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
भारत बनाम आयरलैंड	06/03/2011	रविवार	1430 बजे	एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर
कनाडा बनाम केन्या	07/03/2011	सोमवार	1430 बजे	फ़िरोज़शाह कोटला, दिल्ली
न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान	08/03/2011	मंगलवार	1430 बजे	पल्लिकिल्ली इंटरनेशनल स्टेडियम
भारत बनाम नीदरलैंड	09/03/2011	बुधवार	1430 बजे	फ़िरोज़शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली
श्रीलंका बनाम जिंबाब्वे	10/03/2011	गुरुवार	1430 बजे	पल्लिकिल्ली इंटरनेशनल स्टेडियम
आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज	11/03/2011	शुक्रवार	0930 बजे	पंजाब क्रिकेट स्टेडियम, मोहाली
बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड	11/03/2011	शुक्रवार	1400 बजे	जौहर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव
भारत बनाम द. अफ्रीका	12/03/2011	शनिवार	1430 बजे	विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम, नागपुर
कनाडा बनाम न्यूज़ीलैंड	13/03/2011	रविवार	0930 बजे	वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
आस्ट्रेलिया बनाम केन्या	13/03/2011	रविवार	1430 बजे	एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगलूरू
बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड	14/03/2011	सोमवार	0900 बजे	जौहर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव
पाकिस्तान बनाम जिंबाब्वे	14/03/2011	सोमवार	1430 बजे	पल्लिकिल्ली इंटरनेशनल स्टेडियम
आयरलैंड बनाम द. अफ्रीका	15/03/2011	मंगलवार	1430 बजे	ईडन गार्डंस, कोलकाता
आस्ट्रेलिया बनाम कनाडा	16/03/2011	बुधवार	1430 बजे	एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर
इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज	17/03/2011	बृहस्पतिवार	1430 बजे	एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
आयरलैंड बनाम नीदरलैंड	18/03/2011	शुक्रवार	09:30बजे	ईडन गार्डंस, कोलकाता
न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका	18/03/2011	शुक्रवार	1430 बजे	वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
बांग्लादेश बनाम द. अफ्रीका	19/03/2011	शनिवार	0900 बजे	शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर
आस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान	19/03/2011	शनिवार	1430 बजे	आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
केन्या बनाम जिंबाब्वे	20/03/2011	रविवार	0930 बजे	ईडन गार्डंस, कोलकाता
भारत बनाम वेस्टइंडीज	20/03/2011	रविवार	1430 बजे	एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
पहला क्वार्टर फाइनल	23/03/2011	बुधवार	1400 बजे	शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर
दूसरा क्वार्टर फाइनल	24/03/2011	बृहस्पतिवार	1430 बजे	सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा, अहमदाबाद
तीसरा क्वार्टर फाइनल	25/03/2011	शुक्रवार	1430 बजे	शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर
चौथा क्वार्टर फाइनल	26/03/2011	शनिवार	1430 बजे	आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
पहला सेमीफाइनल	29/03/2011	मंगलवार	1430 बजे	आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
दूसरा सेमीफाइनल	30/03/2011	बुधवार	1430 बजे	पंजाब क्रिकेट स्टेडियम, मोहाली
फाइनल	02/04/2011	शनिवार	1430 बजे	वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

Now, mixing business with pleasure makes perfect business sense.

Welcome to Fortune Inn Grazia, Noida, an elegant, upscale, full-service business hotel. It is strategically located in the heart of the city and in close proximity to Sector 18, the commercial and shopping hub of Noida. The hotel offers everything from contemporary accommodation and exciting dining options to, of course, comprehensive facilities for business and leisure. All to meet the growing needs of the new-age business traveller.

FORTUNE
Inn Grazia
BY WELCOMGROUP
Noida

Block-I, Plot No. 1A, Sector-27, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India
Tel: 0120-3988444, Fax: 0120-3380144
E-mail: grazia@fortunehotels.in Website: www.fortunehotels.in

CRAYONS

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 21 फरवरी-27 फरवरी 2011

1960 में बनी महान फिल्म मुग़ल-ए-आज़म भी नवंबर 2004 में रंगीन होकर दोबारा अपनी छाप छोड़ चुकी है.

पुरानी फ़िल्मों का रंगीन दौर

वर्ष 1961 में आई देवानंद की फिल्म हम दोनों के गीत न जाने कितने प्रेमी-प्रेमिकाओं को एक-दूसरे के क़रीब लाए होंगे, न जाने उन गीतों ने कितने युवाओं को फ़िक्र से निजात दिलाई होगी. इन अफ़सानों का लुत्फ उठाने वाले उस दौर के दर्शक अब जीवन उम्रदराज़ हो चुके हैं, लेकिन इन गीतों की आवाज़ कानों तक पहुंचते ही वे उन्हीं प्रेम भरे पलों में वापस पहुंच जाते होंगे, जब ये गीत उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे.

सलमान अली

भारतीय सिनेमा आज इतनी तरक़्क़ी कर रहा है कि इसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. यह सच है कि फिल्में समाज के हालात को मद्देनज़र रखकर ही बनाई जाती हैं. फिल्म निर्माता भी सरकार की तरह जनता की पसंद-नापसंद को ध्यान में रखकर ही फिल्में बनाते हैं. जो निर्माता अवाम की नब्ज़ को अच्छी तरह जानते हैं और उसके विचारों को उसी के मुताबिक़ उठाते हैं, वे कामयाब होते हैं और उनकी फ़िल्में भी. हर साल बॉलीवुड में सैकड़ों फिल्में पर्दे पर आती हैं, कुछ को दर्शक पसंद करते हैं और कुछ को सपना समझ कर भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई संदेश नहीं होता. समाज में सभी लोग एक ही तरह के विचारों-पसंद वाले नहीं होते. किसी को रोमांस पसंद है, किसी को एक्शन, किसी को पारिवारिक समस्याएं और किसी को सामाजिक मुद्दे. इसमें सबसे अहम मुद्दा सामाजिक है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं पर बनी फिल्में ही आज की पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकेंगी.

क्या बॉलीवुड की बुनियाद ग्लैमर पर टिकी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ फिल्में भारतीय संस्कृति के ख़िलाफ़ आती हैं तो कुछ फिल्में भारतीय संस्कृति को विकसित भी करती हैं. भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1930 में बनी पहली ख़ामोश फ़िल्म राजा हरिश चंद्र से हुई. इसके बाद 1931 में दूसरी फ़िल्म आलमआरा रिलीज़ हुई, जो भारतीय सिनेमा की पहली साउंड फिल्म थी और तबसे आज तक हिंदी सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. यह हक़ीक़त है कि आज से 50 वर्ष पुराने सिनेमा की तरफ़ मुड़कर देखें तो हमें दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर नज़र आएगा. आज जबकि हिंदी सिनेमा बेपनाह तकनीक और आधुनिकता से लबरेज़ है और हर तरह से इनका प्रयोग फिल्मों में किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्लासिकल सिनेमा को रफ़्ता-रफ़्ता भुलाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या लोग वाकई क्लासिकल सिनेमा को भुला सकते हैं? इसका जवाब बीती 4 फ़रवरी को रंगीन होकर दोबारा रिलीज़ हुई 1960 में बनी देवानंद की फिल्म हम दोनों ने साफ-साफ दे दिया, जो इन दिनों थियेटरों में धड़ल्ले से चल रही है. इस फिल्म के लिए तब देवानंद को फिल्म फेयर पुरस्कार हेतु नामज़द किया गया था. इसका गाना-*अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं*...लोग आज भी सहज गुनगुना उठते हैं. यह इस बात का सबूत है कि क्लासिकल सिनेमा के दीवाने आज भी मौजूद हैं और आज की आधुनिक और ग्लैमरस फिल्में उनका मुक़ाबला नहीं कर सकतीं. आधुनिक तकनीक के ज़रिए और लीक से हटकर बन रही बोल्ड फिल्मों के इस दौर में उन पुरानी फिल्मों को रंगीन बनाकर पेश करना यह बताता है कि प्रोडक्शन कंपनियां नई पीढ़ी को भारतीय सिनेमा का पुराना सुनहरा दौर दिखाना चाहती हैं, जिससे वह परिचित नहीं है. अगर आप इस फ़िल्म की तकनीक या क्वालिटी की तुलना आज के दौर की फ़िल्मों से करते हैं तो यह यक़ीनन आपके लिए नहीं है, मगर कहानी और इंसानी जज़्बात को पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारने की कोशिश की बात की जाए तो फिल्म शुरू से लेकरआख़िर तक निश्चित ही आपका दिल जीत लेने वाली है.

इससे पहले 1960 में बनी महान फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म भी नवंबर 2004 में रंगीन होकर दोबारा अपनी छाप छोड़ चुकी है. याद रहे कि यह फिल्म 1960 में एक साथ पूरे 150 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी, जो उस समय भारतीय सिनेमा के लिए एक महान उपलब्धि थी. फिर जब दोबारा इसे रंगीन बनाकर दर्शकों के सामने पेश किया गया तो इसके चाहने वाले ख़ुशी से उछल पड़े और उन्होंने इसे उसी जोश-ओ-ख़रोश के साथ देखा, जैसे 1960 में देखा था. इस फिल्म ने दोबारा सारे रिकार्ड तोड़ दिए और पूरे 25 सप्ताह तक बराबर सिनेमाघरों में चलती रही तथा भारतीय सिनेमा के लिए एक नई मिसाल क़ायम की. ख़ास बात यह है कि जिस समय मुग़ल-ए-आज़म रंगीन होकर दोबारा रिलीज़ हुई थी, उस वक़्त बॉलीवुड के मौजूदा दौर के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं की फिल्में रिलीज़ हुई थीं, जिनमें शाहरुख़ ख़ान एवं प्रीति जिंटा अभिनीत वीर ज़ारा, अक्षय कुमार एवं प्रियंका चोपड़ा अभिनीत ऐतराज़ और अभिषेक बच्चन एवं अंतरा माली अभिनीत नाच आदि फिल्में प्रमुख थीं, लेकिन इन सभी फ़िल्मों की चमक मुग़ल-ए-आज़म के सामने फीकी ही रही. इससे साफ ज़ाहिर होता है कि नई पीढ़ी आज भी क्लासिकल सिनेमा को कितना पसंद करती है. इसके बाद 1957 में रिलीज़ हुई दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म नया दौर को अगस्त 2007 में रंगीन पर्दे पर पेश किया गया. इसे भी दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया और इसने ख़ासी कमाई की.

आज जबकि फिल्म हम दोनों रंगीन होकर सिनेमाघरों में चल रही है, दर्शकों में वही ख़ुशी और दिलचस्पी देखने को मिल रही है. ऐसा नहीं है कि इन फिल्मों को रंगीन करने के लिए कम मेहनत-जद्दोजहद करनी पड़ी हो. फिल्म हम दोनों को रंगीन बनाने में साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत आई है. फिल्म रिलीज़ होने के बाद देवानंद भावुक हो उठे और उन्होंने कहा, अगर दर्शकों ने इस फ़िल्म को पसंद किया तो मैं अपनी तमाम फ़िल्में रंगीन कर दूंगा. जैसे एक चित्रकार अपनी सभी पेंटिंग्स के लिए भावुक होता है, उसी तरह मुझे अपनी सभी फ़िल्में प्यारी हैं. देवानंद बताते हैं, फिल्म हम दोनों को रंगीन करने की पहल मैंने नहीं की थी, बल्कि किसी ने हैदराबाद से मुझे फोन किया और कहा कि वे लोग मेरी इस फिल्म को रंगीन करना चाहते हैं. इससे मुझे लगा कि क्यों न लोगों को 50 साल पुराने देवानंद को देखने का मौक़ा दिया जाए. देवानंद को अपनी फ़िल्मों का रीमेक बनाना क़तई पसंद नहीं. वह कहते हैं, अगर मैं अपनी फ़िल्में दोहराऊंगा तो इसका मतलब यह होगा कि मैं ख़ुद को दोहरा रहा हूं. मैं अपनी फ़िल्म गाइड के रीमेक की इजाज़त क़तई नहीं दूंगा.

याद रहे कि देवानंद ने हमें दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें बाज़ी, गाइड, ज्वैलथीफ, पेइंग गेस्ट, हरे रामा हरे कृष्णा, सीआईडी, मि. प्राइम मिनिस्टर एवं चार्जशीट प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं. देवानंद को अभिनय का जादूगर कहा जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

तनु वेड्स मनु

कहते हैं कि शादियां स्वर्ग में ही तय हो जाती हैं, लेकिन जोड़ियों को शादी तक पहुंचने के लिए टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुज़रना पड़ता है. रास्ते में कई कठिनाइयां आती हैं. फिल्म तनु वेड्स मनु कुछ इसी तरह की कहानी पर आधारित है. तनुजा त्रिवेदी (कंगना) उर्फ तनु बहुत बोलती है. तेज बाइक चलाना, टैटू बनवाना और शराब पीना (वह भी नीट) उसे बहुत पसंद है. अरेंज मैरिज, सामाजिक बंधन और कोई उसे यह बताए कि क्या करना है, जैसी बातों से नफरत है. मनोज शर्मा (माधवन) उर्फ मनु होशियार, शांत और सीधा-सादा इंसान है. ऐसा लड़का जिसे हर लड़की के अभिभावक ढूंढते फिरते हैं, पढ़ाई-लिखाई करके डॉक्टर बन गया है और लंदन में सेटल हो गया है. वह एक प्यारी सी घरेलू किस्म की लड़की से शादी करना चाहता है. परिवार वालों के कहने पर मनु कानपुर में तनु से मिलने आता है. तनु और मनु का एक भी गुण नहीं मिलता. स्वभाव में एक आग है तो दूसरा पानी, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है. बार-बार उनके रास्ते एक-दूसरे से टकराते हैं और उनकी कहानी कई मजेदार उतार-चढ़ाव लेती है.

कंगना रानावत को इस फिल्म में आप एक बिल्कुल नए अवतार में देखेंगे. वह पहली बार कॉमेडी करती नज़र आएंगी. कंगना ने इस फिल्म के लिए अपने सीने पर एक अवस्थी नाम का टैटू गुदवाया. फिल्म के एक दृश्य में उनके सीने पर गुदा हुआ यह टैटू तब दिख जाता है, जब एक लड़का उन्हें देखने आता है और कंगना के क्लीवेज से यह टैटू देख लेता है. कंगना इस सीन को लेकर थोड़ी हिचक रही थीं, मगर एक प्रोफेशनल होने के नाते उन्होंने यह सीन बख़ूबी दिया. यह टैटू कंगना ने ब्रेस्ट के ऊपरी हिस्से पर हिना से गुदवाया और सीन पूरा होने तक उसे लगाए रखा. इसके अलावा फिल्म का अट्रैक्शन है इसका एक गीत. कजरा मोहब्बत वाला... यह गाना तो आप सभी ने किसी न किसी की शादी में सुना ही होगा. चार दशक पहले रिलीज हुई फिल्म क़िस्मत का यह ज़बरदस्त हिट गाना एक नए अंदाज़ में फिल्म तनु वेड्स मनु में दिखाई देगा. ओ पी नैय्यर द्वारा संगीतबद्ध इस गाने को तब अभिनेत्री बबिता और अभिनेता विश्वजीत पर फिल्माया गया था, लेकिन अबकी बार इस गाने में कंगना रानावत और आर माधवन दिखाई देंगे. अच्छी बात यह है कि इस गाने को रीमिक्स नहीं किया गया है, बल्कि अपने मूल स्वरूप में ही इसे प्रस्तुत किया गया है. यह फिल्म आगामी 25 फरवरी को रिलीज़ हो रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 21 फरवरी-27 फरवरी 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान,
झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

Website : sanjeevanibuildcon.in

PLOT

BUNGALOW

DUPLEX

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9973959681
9471356199
9431190351
9472727767
9471527830

भाजपा का सम्मान जदयू का अपमान

भाजपा ने बिहार चुनाव में मिली रिकॉर्ड तोड़ सफलता के लिए अपने कार्यकर्ताओं और सांसदों का सम्मान किया तो वहीं जदयू ने लगभग छह सौ कार्यकर्ताओं, कुछ सांसदों एवं मंत्रियों से जवाब-तलब कर डाला. जीत के मायने किस तरह से बदले, इसका नमूना दोनों दलों ने दिखा दिया है. अब सवाल उठता है कि इस तरह के रवैए के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी. वे इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे या फिर वे भी जवाब में कोई नया सियासी पैंतरा आज़माएंगे.

सरोज सिंह

बिहार की जनता ने जदयू-भाजपा गठबंधन को भारी बहुमत से सत्ता की चाबी सौंपी तो देश-दुनिया के लोगों ने सूबे के लोगों की राजनीतिक चेतना की तारीफ़ की. कहा गया कि लोगों ने बिहार की ज़रूरत को समझा और विकास के लिए जातिपात से ऊपर उठकर एकजुट होकर मतदान किया. लेकिन लगता है कि जीत पर गठबंधन की राय एक नहीं हो पाई और दोनों दलों ने जीत की अलग-अलग व्याख्या कर डाली. भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता के लिए अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया तो जदयू ने लगभग छह सौ कार्यकर्ताओं, कुछ सांसदों एवं मंत्रियों से जवाब-तलब कर डाला. भाजपा ने माना कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता का रास्ता साफ़ करने में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ लगा दिए. यही वजह रही कि पटना के गांधी मैदान में पहली बार कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित कर यह संदेश दिया गया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शानदार काम किया और लोकसभा चुनाव में भी इसी ज़ज्बे को बरक़रार रखना है.

समारोह की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई. दूसरी तरफ़ जदयू ने छह सौ से अधिक कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उन्हें पटना बुलाया और पार्टी विरोधी गतिविधियों का जवाब पूछा. बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र कुमार उर्फ़ ज्ञानू की अनुशासन समिति ने सांसद ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मोनाज़िर हसन, पूर्णमासी राम, मंगनी लाल मंडल, महाबली सिंह के अलावा पूर्व सांसद अरुण कुमार, विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तलब किया. लेकिन जैसा कि तय था, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और प्रेम कुमार मणि समिति के सामने पेश नहीं हुए. ललन सिंह ने तो साफ़ कह दिया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है. जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ज्ञानू समिति को सांसदों को तलब करने का अधिकार ही नहीं है. मैंने कोई भी दल विरोधी काम नहीं किया है. अगर मुझे कोई सफ़ाई देनी या बात कहनी होगी तो नीतीश कुमार या फिर शरद यादव के सामने कहूंगा. ये दोनों जहां बुलाएं, मैं वहां आकर अपनी बात कहने को तैयार हूं. इसके साथ ही कुशवाहा ने सवाल दागा कि जो पार्टी अपने छह सौ से अधिक कार्यकर्ताओं को नोटिस देती है, उसमें आंतरिक लोकतंत्र का क्या हाल होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं गई, एकतरफ़ा फ़ैसला लिया गया, जिसके कारण कार्यकर्ताओं ने अपनी लाइन ख़ुद तय कर ली. अब चेहरा बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है.

इसी तरह प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि क्यों सफ़ाई दें हम, कोई सरकारी सेवा में हैं. ईमानदारी से सिद्धांतों के साथ राजनीति करते हैं और जनता की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. केवल दिखावा हो रहा है. इससे पार्टी का भला होने वाला नहीं है. मणि के अनुसार, जो पार्टी अपने सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगी, उसका क्या हाल होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है. लेकिन अनुशासन समिति के प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की दलील कुछ और ही है. उनका कहना है कि पार्टी कायदे-क़ानून से चलती है, न कि मनमानी से. चुनाव के समय जिन नेताओं पर दल विरोधी काम करने का आरोप लगा है, उनसे सफ़ाई मांगने में क्या बुराई है. जब कई सांसद एवं बड़े नेता समिति के सामने अपनी बात रख सकते हैं तो ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा एवं मणि पेश क्यों नहीं हो सकते. इसका तो यही मतलब है कि ये तीनों नेता ख़ुद को पार्टी संविधान से ऊपर मानते हैं.

ज्ञानू के अनुसार, इन तीनों नेताओं के ख़िलाफ़ समिति के पास काफ़ी साक्ष्य हैं और मार्च के प्रथम सप्ताह तक हम अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को सौंप देंगे. उसके बाद इन नेताओं पर फ़ैसला लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि ललन सिंह की सदस्यता रद्द करने और उपेंद्र कुशवाहा एवं प्रेम कुमार मणि को पार्टी से बाहर करने की सिफ़ारिश की जा सकती है.

धीमी आंच पर पक रही है नई खिचड़ी

जदयू के अंदरूनी टकराव से राजनीति की नई कोपलें फूट सकती हैं. बिहार की विकल्पहीन सियासत में विपक्ष की अहमियत धेले भर की रह गई है. ऐसे में सत्ताधारी दल के भीतर राजनीतिक रसूख़ एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण आपसी भिड़ंत में सियासी महारथियों को नई संभावना दिख रही है. सूत्रों पर भरोसा करें तो उपेंद्र कुशवाहा एवं डॉ. अरुण कुमार के बीच धीमी आंच पर नई खिचड़ी पक रही है. जदयू में वापसी के बाद ये दोनों नेता ठगा सा महसूस करते हैं. इन्हें बड़ी चालाकी के साथ पार्टी में लाकर चुनाव के दौरान हाशिए पर डाल दिया गया. इन दोनों नेताओं को गत विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ी मिन्नत-आरजू के साथ दल में लाया गया था. तब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही इन दोनों को कथित अनुशासनहीनता एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया.

अरुण कुमार

ललन सिंह

उपेंद्र कुशवाहा

उधर कुशवाहा समाज के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास भी चल रहा है. बताया जाता है कि पूर्व मंत्री नागमणि, भगवान सिंह कुशवाहा एवं उपेंद्र कुशवाहा के बीच सुलह-सफ़ाई की कोशिशें सामाजिक स्तर पर चल रही हैं. इसी के तहत लंबे अर्से के बाद उपेंद्र कुशवाहा एवं भगवान सिंह कुशवाहा दानापुर में एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान एक साथ एक मंच पर मौजूद थे. बेचैनी की बड़ी वजह यह है कि 2005 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 19 टिकट कुशवाहा समाज के नेताओं को दिए थे, गत चुनाव में इस समाज के सिर्फ़ 14 नेताओं को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया. नीतीश सरकार के पिछले मंत्रिमंडल में चार कुशवाहा नेताओं को मंत्री पद से नवाजा गया था. वर्तमान कैबिनेट में मात्र दो कुशवाहा विधायक मंत्री हैं. इसलिए इस समाज में बेचैनी का आलम है. शायद यही वजह थी कि संजय गांधी जैविक उद्यान में आयोजित कुशवाहा समाज के वार्षिक वन भोज में जब कतिपय नेतागण नीतीश चालीसा का पाठ कर रहे थे, तब उपेंद्र कुशवाहा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि समाज को दिशानिर्देश प्राप्त करने के बजाय दिशानिर्देश देने की स्थिति में आना चाहिए. उपस्थित जनसमूह ने उनके इस कथन को उत्साहित होकर सराहा. वहीं उनके नेतृत्व में पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जुटी भीड़ इस बात का इशारा है कि नए विकल्प की तैयारी चल रही है.

महात्मा फुले परिषद के प्रदेश महासचिव विनोद मेहता के अनुसार, उपेंद्र कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्वीकार्य हो सकते हैं. यही वजह है कि जदयू की ओर से कुशवाहा समाज के ही निरंजन कुमार पप्पू एवं सी पी सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा की संपत्ति में कथित बेतहाशा वृद्धि पर सवाल उठाया था. इसके जवाब में उपेंद्र ने अपनी ही संपत्ति की जांच की मांग करके तुरुप का पत्ता फेंक दिया और बीती 24 जनवरी को वह इसके लिए भूख हड़ताल पर भी बैठे. बताया यह भी जा रहा है कि ललन सिंह भी इस कवायद में पूरी रुचि ले रहे हैं. बिहार में नए विकल्प के लिए जुटे लोगों को राष्ट्रीय राजनीति से प्रेरणा मिल रही है. देश में कांग्रेस के एकदलीय शासन का अंत पार्टी के पैरोकारों के बीच आंतरिक विवाद की वजह से हुआ था. कांग्रेस (एस) एवं कांग्रेस (आई) के बीच विभाजित कांग्रेसी ही 1977 में पार्टी के सत्ताच्युत होने की प्रमुख शुरुआती वजह बने. पार्टी से बग़ावत करके बाहर निकले मोरार जी देसाई देश के पहले ग़ैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने. उधर राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 1984 में ज़बरदस्त बहुमत मिला था. विपक्ष पूरी तरह हताश था. इसी बीच कांग्रेस में विद्रोह की चिंगारी फूटी. विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके अगुवा बने. वही तीसरे ग़ैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने. इसे बिहार में पुन: दोहराने की संभावना जताई जा रही है. जदयू के बाग़ियों के भरोसे नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कवायद पर गहरी नज़र है. इसमें राजद के भी कुछ नेता साथ हैं. सोनपुर के पूर्व विधायक रामानुज प्रसाद एवं राम बिहारी सिंह काफी सक्रिय रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

करोड़ों का संसाधन जंग का आहार बना दशकों से एक उद्धारक की बाट जोह रहा है. वेद सदर लैंड कंपनी के नाम से शुरू इस मिल का संचालन अंग्रेज सरकार द्वारा ही होता रहा.

बीपीएल परिवार में वैसे लोगों का नाम भी दर्ज है जिनकी हैसियत करोड़ों में है जबकि वैसे गरीब परिवारों का भी इस सूची में नाम दर्ज नहीं हो सके है जिनकी माली हालत अत्यन्त ही कमजोर है.

एक नज़र इधर भी

सूचना मांगी तो जेल भेजा

महनार में भाजपा कार्यकर्ता सुबोध राय ने अवर निबंधक की लेट लतीफ़ी का विरोध किया तो अवर निबंधक ने उसकी अनुज्ञप्ति ही रद्द करने का प्रस्ताव ज़िला निबंधन को भेज दिया. जब सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो आवेदन के अगले दिन ही मुकदमा कर जेल भिजवा दिया. हालांकि, न्यायालय ने सुबोध राय के सूचना का अधिकार से संबधित दलील को उचित मानते हुए जमानत पर मुक्त कर दिया. इस संबंध में अवर निबंधक ने बताया कि सुबोध राय काफ़ी पहले से गाली गलौज करते आ रहे थे और जब काम करना मुश्किल हो गया तब जाकर उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवानी पड़ी.

रंगरेज बिरादरी का हो उत्थान : मुस्तकिम

रंगरेज बिरादरी के उत्थान को लेकर ऑल इंडिया रंगरेज जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. मुस्तकीम अख्तर रंगरेज ने पटना के एस.के. मेमोरियल हॉल में आगामी 3 अप्रैल को सेमिनार का आयोजन किया है. अख्तर ने बताया कि रंगरेज बिरादरी पुराने समय से सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम देते आ रहे हैं एवं हिंदू भाइयों के पूजा-विवाह व अन्य कार्यों में इसी धंधे से जुड़े लोगों के द्वारा चुनरी रंगवाई जाती है. उन्होंने कहा कि इस बिरादरी के लोग शैक्षणिक आर्थिक व राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं तथा इनके अधिकारों के लिए मंच का अभियान जारी है.

विकलांग को नहीं मिली ट्राई साइकिल

विकलांगों के लिए ढेरों सरकारी लाभप्रद योजनाएं होने के बावजूद महानार प्रखंड के बघनोचा निवासी मनोज राय (33 वर्ष) को अब तक ट्राईसाइकिल नहीं मिल पाई है. मनोज राय ने बताया कि 22 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में उसका पैर चोटिल हो गया तथा अब वह हाथ के सहारे ही चलता है. कल्याणकारी योजनाओं की बात सुन कर वह हाकिम लोगों के पास आया था लेकिन एसडीओ-बीडीओ के यहां चक्कर लगाते-लगाते वह थक चुका है. उसने बताया कि उसे पेंशन भी नहीं मिल रही है. ज़िला पार्षद रंजीत राय ने अविलंब ट्राईसाइकिल व पेंशन उपलब्ध कराने की मांग डीएम से की है. दूसरी तरफ़ भाजपा नेता प्रियरंजन दास ने इसके लिए कल्याण मंत्री को पत्र लिखा है. *- अंजुम परवेज*

दरभंगा का बाज़ार अतिक्रमण की चपेट में

लेहरिया सराय स्थित गुदरी बाज़ार वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में है. इससे यहां के लोगों को ख़रीददारी करने में बहुत परेशानी होती है. कई बार अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने के बावजूद पुन: दुकानदारों द्वारा गुदरी बाज़ार की सड़क को अतिक्रमित कर लिया गया है. इससे गुदरी बाज़ार जाने वाले आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसका मुख्य कारण जनसंख्या का बढ़ना तथा लोगों की जरूरतों के अनुसार बाज़ार का विस्तार न होना बताया जाता है. दरभंगा स्थित इन बाज़ारों के अतिक्रमण की इस समस्या के प्रति प्रशासन उदासीन है. अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य में यह समस्या और गंभीर हो जाएगी.

मिथिला के कलाकार महाराष्ट्र में सम्मानित

मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय आकाशवाणी शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में पुरस्कृत होकर युवा गायक साहित मल्लिक एवं संगीत मल्लिक ने दरभंगा घराना का नाम रोशन किया है. उन्हें यह पुरस्कार आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की तरफ से मुंबई के एनसीपी हॉल में दिया गया. मल्लिक बंधुओं को हिंदुस्तानी गायन ध्रुपद-धमार के लिए यह पुरस्कार दिया गया. इसके अलावा ये दोनों ठुमरी, भजन, विधापति संगीत में भी निपुण हैं. इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के हाथों उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा. दोनों भाइयों ने अपने पितामह पं. विदूर मल्लिक से बचपन में सुर का ज्ञान प्रदान किया है. इन्हें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से छात्रवृति भी मिल रही है.

दरभंगा का नन्हा महंथ

दरभंगा के राधा गोविंदमठ मकरंदा के महंथ राम शंकर दास के सानिध्य में सकतपुर के विशनपुर गांव का चार वर्षीय बालक इन दिनों इलाक़े में कौतूहल का विषय बना हुआ है. माथे पर तिलक लगाए यह बालक सीताराम चौधरी अब सीताराम दास के नाम से जाना जा रहा है. मठ से सटे मध्य विधालय में नन्हा महंथ आम छात्रों के साथ बैठकर रोज़ पढ़ाई करता है. यही कोई छह माह पूर्व वह मां ममता देवी के आंचल से दूर होकर महंथ राम शंकर दास के सानिध्य में आया है. पिता किसी लड़ाई-झगड़े के मामले में जेल में है. उसके धर्म गुरु महंथ राम शंकर दास ने कहा कि उन्हें इस अनुपम चेले की बुद्धि पर गर्व है. इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नही रखी जाएगी. *-चौथी दुनिया ब्यूरो*

जमुई के अस्पताल में पार्क बना

जमुई के सदर अस्पताल में बने पार्क का उद्‌घाटन ज़िलाधिकारी विपिन कुमार ने वृक्ष लगाकर किया. इस मौक़े पर सिविल सर्जन सह रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ. चन्द्रेश्वर चौधरी ने कहा कि सदर अस्पताल में वृक्ष दान के सहयोग से पार्क का निर्माण किया गया है. इससे इलाज करवाने वालों तथा उनके परिजनों को अच्छा अनुभव होगा. इस मौक़े पर जनसामान्य विकास समिति के सचिव निर्जय सिंह, डॉ. नौशाद अहमद के अलावा आशा व ममता कार्यकर्ता उपस्थित थे. *-इमरान ख़ान*

80 बच्चों को मिली पोशाक की राशि

जमुई के वॉर्ड नं. 22 के प्रभाग के आयुक्त अमर भगत ने आगंनबाड़ी केन्द्र पर 80 बच्चों के बीच पोशाक की राशि वितरित की. ढाई सौ बच्चों के दर से प्रभाग आयुक्त ने 40 बच्चों को पोशाक की राशि दी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस राशि से पोशाक ख़रीदेंगे और आगंनबाड़ी केन्द्र पर आएंगे. इस मौके पर अरूण कुमार भगत, कपिल देव रावत, अमित केसरी के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे.

खगड़िया में बनेगा ओवरब्रिज

खगड़िया के लोगों को जल्द ही जाम से निजात मिलने वाली है. शहर के पूर्वी केबिन ढाला पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू होगा. सांसद दिनेशचन्द्र यादव ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. तीन महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि दो साल में निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. सांसद ने बताया कि खगड़िया के लोग ओवरब्रिज के न होने से काफी कठिनाई महसूस कर रहे थे.

महंगाई को लेकर वामदलों का धरना

महंगाई व भ्रष्टाचार के विरोध में खगड़िया समाहरणालय के साथ माकपा व भाकपा ने धरना दिया. इसकी अध्यक्षता पुनीत मुखिया व विद्यानंद सिंह ने की. घटना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सत्यानारायण सिंह ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह असफल रही है. इस मौक़े पर प्रभा शंकर सिंह गीता यादव अजय वर्मा आदि मौजूद थे.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

मगध मेडिकल कॉलेज

यहां इलाज नहीं बाक़ी सब होता है

सुनील सौरभ

सपना था, मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एशिया स्तर के अस्पतालों की सूची में सबसे अव्वल रखना, लेकिन सरकारीकरण होने के साथ ही मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखने वाले सदस्यों का सपना एक-एक कर टूटता चला गया. सेवा, सहिष्णुता और प्रेम का पाठ सिखलाने की बजाए यहां हिंसा का पाठ पढ़ाया जाने लगा. तभी तो मेडिकल कॉलेज में जूनियर चिकित्सकों का दबदबा इस कदर है कि ज़रा सी भी बात होने पर धरना, तालेबंदी, मार-पीट और आंदोलन का रुख़ अख्तियार करना इनके लिए खेल बन गया है. डॉक्टर बनने के पूर्व एक शपथ ली जाती है. ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम भाव से मरीजों का इलाज करने का और मरीजों की जान बचाने के लिए जी-जान लगाने का, लेकिन ऐसा हो कहां रहा है? अगर ऐसा होता तो क्या मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अपनी जिद मनवाने के लिए हड़ताल करते! इनकी तो जिद पूरी हो गयी, लेकिन जिनके घरों का एकमात्र चिराग बुझ गया, पुत्र के सिर से पिता का साया उठ गया, गोद में खिलाने वाली मां चली गई, क्या वापस आ पाएगी? क्या जूनियर डॉक्टरों को इसका अफ़सोस है. वे तो जश्न मना रहे हैं कि उनकी जीत हो गयी. लेकिन जिन लोगों को मौत ने हरा दिया, उनके परिवार का क्या होगा? राज्य सरकार के ज़िम्मे आते ही अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले लोगों के भविष्य तो सुरक्षित हो गए, लेकिन यहां आने वाले मरीज़ों को सुविधाएं कम होती चली गईं. हालांकि, आज बदले माहौल में इस मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन साथ ही यह मेडिकल कॉलेज आज राजनीति, बैठकबाज़ी, झगड़ा-झंझट, दलित-महादलित की गुटबाजी का मैदान बन गया. हालिया दिनों में यहां के जूनियर डॉक्टरों एवं राजद विधायक डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव के बीच हुई झड़प राज्य स्तरीय सुर्ख़ियों का विषय बनी, जिस कारण राज्य भर के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जूनियर डाक्टरों ने हड़ताल की.

भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टर तमाम अपील के बाद भी मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर अपनी मांगों पर अड़े रहे. वहीं विधायक के बचाव में उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई फायरिंग को बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने जायज़ ठहराते हुए राज्य सरकार से अपने सिपाही को जेल भेजे जाने के मामले पर गंभीर होते हुए राज्य सरकार से ही पूछ डाला कि आख़िर वीआईपी की सुरक्षा में लगाये गए अंगरक्षकों की ड्यूटी क्या हो. यह सरकार तय कर दे. एक तरफ़ किसी वीआईपी के साथ घटना घटती है, तो अंगरक्षक ज़िम्मेदार माने जाते हैं. यदि इनके बचाव में अंगरक्षक फायरिंग करता है, तब भी उसे दोषी ठहराया जाता है. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में एक मरीज़ के इलाज को लेकर विधायक डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई झड़प में कौन दोषी है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन राज्य भर में इस मामले को लेकर जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के कारण आम आदमी एवं जनता ही हलकान रही. आख़िर इस मामले में जनता का क्या दोष था. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई हरकत इसके पूर्व भी कई बार देखी गई है. मरीज़ों के परिजनों से की जा रही मारपीट को जब कैमरे में क़ैद करने वाले मीडियाकर्मियों को पीटा गया, तब भी जूनियर डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर अपनी-अपनी राग अलापते रहे. बिहार के एक ज़िले के तत्कालीन जज की पत्नी के इलाज में भी जूनियर डॉक्टरों ने जो अमानवीय हरकत की, वह भी राज्य स्तर में सुर्ख़ियों पर छाई रही. हाल के दिनों में बिजली-पानी की समस्या को लेकर इस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने अपने ही कॉलेज और अस्पताल में जो तोड़-फोड़ और आगजनी की. विधायक डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ जब घटना घटी, तो पुलिस जीप को फूंक देने, सदर अनुमंडल पदाधिकारी के अंगरक्षक के साथ मारपीट करने के मामले में भी जूनियर डॉक्टरों की कार्रवाई को मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे संबोधन से पुकारा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि आज के सुशासन में ऐसी स्थिति आई है, राजद शासनकाल में इस मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में राजद के स्थानीय एवं दबंग कार्यकर्ताओं का आना-जाना भी इस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों के कारण ही था. इस समय छात्रावास में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ अमानवीय घटना घटी थी, तब पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में परिजनों ने इस मामले को नहीं देकर अपनी इज़्ज़त बचाई थी, लेकिन लोगों को कानों-कान ख़बर तो लग ही गई. इस मेडिकल कॉलेज में विधायक और जूनियर डॉक्टरों के बीच एक मरीज के इलाज पर हुए मामले में भी कुछ वरीय व अवकाश प्राप्त चिकित्सकों की भूमिका भी संदिग्ध रही. इस मामले को लेकर गया में आम लोगों की सहानुभूति अब डॉक्टरों, विशेष कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के प्रति नही रही. इस बात का पता विधायक-जूनियर डॉक्टर के बीच हुई झड़प और गोलीबारी की घटना के बाद और स्पष्ट हो गया. क्योंकि इस मामले को लेकर तमाम शहरवासियों और विभिन्न संगठनों के लोगों ने जूनियर डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जमकर धरना-प्रदर्शन किया और मौन जुलूस भी निकाला. लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज़ों के परिजनों के साथ जूनियर डॉक्टरों की जो हरकत होती है, इसके कारण ही वहां पदस्थापित वरीय चिकित्सक भी काम करने से कतराते हैं. लेकिन मामला जब पेशे से संबंधित होता है, तो लाचार होकर वरीय चिकित्सकों को भी जूनियर डॉक्टरों का साथ देना पड़ता है. ऐसे प्रतिदिन इस मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजनों के साथ कुछ न कुछ होने की बात सामने आती है. लेकिन इस बार मामला राजद के दबंग विधायक डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कुछ विशेष लोग राजदकालीन शासन को दोहराकर विधायक के लोगों की ग़लती का हवाला दे रहे हैं. पर सच्चाई यही है कि अब जूनियर डॉक्टरों के प्रति गया में आम लोगों की सहानुभूति लगभग समाप्त सी हो गई है.

feedback@chauthiduniya.com

चीनी मिलों का ताला कब खुलेगा

समस्तीपुर

तत्कालीन सरकार चीनी मिलों के प्रति काफ़ी उदासीन रवैए के कारण मिलों को बंदी के कगार पर पहुंचना पड़ा. आज भी यही सब हो रहा है. किसानों की तरफ़ से गन्ने की उपज में कोई कमी नहीं आई है तो फिर भी मिलें क्यों बंद हो रही हैं.

बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कराने की घोषणा करने वाली राजग गठबंधन की सरकार में बदहाल औद्योगिक इकाईयों की दशा सुधारने हेतु व्यापक कार्य किए गए, लेकिन सत्ता शासन की उपेक्षा के कारण समस्तीपुर चीनी मिल कबाड़खाना में तब्दील हो गया है. समस्तीपुर शहरी क्षेत्र में स्थित चीनी मिल की नींव अंग्रेजों के शासनकाल में ही डाली गई थी. वर्ष 1920-21 में स्थापित इस मिल का प्रारंभिक दौर जहां स्वर्णिम रहा है, वहीं वर्तमान अतीत कूपा बनकर रह गई है. मिल से जुड़े हज़ारों परिवार आज जीवन यापन के लिए काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं. करोड़ों का संसाधन जंग का आहार बना दशकों से एक उद्धारक की बाट जोह रहा है. वेद सदर लैंड कंपनी के नाम से शुरू इस मिल का संचालन अंग्रेज सरकार द्वारा ही होता रहा. तब इसकी क्षमता का सही मायने में उपयोग कर कंपनी जहां करोड़ों के वार्षिक मुनाफे में रहती थी वहीं समस्तीपुर के हज़ारों लोगों को रोज़ी-रोज़गार उपलब्ध था. आज़ादी का जश्न चीनी मिल के मिठास को सहन नहीं कर सका. कंपनी ने इसे एक उद्योगपति के हाथों बेच दिया. अग्रवाल एंड कयान्स ब्रदर्स नाम से संचालित यह मिल किसी तरह डेढ़ दशक तक अपनी चिमनी से धुंआ उड़ाता रहा परंतु 1962-63 में प्रबंधन ने अपने हाथ खड़े कर दिये और मिल में तालाबंदी की घोषणा कर दी. तब मिल से जुड़े लोगों का एक शिष्टमंडल बिहार बिधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से मुलाकात की और ज़िले की इकलौती औद्यौगिक इकाई होने का हवाला देते हुए इसे बचाने की गुहार लगाई. प्रधानमंत्री ने मामले को जनहित राज्य हित में बेहतर मानकर मिल को केंद्र सरकार के अधीन ले लिया. वर्ष 1972 तक केंद्र सरकार ने इसे चलाकर राज्य सरकार के हवाले प्रबंधन का ज़िम्मा छोड़ दिया. तब बिहार सरकार ने 1972 से स्थानीय बोर्ड बनाकर प्रबंधन करना शुरू किया. वर्ष 1976 में चीनी अर्जन विधेयक में चीनी निगम स्थापित हो गई जिसमें समस्तीपुर समेत अन्य मिलों का अधिग्रहण कर इसके प्रबंधन का ज़िम्मा चीनी निगम को सौंप दिया गया. 1976 से 1997 तक चीनी निगम के अधीन इसका संचालन होता रहा. वर्ष 1997 में ही निगम ने मिल में उत्पादन कार्य बंद कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने उत्पादन के लिए आर्थिक सहयोग देना बंद कर दिया. तब से लेकर आज तक यह चीनी मिल बंदी का दंश झेल रही है.

तत्कालीन सरकार के इन चीनी मिलों के प्रति काफ़ी उदासीन रवैए के कारण चीनी मिलों को बंदी के कगार पर पहुंचना पड़ा. शुरुआती दिनों में 8 हज़ार क्विंटल प्रतिदिन पेराई करने वाले इस मिल में नई तकनीकों का उपयोग न किये जाने के कारण समय के साथ पेराई क्षमता घटने लगी और उत्पादन ख़र्च बढ़ता गया. वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रथम कार्यकाल में राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से प्रारंभ कराने की कयावद शुरू की. सरकार ने राज्य की सभी बंद मिलों को निजी कंपनियों को सौंपना शुरू किया. इसके लिए एसबीआई कैप्स (टेक्निकल सेल) को बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसे चीनी मिल निगम के बंद मिलों का मूल्यांकन एवं देयता के निर्धारण का ज़िम्मा सौंपा. कैप्स रिपोर्ट के आधार पर निजी उद्योगपतियों को मिल देने के लिए निविदा भी आमंत्रित की गई, जिसमें समस्तीपुर के लिए एक भी उद्योगपति सामने नहीं आए. स्थापना काल में तकरीबन 900 लोगों के लिए रोज़गार का केंद्र रही समस्तीपुर मिल में बंदी के बाद मात्र 60 कर्मचारी ही कार्यरत हैं, जिन्हें वर्षों से वेतन के लाले पड़े हैं. एफसीआई को किराये पर दिये गये गोदाम की राशि से यदा-कदा कर्मियों को अग्रिम के रूप में कुछ राशि दी जाती है. सेवानिवृत कर्मियों का हाल तो और भी बुरा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिल बंदी समय तक के गन्ना की बकाया राशि का भुगतान करा दिया, लेकिन कर्मचारियों के हित में कुछ भी नहीं सोचा गया. इससे मिल में कार्यरत कर्मियों को एक-एक दिन पहाड़ के समान लग रहा है.

प्रकाश कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देवघर: नेताओं में मची है खींचतान

देवघर ज़िले में मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए जहां एक तरफ जनता जूझ रही है, वहीं इन दिनों नेताओं में वर्चस्व को लेकर घमासान मचा है. इस बार गर्मी के मौसम में शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या से शोर मचने की आहट हो चुकी है. 25 वर्षों से अधर में लटकी पुनासी जलाशय योजना को लेकर शुरू हुई राजनिति अब विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है. लंबे समय तक वोट की राजनिति के तहत पुनासी जलाशय योजना को लटकाने वाले स्थानीय विधायक सुरेश पासवान को सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार की सहायता से योजना पर काम प्रारंभ करवा कर चुनौती दे दी. विधायक सुरेश पासवान के समर्थन में जहां योजना से विस्थापित सैकड़ों ग्रामींण हैं वहीं दुबे के समर्थन में मेयर राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलु खवाड़े, समाजसेवी सुनील खवाड़े सहित शहरी क्षेत्र के कई दिग्गज साथ हैं. हाल ही में भाकपा माले ने पुनासी जलाशय योजना के विस्थापितों को समर्थन देने की घोषणा से मामला गरमाने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है. पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी पुनासी के विस्थापितों की मांगों को जायज़ ठहराते हुए हरसंभव समर्थन देने की घोषणा की है. पंचायत चुनाव के बाद विधायक सुरेश पासवान ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर ज़िला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी को जिता कर अपना पक्ष मज़बूत कर लिया है. इसी बीच निशिकांत दुबे की विशेष पहल पर स्थानीय हवाई अड्डे विस्तारीकरण के मुद्दे ने नया विवाद खड़ा कर दिया. वहां भी विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले आसपास के ग्रामीणों ने विरोध में झंडा उठा लिया है. इनका नेतृत्व वयोवृद्ध समाजसेवी व लोहिया कर्पूरी विचार मंच के संस्थापक अनिरूद्ध आजाद कर रहे हैं. आजाद जी के नेतृत्व में हवाई अड्डा परिसर से लेकर समाहरणालय तक प्रदर्शन व धरना कार्यक्रम भी हो चुका है. इसी बीच ज़िला प्रशासन ने आज़ाद जी सहित दो सहयोगियों पर प्रदर्शन के दौरान भड़काने वाले भाषण देने के आरोप में निरोधात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है, जिसके कारण आजाद जी ने आंदोलन को और अधिक तेज़ करने का ऐलान कर दिया है. ग्रामींणों का कहना है कि पूर्व में अधिग्रहीत की गई ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है. विद्युत कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार के अनुसार विभाग से कई बार तकनीकी कर्मचारी सहित सामग्री की मांग की गई है. ज़िले में सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इंदिरा आवास योजना, बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जनवितरण प्रणाली जैसी कई योजनाओं का लाभ ग़रीबों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी चिंता करना शायद इन नेताओं के क़द व प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है. सिर्फ़ कभी कभार अख़बारों के माध्यम से बयान जारी कर पदाधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार की चेतावनी दे देते हैं. बुद्धिजीवियों का कहना है कि अब जनता काफ़ी जागरूक हो गई है अपने अधिकार के प्रति सजगता के साथ आवाज़ बुलंद करने से पीछे नहीं रहती. ऐसी स्थिति में सांसद व विधायक सहित अन्य नेतागण उपरोक्त मामलों में जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया और दमनात्मक कार्रवाई हुई तो शायद लोगों का गुस्सा बढ़े और अशांति फैल सकती है. इससे बाबा वैद्यनाथ की पावन नगरी दागदार होगी और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ ज़िले के शीर्ष नेता ही होंगे.

समाजसेवी अनिरुद्ध आजाद

सांसद निशिकांत दुबे

विधायक सुरेश पासवान

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com

पारिवारिक सर्वेक्षण सूची

हज़ारों लोगों के नाम ग़ायब

विजयेन्द्र कुमार

कमज़ोर बुनियाद पर ऊंची इमारत की हसरत पूरी नहीं हो सकती. अगर ऐसा होता है तो भविष्य में संकट का भय बना रहता है. हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त उपभोक्ता वस्तुओं के वास्तविक लाभुकों की समस्याओं से. जो पिछले कई वर्षों से इस व्यवस्था के चक्की में पिसते हुए अक्सर हाय तौबा मचाते हैं. बहरहाल, जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को सरकारी स्तर पर दो वर्गों में विभाजित कर साधन संपन्न व ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए अलग-अलग मानक तय किये गये हैं. जिसमें बीपीएल परिवार के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही अनुदानित मूल्य पर जन वितरण प्रणाली के दुकानों के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है. वर्तमान में ज़िले में ग़रीबी रेखा के नीचे क़रीब 4 लाख चिन्हित हैं. ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में बीपीएल परिवारों का जो निर्धारण किया गया है, उसे लेकर बराबर मामला गहराता रहा है. मीडिया के रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि बीपीएल निर्धारण में सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र के मानको को ताक पर रखकर मनमाने तौर पर बीपीएल परिवार का निर्धारण करने का बख़ूबी रूप से कार्य किया है. बीपीएल परिवार में वैसे लोगों का नाम भी दर्ज है, जिनकी हैसियत करोड़ों में है. जबकि वैसे ग़रीब परिवारों का भी इस सूची में नाम दर्ज नहीं हो सके है, जिनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है तथा वैसे परिवार की ज़िंदगी केवल मज़दूरी पर आश्रित है. ऐसी स्थिति में जन वितरण प्रणाली के तहत व्यवस्था का आलम क्या होगा? यह सहज रूप से जाना जा सकता है. हाल यह है कि ज़िले के राशनिंग लानिंग में जहां भी हाथ रखा जाएगा, वहीं सड़ाध मिलेगी. ज़िला आपूर्ति व्यवस्था बिचौलिये की मुट्ठी में क़ैद होकर कसमसा रही है. अधिकारियों की मिली-भगत से मानकों के विपरीत आवंटन सूची बनाकर पसंदीदा डीलरों को मनमानी तौर पर वस्तुओं का उठाव कराया जाता है, जबकि अधिकांश दुकानदारों को नाम मात्र का आवंटन उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आती है. हद तो तब हो गई जब बनियापुर प्रखंड में मई 2010 के कूपन जनवरी 2011 में बंटने पर उपभोक्ता भड़क गए और उन्होंने पंचायत सचिव के मैसेंजर से कूपन छीनकर फाड़ डाले. कूपन का वितरण सभी पंचायतों में सरकारी कर्मियों के द्वारा बांटने का सरकारी निर्देश है मगर प्राय: सभी पंचायतों में संबंधित पंचायतों के मुखिया द्वारा बांटे गये. जिसमें संबंधित मुखियाओं द्वारा व्यापक रूप से मनमानी किए जाने की आम शिकायत मिलती है. बताया जाता है कि करीब 75 हज़ार से अधिक परिवार ऐसे भी हैं, जिनका नाम पारिवारिक सर्वेक्षण सूची से ग़ायब है. जिसके कारण उन्हें किरासन तेल नहीं मिलता है. शहर व देहात के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां ग़रीब परिवार के लोगों को अंधेरे में ही रात गुज़ारनी पड़ती है. ज़िले में किरासन तेल का भारी संकट है. जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के माध्यम से मिलने वाला किरासन बहुत कम है. एपीएल व बीपीएल सूची में शामिल ग्रामीण परिवार को 3 लीटर और शहरी परिवार को ढाई लीटर किरासन दिया जाता है. इस मात्रा से महीने भर का गुज़ारा कैसे होता होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है. इससे अलग स्थिति यह है कि जिनका नाम न तो एपीएल सूची में है और न ही बीपीएल सूची में. उन्हें सिर्फ़ कालाबाज़ारी मे बिकने वाले किरासन से ही घर में उजियारा मिल सकता है. हालत यह है कि लोग ज्यादा हैं और तेल कम. ठेला वेंडरों को किन कूपनधारियों के बीच किरासन का वितरण किया जाने का प्रावधान है. कहना मुश्किल जान पड़ता है. इसके अलावा सुदूरवर्ती पुलिस थानों के लिए 1 हज़ार 860 लीटर, हाट बाज़ार के नाम पर 6 हज़ार लीटर व सरकारी संस्थानों के मद में 7 हज़ार लीटर किरासन तेल का आवंटन किया गया है. जबकि सरकारी मानकों का अलग मानना है. ज़िले में किरासन तेल के थोक अधिकृत विक्रेताओं की संख्या 17 है, जिन्हें जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं सहित ठेला वेंडरों को अनुदानित दर पर तेल उपलब्ध कराने की ज़िम्मेवारी है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र इधर भी

फरकिया की दीक्षा बनी बिहार टॉपर

खगड़िया ज़िले के फरकिया की दीक्षा ने 2009 की इंटर साइंस परीक्षा में सूबे में पहला स्थान प्राप्त किया है. ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दोबारा मेधासूची जारी करने के बाद दीक्षा को यह सफलता हाथ लगी है. दीक्षा को सर्वाधिक 423 अंक प्राप्त हुए हैं. वहीं उसके सहोदय भाई यतीन्द्र को परीक्षा में दूसरा स्थान मिला है. ग़ौरतलब है कि दीक्षा व यतीन्द्र परबत्ता प्रखंड के नया गांव के रहने वाले हैं.

रोहित बने छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

तेज़ तर्रार युवा नेता रोहित कुमार सिंह को छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र पासवान और बिहार लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सहित पार्टी के कई नेताओं ने रोहित को नई ज़िम्मेदारी के लिए बधाई दी. रोहित ने बताया कि पार्टी ने उनके कंधे पर जो ज़िम्मेदारी सौंपी है, उसका यथाशक्ति निर्वहन करूंगा. उन्होंने कहा कि लोजपा पूरे देश में एक बड़ी ताक़त बनकर उभर रही है और पार्टी की छात्र इकाई इस काम में अब जी जान से जुट गई है. उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे देश में छात्र लोजपा का संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लिया जाएगा.

संगीत व नृत्य कला की शिक्षा ज़रूरी

पटना के डॉ. ज़ाकिर हुसैन संस्थान परिसर में कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर से अंगीभूत आनंद शास्त्री संगीत नृत्य एवं कला महाविद्यालय का उद्‌घाटन किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए पंडित डॉ. नागेन्द्र मोहनी ने कहा कि युवा वर्ग को सामान्य एवं तकनीकी शिक्षण के साथ-साथ संगीत व नृत्य कला की शिक्षा भी ज़रूरी है. रोज़गार प्राप्त करने के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक है तो विवेकपूर्ण व सात्विक जीवनशैली विकसित करने करने के लिए कला व संस्कृति का अध्ययन भी आवश्यक है. समारोह मे आए अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान के महानिदेशक प्रो. डॉ. उत्तम सिंह ने कहा कि महाविद्यालय में ललित कला, नृत्य व संगीत विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरूआत की जाएगी. इस मौक़े पर कुसुम देवी, महाविद्यालय के प्राचार्या आचार्य सीमांचल दास, सुमन कुमार प्रो. डॉ. समीर कुमार सिंह तथा डॉ. जगदानंद झा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए.

सहजानंद सरस्वती याद किए जाएंगे

स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के मौक़े पर दो मार्च को स्थानीय एस.के. मेमोरियल हॉल में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. सम्मेलन का उद्‌घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. मुख्य वक्ता के रूप में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ट नारायण सिंह व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (पीएचईडी) मंत्री चन्द्रमोहन राय उपस्थित रहेंगे. यह जानकारी अयोजन की राज्यस्तरीय तैयारी समिति के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दी. कुमार ने बताया कि सम्मेलन में इस बात पर विशेष चर्चा होगी कि राज्य के कृषि रोडमैप से आम किसानों को किस तरह से जोड़ा जाए. सोमवार को राज्य स्तरीय तैयारी समिति की बैठक में भाजपा प्रवक्ता सुधीर शर्मा व जदयू नेता अजय सिंह टुन्नू भी शामिल हुए. समरोह में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. *-चौथी दुनिया ब्यूरो*

शाहाबाद

कहीं बंजर न हो जाए ज़मीन

सन 1857 की क्रांति के दौरान जब शाहाबाद की धरती ने आग उगलना शुरू किया तब यहां के लोगों को सिंचाई के संसाधन देकर कृषि कार्य की तरफ मोड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक बड़ी परियोजना की शुरूआत की थी. डेहरी के ऐनकार्ट में सोन नदी पर एक बांध बना और पूरे शाहाबाद में नहरों का जाल बिछाने की कवायद तेज़ हुई. धीरे-धीरे पूश एवं राड़ी से भरी पड़ी यहां की धरती ने अंगड़ाई ली और खेतों से अनाज के दाने निकलने शुरू हो गए. कालांतर में देश आज़ाद हुआ और साठ के दशक में इस परियोजना का विस्तार कर इंद्रपुरी में एक बड़े बैराज का निर्माण किया गया. अब इस बैराज से सोन कनाल की पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों ही नहरों से शाहाबाद के रोहतास भोजपूर बक्सर, कैमूर एवं औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल एवं पटना ज़िले के खेतों को सींचा जाने लगा. तब से लेकर वर्ष 2010 तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि किसानों को खरीफ या रवि फसल की पटवन में इतनी मशक्कत करनी पड़ी जितनी उस वर्ष करनी पड़ी थी. रोहतास ज़िले से होकर पश्चिमी कैनाल से होकर जाने वाली वितरणीयों एवं उपवितरणीयों के माध्यम से प्रतिदिन हज़ारों क्यूसेक पानी खेतों को जाता है, जो लक्ष्य के अंदर है. इस वर्ष खरीफ एवं रवि फसल पटवन के लिए केवल पश्चिमी केनाल को मिले पानी को देखा जाए तो वह हमेशा मिलने वाले जल राशि का आधा भी नहीं है. जबकी ज़रूरत के हिसाब से एक चौथाई से कम पड़ेगा. इस वर्ष कम हुई यह जल राशि कोई अचानक घटी घटना नहीं बल्कि, पिछले चार वर्षों से यह कटौती हो रही है. शायद यही कारण है कि राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर दिए जाने वाले डीजल पंप सेट के ख़रीददारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जो यह इंगित कर रहा है की यहां के किसानों को नहरों से मिलने वाले पानी पर भरोसा नहीं है. इस वर्ष रवि फसल में पटवन को लेकर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से क्रमश: रिहन्द एवं वाणसागर जलाशयों ने ज़बरदस्त वादा ख़िलाफ़ी की है. अब तक रवि फसल के दूसरे पटवन तक कुल 5000 क्यूसेक पानी नहीं मिला. अब शाहाबाद के खेतों की नहरें सूख कर रह गई हैं. राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग को जो निर्देश दिए उस हिसाब से फरवरी के दूसरे सप्ताह में रिहन्द एवं वाणसागर परियोजनाओं के अधिकारियों से मिलकर तकनीकी अड़चनों को दूर करते हुए अपनी हिस्सेदारी लेने का प्रयास करें बतातें चले की उक्त समय अवधि तक रवि फसल की पटवन अवधि समाप्त प्राय: हो जाती है. इन परिस्थितियों में वार्ता से निकले परिणाम का किसानों को क्या लाभ मिलेगा. मतलब साफ है. सोन नहर प्रणाली एवं इन्द्रपुरी बैराज से नए सिरे से बचाने के लिए प्रयास नहीं हुए तो समझो धान के कटोरे के रूप में मशहूर हरी भरी शाहाबाद की धरती को बंजर होने में समय नहीं लगेगा. हाल के दिनों में यहां की धान एवं गेंहू की उपज पंजाब के क़रीब पहुंच रही थी. लेकिन भी झारखंड के बंटवारे के बाद शेष बिहार के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत के रूप में देखा जा रहा था. परन्तु इन हलातों में शायद ही इस क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

बदलते दौर में यदि भाषा की बात करनी है तो निश्चित रूप से इस भाषा के साहित्य को आगे लाकर भोजपुरी भाषा का प्रचार प्रसार करना होगा.

कोलकाता में भिखारी ठाकुर फेस्टिवल

भोजपुरी के लिए आवाज़ बुलंद

महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति तथा महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर.आर.पाटिल, माया गोविंद (प्रख्यात रचनाकार) समेत कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में हिंदुस्तान की समस्त क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कल्पना के सम्मान के जरिए भोजपुरी व भिखारी ठाकुर की तरफ़ भी राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया.

राजेश एस कुमार

भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हर भाषा को सरकारी दर्ज़ा हासिल नहीं होता है. हालांकि, किसी भी भाषा को दर्ज़ा मिलने का पैमाना उस भाषा को बोलने वालों की संख्या पर भी निर्भर करता है. अगर इस आधार पर भी उस भाषा को उसका दर्ज़ा हासिल न हो तो इसे अन्याय नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे. इसी अन्याय की शिकार एक भाषा भोजपुरी भी है. भोजपुरी भाषा को लेकर आज उत्तर भारत समेत संपूर्ण विश्व में चाहे जितने ज़ोर-शोर से बातें की जाएं, लेकिन यह सारी बातें तब तक निरर्थक हैं जब तक हिंदुस्तान में बोली के रूप में सिसक रही भोजपुरी को भाषा का दर्ज़ा दिलाने की सही लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी.लेकिन अब कुछ लोग आगे आए हैं, जिन्होंने भोजपुरी को उसका अधिकार दिलाने के लिए कमर कस ली है. इसमें राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन (डब्ल्यूएजेए) का नाम प्रमुख है. बदलते दौर में यदि भाषा की बात करनी है तो निश्चित रूप से बातूनी कटघरों को तोड़ इस भाषा के साहित्य को आगे लाकर भोजपुरी भाषा का प्रचार-प्रसार करना होगा. और इसके लिए भिखारी ठाकुर तथा उनकी रचनाओं से बड़ा हथियार भला और क्या हो सकता है? इसी को ध्यान में रखते हुए देश के समस्त रचनाकारों के सम्मान-स्वाभिमान एवं विभिन्न भाषा-साहित्य के विकास हेतु दृढ़ संकल्पित राष्ट्रीय स्तर पर रचनाकारों-पत्रकारों का साझा मंच राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन (डब्ल्यूएजेए) इस मामले में बेहद गंभीर है. इसीलिए वह भोजपुरी के उत्थान हेतु कार्य कर रहे प्रबुद्धजनों व संस्थाओं का इस संबंध में खुला समर्थन करता है. पिछले दिनों 18 दिसंबर 2010 को भिखारी ठाकुर के जन्मदिवस पर पटना में देश के भविष्य आईआईटियंस को प्रमोट कर रही विजन क्लासेज के साथ राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अपनी संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की थी कि भिखारी ठाकुर को नई पीढ़ी के समक्ष सही ढंग से प्रस्तुत कर उनके साहित्य को वैश्विक प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत है. इसके लिए प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका कल्पना अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट द लीगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर के माध्यम से एक सार्थक पहल कर रही हैं. भविष्य में ऐसी अनेक पहल शुरू हों और भिखारी ठाकुर व उनके साहित्य के ज़रिए भोजपुरी भाषा मान्यता की राह में कुछ क़दम आगे बढ़ सके. इसी को ध्यान में रखते हुए राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पटना की यह कांफ्रेंस नई पीढ़ी की नई सोच व स्थानीय स्तर पर इस पहल को समर्थन देने वाले जनांदोलन की पहली कड़ी के रूप में की.

इसी तरह राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने वाईबी चौहान सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में राष्ट्रीय स्तर पर लेखकों-पत्रकारों के स्नेह सम्मेलन के दौरान पटना व मुंबई के बाद तीसरे चरण में राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन आगामी 15 मार्च 2011 को कला मंदिर, थिएटर रोड कोलकाता में भिखारी ठाकुर फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है. जिसमें भिखारी ठाकुर व उनके विचार साहित्य को आगे बढ़ाने वाली देश की कई प्रख्यात हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा और भोजपुरी साहित्य में भिखारी ठाकुर के योगदान पर संपूर्ण चर्चा की जाएगी. इस समारोह में विश्व भोजपुरी उत्थान सेवा संस्थान समेत कई स्थानीय संस्थाएं तथा कई बड़ी इवेंट कंपनियां राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोशिएशन के कंधे से कंधा मिलाते हुए इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं.

मुंबई से उक्त बयान जारी करते हुए राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी के मुताबिक़ कोलकाता का यह भिखारी ठाकुर फेस्टिवल कई मायनों मे बहुत ख़ास है. सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजाराम मोहन राय और विवेकानंद जैसी प्रतिभाओं ने कोलकाता में ही नव जागरण का पाठ सीख कर समूचे भोजपुरी भाषियों को अपने क्रांतिकारी विचारों से अभिसिंचित किया था. ऐसे में भोजपुरियों के चहेते शहर कोलकाता में होने वाला यह भिखारी ठाकुर फेस्टिवल न केवल भोजपुरी बेल्ट में नई क्रांति लाएगा बल्कि कई मायनों में ऐतिहासिक भी होगा. जिस तरह से लोग एकजुट हुए हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि इस भिखारी फेस्टिवल के ज़रिए भोजपुरी की आवाज़ सही तरीक़े से उठेगी.

rajeshy@chauthiduniya.com

ग़रीबों का अनाज बंगाल की मंडियों में

किशनगंज

नीरज कुमार सिंह

जहां बिहार की ग़रीब जनता खाने के लिए एक-एक दाने को मोहताज है वहीं किशनगंज में जनवितरण प्रणाली व एसएफसी के ठेकेदार ग़रीब जनता का हक़ मारकर अनाज को कालाबाज़ारी द्वारा किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के रामपुर व पांजीपाड़ा की मंडियों में पहुंचा रहे हैं. मालूम हो कि सरकार ने ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो के लिए लाल कार्ड व पीला कार्ड दे रखा है. इसके तहत अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के द्वारा सस्ती दर पर अनाज को जनवितरण प्रणाली के माध्यम से ग़रीबों के बीच वितरित किया जाता है. ताकि इन ग़रीबों को समुचित मात्रा में प्रत्येक माह चावल एवं गेहूं मिल सके. लेकिन दुकानदारों की मिलीभगत से अनाज माफिया किशनगंज से बंगाल की 5-6 किलोमीटर की दूरी को आनन-फानन में वाहनों द्वारा तय करवाकर अनाज को बंगाल की मंडियों में पहुंचा देते हैं. ऐसा ही एक मामला विगत माह किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी ने खगड़ा गुमटी के पास पकड़ा, जब पांच ट्रैक्टर पर लोड सरकारी गेहूं रामपुर की मंडी में बिकने जा रहा था. अनुमंडल पदाधिकारी दो ट्रैक्टर पकड़ कर थाने में ले आया, जबकि तीन ट्रैक्टर माल पहले ही रामपुर मंडी पहुंच चुकी थी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज के बाज़ार समिति सह पुलिस लाइन स्थित एसएफसी के गोदाम से गेहूं को डीलरों के घर पर जाना था, लेकिन गेहूं रामपुर (बंगाल) मंडी बिकने के लिए जा रहा था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज में राशन माफिया प्रशासन पर काफी हावी है. इस खेल में दबंग तो शामिल हैं ही, इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ कई सफ़ेदपोश राजनेता शामिल हैं, जिनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में आमलोग तो क्या प्रशासन भी कार्रवाई से बचता है. अत: सुशासन में ग़रीब जनता को उसका राशन और वाजिब हक़ कैसे मिले, सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

हम निम्नलिखित में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं:

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी
मास्टर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
मास्टर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक*
मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी*
एम. एड. (स्पेशल एजुकेशन)*

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम
बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी
बैचलर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
बैचलर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी
बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन)
बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ रेडियोइमेजिंग टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ बायो-टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ ऑफ्थालमोलॉजी

डिप्लोमा पाठ्यक्रम
डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी
डिपलोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
डिप्लोमा इन हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट
डिप्लोमा इन ओ.टी.असिस्टेन्ट
डिप्लोमा इन इ. सी. जी.
सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसींग

डी.पी.टी./डी.ओ.टी. के लिये १ वर्षीय अवॉर्ड्ड डिग्री इन

Anil Sulabh
Director-in-Chief

फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290, www.iiher.ac.in

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
मगध विश्वविद्यालय बोधगया

डॉ. इसराईल खां
निदेशक

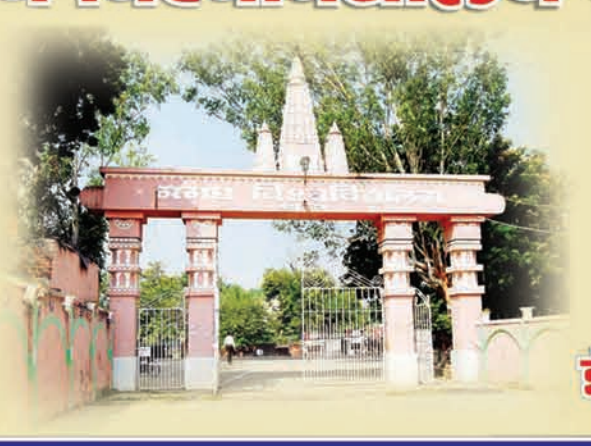

डॉ. अरविन्द कुमार
कुलपति

"Open Universities are veritably the new temples of Learning, responding to new needs"

इस नारा के आलोक में मगध विश्वविद्यालय परिसर अन्तर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई। यह संस्थान दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने अल्प काल में ही काफी लोकप्रियता हासिल की है। वर्तमान में विद्वान कुलपति प्रो. (डॉ.) अरविन्द कुमार के निर्देशन में यह संस्थान अपने सामाजिक दायित्व का भरपूर निर्वहन करते हुए समाज को योग्य एवं अनुभवी शिक्षक प्रदान कर रहा है ये शिक्षक नौनिहालों को शिक्षित कर देश का भविष्य संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) के साथ-साथ **B.LIS : Bachelor of library & Information Science, MBA, MCA, BCA, CCA, TTM : Tourism & Travel Management, HRM : Human Resource Management, FM : Financial Management ,Marketing Management., Mass Communication and Journalism, M.A. in Education, M.LIS : Master in library & information Science** इत्यादि का अध्ययन छात्र-छात्राओं को प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त **Biotechnology, Physiotherapy, Hotel & Hospitality Management, Foreign languages, Mass Comunication & journalism, PG in Maghi, Food & Nutrition** इत्यादि Course भी विश्वविद्यालय की गरिमा में चार चांद लगा रहे हैं। 25 वर्ष के बाद दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन वर्तमान कुलपति डॉ. अरविन्द कुमार की बड़ी उपलब्धि है। विश्वविद्यालय 2011 सत्र से एम.एड. की पढ़ाई आरम्भ करने के लिए अपने स्तर से पूरी तैयारी कर चूका है। केवल **NCTE** से अनुमति का इन्तजार है। तीन वर्ष के अर्न्तकाल में ही दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने अपना भव्य भवन ,सुसज्जित **Class Room** 200 सीट का सेमिनार हॉल बनाकर दूरस्थ शिक्षा को नया आयाम दिया है।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

दिल्ली, 21 फरवरी–27 फरवरी 2011 www.chauthiduniya.com

योजना और स्वास्थ्य दोनों से खिलवाड़

ग्राम्य विकास विभाग ने हेल्प लाईन नंबर शुरू किया है लेकिन इसका विज्ञापन ग्रामीण क्षेत्रों के अख़बारों के स्थान पर शहरी क्षेत्रों के अख़बारों में छपवाकर बजट को ख़र्च कर डाला है.

ग्रामीणों का कहना था कि ब्लॉक मुख्यालय की स्मार्ट कार्ड बनाने वाले टीम ने वर्ष 2010 फरवरी में स्मार्ट कार्ड बनाए थे. पर जब उन्हें स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत आती तो वह केवल एक कोरा काग़ज़ सिद्ध होते है.

स्मार्ट कार्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, योजना का लक्ष्य तो सकारात्मक है लेकिन इसमें सरकारी अस्पतालों को न के बराबर समाहित किया गया है.

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश में पांच वर्ष पूर्व लागू राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में कार्ड बनवाने से लेकर इलाज कराने तक की राह में रोड़े ही रोड़े नज़र आ रहे हैं. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना को लेकर किए जा रहे बड़े–बड़े दावे धराशाई होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य था अनौपाचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली प्रणाली को सुनिश्चित करना लेकिन इतने वर्षों के बाद भी यह योजना जनमानस को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में नाक़ाम रही है. केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना में सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन में पंचायतों को प्रभावी भूमि सौंपी जानी थी. जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण समिति के माध्यम से ग्राम सभा स्तर पर एएनए, एमपीएचडब्ल्यू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवियों को पंचायतों के दायरे में रहकर ग्रामीण लोगों को अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था. सरकारी अस्पतालों का प्रबंधन ज़िला पंचायतों के माध्यम से किया जाना था. पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लाल फीताशाही के साथ–साथ बजट व प्रशिक्षण के अभाव में इस योजना के क्रियान्वयन की स्थिति शाख़ के तीन पात वाली है. ग़रीबों के परिवारों का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जाना था, परंतु इसके क्रियान्वयन की स्थिति चिंता का सबब बन गई है.

ग़रीब और बेसहारा परिवारों को आज भी उक्त योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से सक्षम तबका सरकारी तंत्र से सांठ–गांठ कर नि:शुल्क बीमा सुविधा का लाभ उठा रहा है. कहने को ग्राम्य विकास विभाग ने हेल्प लाईन नंबर की सुविधा शुरू की है. लेकिन इस सुविधा का विज्ञापन ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले ग्रामीण अख़बारों के स्थान पर राजधानी तथा शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी और हिंदी के रंगीन समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाकर बजट को पूरा ख़र्च कर डाला है. इस मिशन द्वारा प्रदेश में संचालित करने वाली नौकरशाही का उद्देश्य मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री की नज़रों में बना रहना है. ग्रामीण जनता स्मार्ट कार्ड के बारे में जाने या न जाने उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सरकारी दावे में कहा गया है कि प्रदेश के सभी स्मार्ट कार्ड धारक हेल्प लाईन (09198004444) पर फोन कर योजनांतर्गत इंपैनल्ड (सूचीबद्ध) अस्पतालों से, मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए एंबुलेंस की नि:शुल्क सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. योजनांतर्गत कार्यरत प्रथम चरण में 12 बड़े अस्पतालों में मरीज का इलाज एवं अस्पताल के संबंध में उनके अपने अनुभव बयान करने के लिए वीडियो बूथ की व्यवस्था है लेकिन इस व्यवस्था की पोल परत दर परत खुलने लगी है.

प्रदेश में स्मार्ट कार्ड्स में फ़र्ज़ीवाड़ा की समस्याएं सर उठाने लगी है. कन्नौज ज़िले के ताल ग्राम ब्लॉक से रावेंद्र पुत्र मलिखान, सुरेंद्र पुत्र बाबू राम, अजय पाल पुत्र अतर सिंह, ओम प्रकाश पुत्र गजाधर, जदुवीर पुत्र राम सनेही, मदन लाल पुत्र भरत सिंह, सरमन सिंह पुत्र रामादीन आदि तमाम ग्रामीण अपने–अपने स्मार्ट कार्ड लेकर मुख्यालय पर पहुंचे. इन ग्रामीणों का कहना था कि ब्लॉक मुख्यालय की स्मार्ट कार्ड बनाने वाले टीम ने वर्ष 2010 फरवरी में स्मार्ट कार्ड बनाए थे लेकिन उनके साथ धोख़ा किया गया. जब उन्हें स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत आती तो वह केवल एक कोरा काग़ज़ सिद्ध होते हैं. जब इन ग्रामीणों ने स्मार्ट कार्ड बनाने वाली टीम से बात की तो उन्होंने भी इन काड्र्स को फ़र्ज़ी करार दिया. ग्रामीणों का कहना था कि 50 से अधिक कार्डधारक धांधली का शिकार हुए हैं. वहीं यह ग्रामीण मानव विकास संस्थान के निदेशक अजय पांडे से भी मिले. पांडे ने ग्रामीणों की सीडीओ से मिलने की मांग पर मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता की. उन्होंने समस्या को सुनकर तुरंत समाधान का आश्वासन भी दिया. दूसरी ओर अंबेडकर नगर के स्मार्ट कार्ड धारकों को निज़ी चिकित्सालयों में इलाज कराना काफ़ी भारी महसूस हो रहा है. कार्डधारकों का मानना है कि निज़ी चिकित्सकों द्वारा बाउचर बनवाने से आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्ड के खाते से निकाल लिया जाता है क्योंकि कार्डधारकों को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं.

स्मार्ट कार्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, इसमें सारी योजना का लक्ष्य तो सकारात्मक सोचकर रखा गया लेकिन इसमें सरकारी अस्पतालों को न के बराबर समाहित किया गया, केवल प्रत्येक ज़िले के ज़िला अस्पताल को इस सुविधा के अंतर्गत चयन किया गया. स्मार्ट कार्ड धारकों के इलाज के लिए अगर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया होता तो शायद इस योजना में बंदरबांट की यह स्थिति देखने को नहीं मिलती.

इस योजना के संचालन में सरकार की चूक आम आदमी के लिए परेशानी का कारण बन गई है. योजना द्वारा निज़ी चिकित्सालयों की तरफ़ किसी भी अधिकारी या विभाग की नज़र नहीं पड़ रही है. निज़ी चिकित्सालयों की अंधेरगर्दी में ख़ूब चांदी कट रही है. इस बात का ख़ुलासा तब हुआ जब पता चला कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बनारस के एक निज़ी अस्पताल में मृतकों का इलाज किया गया. इलाज के नाम पर अस्पताल संचालक ने 1.42 करोड़ रुपए डकार लिए. अभी 10 लाख रुपए का भुगतान होना बाक़ी था. इसकी शिकातय हुई तो ग्राम्य विकास आयुक्त ने गोपनीय तरीक़े से बनारस और जौनपुर टीम भेजकर जांच कराई और आरोप पुष्ट होने पर स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया. शिव सर्जिकल सेंटर के संचालक डॉ. एसपी यादव के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ हो गया. सारनाथ थानाध्यक्ष शिव शंकर सिंह के मुताबिक़ ज़िला विकास अधिकारी (डीडीओ) की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज़ हुई. जांच में अगर अस्पताल के अन्य लोग संलिप्त मिले तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी. उधर, शहर के तीन और निज़ी अस्पतालों के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के फ़र्ज़ीवाड़े की छानबीन हो रही है. ज़िले में अब तक इस योजना के तहत हुई नौ करोड़ 36 लाख रुपए की कुल निकासी की भी जांच शुरू हो गई है. जांच से पता चला है कि जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के बांसवारी गांव के 18 लोगों को ब्रेन हीमोटोमा का शिकार बताकर फ़र्ज़ी तरीक़े से उनके नाम हेल्थ स्मार्ट कार्ड बना कर 1.42 करोड़ रुपए हड़प लिए गए. 18 कथित रोगियों की सूची में गांव के पांच ऐसे लोगों का नाम है जिनका दो साल पूर्व ही निधन हो चुका है, जबकि, सात लोग ऐसे है जो इस गांव के नागरिक ही नहीं है. चार लोग गांव के तो हैं मगर उन्होंने इस अस्पताल में उपचार कराया ही नहीं, जबकि, दो ने किसी अस्पताल में इलाज नहीं कराया.

18 लोगों का फ़र्ज़ी तरीक़े से बनाया गया कार्ड और बिल भुगतान की जानकारी पिछले अक्टूबर माह में ही लखनऊ के अधिकारियों को इंटरनेट के ज़रिए मिल गई थी. ग्राम्य विकास आयुक्त के निर्देश पर नवंबर में गांव गई टीम ने जांच के बाद पूरे मामले का ख़ुलासा किया. 11 जनवरी 2010 को ज़िले में बीपीएल श्रेणी में शामिल लोगों के लिए स्मार्ट कार्ड बनने शुरू हुए थे. प्रथम चरण में इसके लिए शहर के 79 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया. जून तक 91 हज़ार 43 ग़रीबों के उपचार के लिए शहर के 105 अस्पताल चयनित किए गए. अगस्त और नवंबर में कुछ अस्पतालों के संचालकों की मिलीभगत से फ़र्ज़ी निकासी की शिकायत मिली. शासन के निर्देश पर हैदराबाद से आई तीन सदस्यीय टीम ने अस्पतालों का भौतिक सत्यापन किया था. राजधानी से लगे बाराबंकी जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आज निज़ी नर्सिंग होम्स की अवैध कमाई का ज़रिया बन गई है. ग़रीब कार्ड धारकों का ज़बरदस्त शोषण किया जाता है. शिकायत करने पर अधिकारी एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराते हुए सिर्फ़ खानापूर्ति करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते है. हालात इतने गंभीर है कि इलाज के नाम पर परिवार को मिले 30 हज़ार रुपए उनके खाते से किसी न किसी बहाने निकाल लिए जाते हैं. मरीजों को भगवान के सहारे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है. इस योजना में धांधली और भ्रष्टाचार का खेल उसी वक्त शुरू हो जाता है जब नियमों और मानकों को दरकिनार कर ऐसे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को मंजूरी दे दी जाती है जिनके पास इलाज के संसाधन भी नहीं है. इलाज के लिए डॉक्टर और प्रशिक्षित कर्मचारी तक नहीं हैं. लापरवाही और मरीज का समुचित इलाज न हो पाने के कारण इलाज की आस में अस्पताल आए मरीजों की मौत तक हो जाती है. अभी हाल ही में नगर के एक प्रतिष्ठित नर्सिंग होम ने राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना के कार्ड पर पेट में पथरी का ऑपरेशन कराने आई महिला चंपा के कार्ड से 13 हज़ार रुपए निकल लिए और जब महिला की हालत बिगड़ी तो मानवता की सारी हदों को पार करते हुए डॉक्टरों ने महिला को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद बेहद ग़रीब और दर–दर इलाज के लिए भटकती हुई महिला ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया. ग्रामीण विकास मंत्री दद्दू प्रसाद सरकार की संवेदनशीलता के विषय में कहते हैं कि वाराणसी में घोटाला पकड़ा है, आगे भी जहां शिकायत मिलेगी किसी को बक्शा नहीं जाएगा.

ग्राम विकास सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं, इनमें कहा गया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2008 से प्रथम चरण के 15 जनपदों में प्रारंभ किया गया. अब यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत अभी तक प्रदेश में कुल लगभग डेढ़ लाख बीमा दावे प्रस्तुत हुए हैं अर्थात एक लाख से अधिक व्यक्तियों का योजनांतर्गत इलाज करते हुए कुल 118 करोड़ रुपए के बीमा दावे प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके सापेक्ष 80 करोड़ रुपए का भुगतान सेवा प्रदाता अस्पतालों को किया गया है. वर्तमान में योजनांतर्गत प्रदेश में जनपद के कुल 158 सरकारी तथा 886 प्राइवेट चिकित्सालय है. योजना के मुख्यत: चार स्टेक होल्डर्स है: राज्य सरकार, बी.पी. परिवार, बीमा प्रदाता कंपनी, सेवा प्रदाता अस्पताल.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

राजधानी से लगे बाराबंकी जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आज निज़ी नर्सिंग होम्स की अवैध कमाई का ज़रिया बन गई है. ग़रीब कार्ड धारकों का जबरदस्त शोषण किया जाता है. शिकायत करने पर अधिकारी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए सिर्फ़ खानापूर्ति करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं. हालात इतने गंभीर है कि इलाज के नाम पर परिवार को मिले 30 हज़ार रुपए उनके खाते से किसी न किसी बहाने इलाज के नाम पर निकाल लिए जाते हैं .

उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से अब तक दर्जन भर से अधिक बाघ को वनाधिकारियों ने गोली का निशाना बनाया है.

बुजुर्ग यह बताकर चुप हो जाते हैं कि यहीं कहीं पंडित नेहरू जन्मे थे. बुजुर्ग स्वामी सरन बताते हैं कि नेहरू जी ने यहीं जन्म लिया था, ऐसा वह सुनते आए हैं.

उत्तराखंड

ख़तरे में बाघ

राजकुमार शर्मा

देहरादून में एक युवक पर हमला करने वाले बाघ को मार डाला गया. कुछ दिनों पहले यहां वन विभाग ने एक बाघिन को आदमखोर घोषित किया था. वन्यजीव प्रेमियों कि माने तो यहां वन्यजीव और मानव संघर्ष के बढ़ते घटनाओं के उचित कारणों पर भारत सरकार एवं सूबे के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. वन क्षेत्र में मानवीय दख़ल के कारण ही उत्तराखंड के बाघ आदमखोर हो रहे हैं. वन विभाग ने बाघ को मार गिराने का फ़ैसला कोसी सुंदर खाल के उग्र नागरिकों के समक्ष घुटना टेकते हुए किया. सुंदर खाल गांव में रिस्तेदारी में आए पूरन(26)पुत्र भूपाल अपनी नानी के घर आया था. शाम को वह कोसी नदी की तरफ़ गया था कि बाघ के जद में आ गया. बाघ ने घबड़ा कर भाग रहे युवक को अपना निवाला बना लिया. इस घटना की सुचना मिलते ही इलाके के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर जाम लगा दिया. बढ़ती आबादी के घनत्व ने मानव को वन में दाख़िल होने की एक ख़तरनाक शुरुआत कर दी है. देवभूमि हिमालय के वन क्षेत्र में जिस तरह मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है, उससे गिनती के बचे बाघ कभी शिकारी तस्करों के कुदृष्टि के शिकार हो रहे हैं तो कभी मानवीय आक्रोश से तंग वनाधिकारियों और शिकारियों की गोली के शिकार हो रहे हैं. वनाधिकारी जनता को समझाने जनता की वन्य जीवों के प्रति उपज रही ग़िवांस को कम करने का प्रयास नहीं करते. वे सीधे वन्य जीव को ही अपनी गोली का शिकार बनाते हैं. उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से अब तक दर्जन भर से अधिक बाघ को वनाधिकारियों ने गोली का निशाना बनाया है. वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि कार्बेट की सीमांत गांव के लोगों ने अपने विकास में दख़ल रखने वाले 91 बाघों को आदमखोर घोषित कर रखा है. राज्य में कुल 178 बाघों की सरकारी सूचना है, जिसमें लगभग 150 बाघ नेशनल कार्बेट पार्क में मौजूद बताए जाते हैं. वन विभाग अगर इन बाघों को मिटाने की अपनी नीति पर काम करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बाघ कस्तूरी मृग की स्थिति में पहुंच जाएंगे.

वनाधिकारियों का मानना है कि इस एनकाउंटर में वन के अधिकारियों ने ऐके–47 का प्रयोग करके ही संज्ञेय अपराध किया है. इस घटना से जुड़े लोग हाथी पर सवार बाघ के शव के साथ जिस तरह उक्त असलहा लहरा कर अपने पराक्रम का संदेश दिया था वही चित्र एवं शिकारियों के बयान वनाधिकारियों के गले का फांस बन गया है. सूबे की सरकार बाघों के संरक्षण में भी पूरी तरह असफ़ल सिद्ध हो रही है.

feedback@chauthidunya.com

राज्य में कुल 178 बाघों की सरकारी सूचना है, जिसमें लगभग 150 बाघ नेशनल कार्बेट पार्क में मौजूद बताए जाते हैं. वन विभाग अगर इन बाघों को मिटाने की अपनी नीति पर काम करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बाघ कस्तूरी मृग की स्थिति में पहुंच जाएंगे.

आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे किसान

राकेश यादव

कृषि ऋण माफी पैकेज–2008 के तहत किसानों को केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा 60 हज़ार करोड़ रुपए पैकेज के उपयोग से संबंधित क्रियान्वयन के नीतियों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न होकर जब नाबार्ड द्वारा किया गया तो हर किसान चौंक गया. यह फ़ैसला नाबार्ड और सरकार की मिलीभगत का परिणाम था या मात्र केंद्र सरकार के निर्देश पर नाबार्ड द्वारा लागू किया गया था, इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा आज देश के हर इस किसान को है. उस किसान को, जो इस ऋण माफी के माध्यम से ख़ुद को ऋण मुक्त होने का सपना देख रहा था. लेकिन आज परिणाम ठीक उसके हितों के विपरीत सामने आए. किसान जो अपनी हैसियत व ईमानदारी से ऋण की किस्तों की अदायगी करते रहे वे इस ऋण माफी से आख़िर क्यों महरूम हो गए. अब इनके समक्ष ऋण अदायगी का विकल्प आत्महत्या के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा है. कृषिप्रधान देश भारत में आज़ादी के बाद से अब तक जिस तरह राजनेताओं व सरकारों द्वारा किसानों का शोषण हुआ, शायद ही विश्व में कहीं हुआ हो. अन्नदाता की संज्ञा से विभूषित किसान शोषण की पराकाष्ठा को छूते–छूते अब क़र्ज़ की मार के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है. ऐसे में क़र्ज़ और किसान की दशा और दिशा का सिंहावलोकन किया जाना स्वाभाविक ही आवश्यक है. शायद इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस की गत मनमोहन सिंह सरकार ने ठीक आम चुनावों के पहले क़र्ज़ माफी को ही मुद्दा बनाकर देश के किसानों के लिए 60 हज़ार करोड़ रुपयों का पैकेज देकर अब कोई किसान ऋणी नहीं रहेगा जैसा अति महत्वाकांक्षी और लुभावने नारे उद्घोषित किया. इस संदर्भ में एक समाचार पत्र में 2 मार्च 2008 को प्रकाशित चार बिंदुओं के विज्ञापन में प्रकाशित अंश जिसका हिंदी रूपांतरण–आज़ादी के बाद से अब तक पहली बार एक ऋण माफी पैकेज जो किसानों को जीवन की नई दिशा प्रदान करता है, पर ज़रा नज़र डालिए–

1. किसानों को लगभग 60 हज़ार करोड़ का ऋण राहत पैकेज,

2. 50 हज़ार करोड़ रुपए लघु एवं सीमांत श्रेणी के उन किसानों के लिए जिन्होंने फ़सलों, कुंओ, पाइप लाइन, बिजली मोटर, पशुधन, फल उत्पादन और मत्स्य पालन आदि के लिए ऋण लिए हैं. यह लाभ देश के लगभग 76 प्रतिशत किसानों को होगा.

3. इसके अतिरिक्त 10 हज़ार करोड़ रुपए शेष, इन किसानों को 25 प्रतिशत छूट के रूप में देय होंगे जो कुल ग्रहीत ऋण की एक मुश्त अदाएगी करेंगे.

4. यह ऋण माफी पैकेज उन किसानों के लिए लागू होगा जिन्होंने 31 दिसंबर 2007 तक ऋणों का आहरण किया है.

ग़ौरतलब है कि उक्त निर्धारित तिथि 31 दिसंबर 2007 तक के ऋण के साथ कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि किसी किसान ने 2007 से पहले कब ऋण लिया था. यही कारण है कि दस बीस सालों से क़र्ज़दारी में चले आ रहे किसानों में यह हर्ष अनुभूत किया गया था कि अब वे ऋण मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. कारण यह कि बाद में नाबार्ड द्वारा यह तय किया गया कि 31 मार्च 1997 से 31 दिसंबर 2007 तक के बीच के आहरित ऋणों की ही माफी होगी. कालांतर में इसे 31 मार्च 1997 को गुप–चुप ढंग से जुलाई 1997 कर दिया गया. 2 अक्टूबर 2007 को केंद्रीय कृषि मंत्री का कथन था कि मैं कृषि कार्य बंद कर देने के बारे में नहीं पूछ रहा हूं बल्कि समय आ गया है, यह निश्चित करने का कि कितने लोग किसानी चालू रखना चाहते है. 10 फरवरी 2008 में पुन: कृषि मंत्री का यह बयान आया कि किसान के यहां जन्म लेने के नाते मैं किसानों की समस्याओं को भली भांति समझता हूं. इन कथनों के साथ पुन: यह कहा जाना कि हम किसानों को लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कांग्रेस का यह प्रचार कि जब औरों ने सिर्फ़ आश्वासन दिए तो हम किसानों के जीवन के लिए नया प्रकाश लेकर आए हैं आदि जैसे मनमोहक विज्ञापन यथार्थ के अंश को भी नहीं छू सके.

फ़ैजाबाद जनपद और समीपवर्ती अन्य जनपदों के कृषकों की बेबाक़ टिप्पणी फ़ायदा बेईमानों को मिला ईमानदार तो देखते रह गए, जिसने ऋण जमा करने की ईमानदारी दिखाई वह अपात्र और जिसने कभी न जमा करने की बेईमानी बरती वे पात्र माने गए. यहां जिसका लेना कभी न देना की धारणा यथार्थ हो उठी और अन्नदाता फिर एक बार महाछल का शिकार हुआ.

इस संबंध में एक वयोवृद्ध कृषक शिवराम शुक्ल अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह फ़ैजाबाद की मिल्कीपुर तहसील के एक पढ़े–लिखे किसान हैं. उन्होंने बतौर लघुजोत किसान के स्थानीय इनायत नगर स्थित ग्रामीण बैंक से क़र्ज़ लिया था. वे कहते हैं कि सरकार द्वारा 22 जनवरी 2008 को ऋण माफी योजना जिस तरह जारी की गई, इसका इतना छोटा परिणाम होगा इसे हम क़र्ज़दार किसान नहीं जानते थे. ऋण माफी योजना से सरकार के कथनानुसार 76 प्रतिशत किसानों के लाभान्वित होने के ठीक विपरीत 70–80 प्रतिशत किसान इस ऋण माफी से वंचित रह गए. इन किसानों का अपराध महज़ इतना था कि बैंकों के ब्याज व आरसी जारी होने से बचने तथा अपना मान–सम्मान बचाने की गरज से 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2007 के बीच इन्होंने कुछ रक़म जमा कर दी थी. दिशा निर्देश बनाने वाली समिति ने सरकार की घोषित मंशा पर पानी फेर दिया. कृषकगण बैंको में चस्पा सूची ही देखते रह गए. शुक्ल कहते हैं कि उनका तो क़र्ज़ माफी सूची में नाम भी था, लेकिन उन्हें क़र्ज़ माफी नहीं मिली. वे दिशा निर्देश के स्वतंत्र अनुच्छेद 5–(1) का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि छोटे व मझोले जोत के किसानों की पूर्ण ऋण माफी होनी चाहिए थी. अनुच्छेद 13 (1) व 13 (2) का उल्लेख करना वह नहीं भूलते. जिसमें कहा गया है कि यदि किसी अनुच्छेद को लागू करने में कोई बाधा आती है तो भारत सरकार उसे दूर करेगी. क़र्ज़ का माफ न होना हम जैसे क़र्ज़दार किसानों के लिए सबसे बड़ी बाधा थी और इस बाधा को किसी बैंक ने शायद सरकार के संज्ञान में नहीं डाला, जब सरकार को कुछ जानकारी मिली भी तो उसने 2 मार्च 08 को एक नोटीफिकेशन जारी कर 31 दिसंबर 07 के सभी किसानों को शामिल कर लिया. लेकिन इसकी भी बैंकों ने अनदेखी ही की. जब कृषक शिवराम शुक्ल ने अपनी पात्रता का हवाला देते हुए 21 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया, तब 6 महीने बाद न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाने के बाद बैंक ने अपना जवाब दावा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. यह याचिका स्वीकृत होकर निर्णय हेतु लंबित है. शिवराम शुक्ल कहते हैं कि उन्होंने कृषि ऋण 2005 में लिया है और वे पूर्णत: कृषि ऋण माफी के पात्र है. इस श्रृंखला में पात्र होकर भी अपात्र ठहराए गए कुछ अन्य कृषकों में फ़ैजाबाद के श्रीपाल सिंह पुत्र तेजवंत सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट रूरूवा वैश्य, जिनका पंजाब नेशनल बैंक आस्तीकन शाखा से आहरित ऋण राशि 75 हज़ार रुपए है. जीत नाथ पांडेय निवासी इनायतनगर, एक ऐसे कृषक हैं जिन्हें पूर्ण ऋण माफी के बाद नोड्यूज प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है लेकिन उनसे अब इस नोड्यूज को ग़लत कहकर बैंक द्वारा बकाया धनराशि जमा किए जाने का बार–बार दबाव बनाया जा रहा है. जनपद फ़ैजाबाद से इतर जनपद अंबेडकरनगर के त्रिलोक नाथ तिवारी पुत्र जगन्नाथ भी पीएनबी शाखा गोठवल के ऋणी हैं और अपने को पात्र होते हुए भी ऋण माफी से वंचित बताते हैं. ऐसे दर्जनों किसान हैं जो ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, पीएनबी बैंक, केनरा बैंक जैसी शाखाओं के आज भी ऋणी हैं. फ़ैजाबाद में पंजाब नेशनल बैंक शाखा की बात करें तो यहां के शाखा प्रबंधक किसानों के बारे में कुछ कहने के नाम पर मुंह खोलना भी उचित नहीं समझते. इस शाखा की गतिविधियों के बारे में खाता धारकों का कहना है कि बैंक द्वारा उनके खातों में जमा निकासी स्वत: ही कर ली जाती है और उसके खातेदारों को पता ही नहीं चलता. गत जनवरी माह में फ़ैजाबाद के ही मिल्कीपुर तहसील के दो किसानों द्वारा ऋण के बोझ से ऊब कर आत्महत्या कर लिए जाने के समाचार ने संपूर्ण जनपद के किसानों को हिलाकर रख दिया है. बताते चलें कि उक्त ऋण माफी योजना के फलस्वरूप आम किसानों में यह धारणा भी अब पूर्णतया बलवती हो चली है कि यदि उन्होंने बैंकों को क़र्ज़ की रक़म कुछ भी न लौटाई होती तो वे भी ऋण माफी योजना का लाभ पाते. तो अब इसी का अनुसरण क्यों न किया जाए. इसी का परिणाम है कि अब बैकों को ऋणों की वसूली में पसीना आ रहा है और किसानों को आरसी की नोटिसों के चलते छिपने का ठिकाना नहीं मिल रहा है. इसकी स्वीकारोक्ति के रूप में जनपद के कई बैंकों के अधिकारियों ने बताया कि कतई ऋण अदायगी न करने का मन बना चुके किसानों से वसूली कर पाना अब असंभव सा लग रहा है. ऐसे में अपेक्षित वसूली के अभाव में पुन: ऋण वितरण कर पाना भी हमारे लिए समस्या बनकर सामने आ रही है. जिस प्रकार क्रय शक्ति के ह्रास के कारण बाज़ारों में माल उपलब्ध होने के बावजूद व्यापारियों के सामने अपेक्षित विक्रय न होने की विकराल समस्या आई है, ठीक उसी प्रकार खेती में नुक़सान उठा चुके किसान पुराने ऋणों की अदायगी कर सकने में पूर्णतया असमर्थ हैं. मौजूदा अलाभकारी और महंगी खेती को चालू रखने के लिए उन्हें सिर्फ़ एक ही विकल्प दिखाई पड़ता है कि उन्हें एक बार ऋण माफी मिले और इसके लिए आम किसान बड़ी आशा भरी निगाहों से सकरार की ओर देख रहा है.

इसके अलावा अब समय आ गया है कि वह इस सत्तारूढ़ सरकार से कड़ाई और प्रभावी ढंग से पूछ पूछें कि आपके वायदे के मुताबिक़ तो 76 प्रतिशत किसानों को ऋण मुक्त किया जाना था, लेकिन 76 प्रतिशत तो ऋण माफी से वंचित ही रह गए. 80 प्रतिशत किसान आत्महत्या को मजबूर हैं. कृषकहितों की बात करने वाले राजनेता काश किसानों के दर्द को समझ पाते.

feedback@chauthidunya.com

कृषि प्रधान देश भारत में आज़ादी के बाद से अब तक जिस तरह राजनेताओं व सरकारों द्वारा किसानों का शोषण हुआ, शायद ही विश्व में कहीं हुआ हो. अन्नदाता की संज्ञा से विभूषित किसान शोषण की पराकाष्ठा को छूते-छूते अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहें हैं. ऐसे में क़र्ज़ और किसान की दशा और दिशा का सिंहावलोकन किया जाना स्वाभाविक ही आवश्यक है.

चाचा की जन्मस्थली कहां है

मीरगंज की मद्रासी गली में जैसे ही आप जाएंगे आपके पैर ठिठक से जाएंगे, जब आपको मालूम चलेगा कि यहां कोई और नहीं चाचा नेहरू का जन्म हुआ था. यकीन ही नहीं होता यह वही गली है, जहां पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे शख्स का जन्म हुआ था. बुजुर्ग यह बताकर चुप हो जाते हैं कि यहीं कहीं पंडित नेहरू जन्मे थे.

देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और चाचा के नाम से मशहूर पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्मस्थली ही ग़ायब हो गई है. जीहां, यह बात अलग है कि यह करनामा अभी सिर्फ़ काग़ज़ों में ही हुआ है. मकान नंबर 77, मीरगंज, इलाहाबाद. यह कोई मामूली पता नहीं. 121 बरस पहले इस मकान में शिशु जवाहरलाल की किलकारी गूंजी थी, जो आगे चलकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने. पुराने अभिलेखों एवं इलाहाबाद संग्रहालय में दर्ज पुराने शहर का यह मकान अब इमारतों की भीड़ में गुम हो चुका है. नगर निगम के दस्तावेज़ों में न इसका नंबर मौजूद है और न ही नक्शा. मीरगंज की मद्रासी गली में जैसे ही आप जाएंगे आपके पैर ठिठक से जाएंगे, जब आपको मालूम चलेगा कि यहां कोई और नहीं चाचा नेहरू का जन्म हुआ था. यकीन ही नहीं होता यह वही गली है, जहां पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे शख़्स का जन्म हुआ था. बुजुर्ग यह बताकर चुप हो जाते हैं कि यहीं कहीं पंडित नेहरू जन्मे थे. बुजुर्ग स्वामी सरन बताते हैं कि नेहरू जी ने यहीं जन्म लिया था, ऐसा वह सुनते आए हैं. इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक डॉ. एस.के. शर्मा ने बताया कि आनंद भवन और संग्रहालय में पंडित नेहरू के जन्म वाले घर का मॉडल सुरक्षित है. इतिहासकार रामकृष्ण शर्मा बताते हैं कि 1900 में मोतीलाल नेहरू ने करनल गंज स्थित महमूद मंजिल ख़रीद ली, जिसका नामकरण बाद में आनंद भवन हुआ. 15 बरस की उम्र में शिक्षा के लिए विदेश जाने से पहले तक शिशु जवाहर लाल के 10–12 शुरुआती साल मीरगंज वाले मकान में ही गुज़रे थे. पर वक्त के साथ आनंद भवन राजनीति का तीर्थ बन गया, जबकि मीरगंज का मकान नंबर 77 इमारतों केबीच कहीं गुम हो गया. अब इसे क्या कहेंगे. सरकारी लापरवाही या आजकल के लोगों में अपने देश के महान लोगों के प्रति बढ़ती उदासीनता. ख़ैर जो भी हो, इस घटना से इतना तो पता चलता है कि जब इतनी बड़ी हस्ती का यह हाल है तो आम आदमी का क्या होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunya.com

योजना और स्वास्थ्य दोनों से खिलवाड़

पृष्ठ 1 का शेष

सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा समय–समय पर जो समस्याएं/कमियां उठाई गई वो हैं: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का वेब साइट पर समय से अपलोड न किया जाना, मिर्जापुर, फतेहपुर एवं कांशीराम नगर के डाटा का अभी तक लंबित रहना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार स्मार्ट कार्ड सभी बी.पी.एल.परिवारों को निर्गत न किया जाना, कार्ड बनाने के पूर्व तथा कार्ड बनाने के दौरान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पर्याप्त प्रचार–प्रसार न किया जाना और इस वजह से लोगों में योजना की पूर्ण जानकारी न होना, कार्ड बनाने के समय ही इसे लाभार्थी को उपलब्ध न कराना, ऐसे व्यक्तियों का कार्ड बनाना जिसका नाम बी.पी.एल. सूची में नहीं है(जनपद भदोही में ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया है), नियत 04 माह की अवधि के बाद भी अधिक धनराशि लेकर कार्ड बनाना, लाभार्थी से नियत रु.30/–के स्थान पर अधिक धनराशि लिया जाना, कार्डधारकों को ओ.पी.डी. की सुविधा उपलब्ध न कराना, बी.पी.एल. परिवार के साथ अस्पतालों में जाने के बाद कार्ड का काम न करना, कार्ड पर सभी पांच सदस्यों का नाम न होना, अस्पतालों की सूची तथा फोन नं. बीमा कंपनी द्वारा न दिया जाना, अस्पताल के अंदर भर्ती होने के दौरान भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा गुमराह किया जाना, कंपनी द्वारा समय से प्रीमियम का भुगतान न होना, बी.पी.एल. परिवारों का कार्ड बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर पर न आना, सेंटर पर बिजली आदि की सुविधा न होना, सरकारी अस्पतालों द्वारा योजना के प्रति पर्याप्त रूचि न दिखाना, जनपद स्तर पर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा चिकित्सालयों में मरीजों को गुमराह करना, दावों के भुगतान में अनावश्यक रूप से 26 दिन से अधिक विलंब करना आदि मुख्य है.

feedback@chauthidunya.com

मंच पर आसीन माननीय अतिथिगण.

लोकार्पण करते मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई कुरैशी.

दीप प्रज्वलित करते हुए संतोष भारतीय.